He Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 31]

नई विल्ली, शनिवार, अगस्त 3, 1974/ श्रावर्ण 12, 1896

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 3, 1974/SRAVANA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों भौर (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये सांविधिक भावेश और स्रधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मल्लिमण्डल सचिवालय

(वार्मिक ग्रीर प्रशासनिक सुधार विभाग) नई विरुत्ती, 2.2 जुलाई, 1974

का॰ बा॰ 1907.—दिल्ली त्रिशेय पुलिस स्थापना धिधिनियस, 1946 (1946 का 25) की धारा उके द्वारा प्रदत्त प्राक्तिया का प्रयोग करते हुये, बेन्द्रीय सरकार, एनद्द्वारा, निम्नलिखिन प्रपराध तथा प्रपराध श्रेणियो को ऐसे प्रपरार्ध निर्धारित करती है, जिनका प्रत्येषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारी किया जाना है, नामत—

- (क) भारत रक्षा श्रधितियम, 1971 (1971 का 42) तथा भारत रक्षा नियम, 1971 के श्रक्षीन वण्डतीय ग्रपराध।
- (बा) खण्ड (क) मे उस्लिखित एक या एक से प्रक्षिक प्रपराधा के सम्ब्रन्ध मे या उससे सबधित प्रयत्नो, उकसाहटो प्रौर पड-यन्त्रो तथा वैसे ही तथ्यो से उत्पन्न हुई वैसी ही कार्रवाई के दौरान किया गया श्रन्य कोई अपराध।

[शक्या 229/15/74-ए० वी० डी०-2]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & A.R.)

New Delhi the 22nd July, 1974

S.O. 1907.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences and classes of offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Fstablishment, namely—

- (a) Offences punishable under the Defence of India Act 1971 (42 of 1971) and the Defence of India Rules, 1971;
- (b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts

[No 228/15/74-AVL* II]

कार आर 1908.—-विस्ली विशेष पुलिस स्थापना श्राधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा उद्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करत हुये, केन्द्रीय सरकार, एसद्द्वारा, निम्नलिखित श्रापराओं को ऐसे प्राराण निर्धारित करती है, जिनका प्रत्वेषण विस्त्री विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना है, नामत .—-

- (क) परमाणु ऊर्जी प्रधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रधीन वण्डनीय अंगराध।
- (सा) खंड (क) में द्रिल्पिकान किसी अपराध के सम्बन्ध में या उससे संबंधित प्रयत्नों, उकसाहटों ग्रीर पडयन्त्रों तथा वैमें ही तथ्यों से उत्पन्न हुई मैसी ही कार्रवाई के दौरान किया गया अन्य कोई प्रपराध।

[मंग्रया 228/21/74-ए० बी० डी०-2] बी० मी० वतजानी, ग्रवर मनिव

S.O. 1908.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:

- (a) Offences punishable under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);
- (b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, any offence mentioned in clause (a) and any other offence committed in course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/21/74/AVD 11] B. C. VANJANI, Under Secy.

भारत निर्वाचन ध्रायोग

भावेश

नई विल्ली, 28 मई, 1974

भार आरं 1909—यन:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया हैं कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन के लिए 93-कोटा निर्वाचन- कें ले चुनाव लड़ने वाले उम्मीवधार श्री मंगल प्रमाद, ग्राम देवरगांव, थो० पेन्ड्रा रोड, तहसील एवं जिला बिलासपुर (म०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व श्रीधिनियम, 1951 तथा तब्धीन बनाए गए नियमों द्वारा श्रोधित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में अमफल रहे हैं;

श्रीर, यत', उनत उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना विशे जाने पर भी, श्रपनी इस श्रमफलना के लिए कोई कारण श्रथवा स्पष्टीकरण नहीं विश्वा है, श्रीर निविचन श्रोयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पाम इस श्रमफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोजिस्य मही है;

इतः प्रवं, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-कं के धन्मरण में निर्वा-चन आयोग एनद्द्वारा उक्त श्री मगल प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा सथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस धादेश की तारीख से तीन वर्ष की काला-विधा के लिए निर्माहत घोषिस करना है।

[सं० क० प्र०-वि० स०/93/72/(১১)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1974

S.O. 1909.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mangal Prasad, Village Deorgaon, Post Pendid Road, Tahsil Bilaspur, Bilaspur District who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 93-Kota constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mangal Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/93/72(38)]

श्रादेश

नई किल्मी, 29 मई, 1974

कां आ 1910 — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए में प्रेंग प्रेंग विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 105-मक्ती निर्वाचन केन्न से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हीरालाल प्रार्जुन, प्राम व पाँ अकलसरा, नहसील सक्ती, जिला बिलासपुर (में प्रेंग), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियस, 1951 तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपे-क्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

भीर, यतः, उक्त उम्मीववार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, भ्रापनी इस भ्रमफलना के लिए कोई कारण भ्रयबा स्पष्टीकरण नहीं विया है भीर, निर्वाचन भ्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस भ्रमफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोजित्य नहीं है;

श्रतः श्रवः, उक्त श्रधिनियमः, की धारा 10-क के श्रनुसरण में निर्वाचन श्रायोग एनद्वारा उक्त श्री हीरालाल श्रर्शुन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा श्रयंका विधान परिवद् के सदस्य जुने जाने श्रीर होने के लिए इस श्रावेश की तारीख से सीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्राहन शोषित करता है।

[सं॰म॰प्र॰-विवस॰/105/72(39)]

ORDER

New Delhi, the 29th May, 1974

S.O. 1910.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Heeralal Arjun, Village and Post Akalsara, Tahsil Sakti, District Bilaspur who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 105-Sakti constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder:

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Flection Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Heeralal Arjun to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/105/72(39)]

সাবৈগ

दिनाक 11 जून, 1974

का. भ्रा. 1911.—यन, निर्वाचन ध्रायोग का समाधान हो गया है कि सार्च, 1972 में हुये राजस्थान विधान सभा के लिये माधारण निर्वाचन के लिये 49-बैराठ निर्वाचन केन्न से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमेश चन्दर सुपुत्र श्री गोठराम मीना, शक्ति चिकित्सा मन्दिर, चान्द-पोल, बाजार, जिया लाल मुन्यी का राम्ता, जयपुर सिटी (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमी द्वारा प्रपेक्षित प्रपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में भ्रमफल रहे है;

ग्रीर, यतः,, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, ग्रपनी इस श्रमफलता के लिये कोई कारण श्रथवा स्पष्टीकरण नहीं विया है, ग्रीर, निर्वाचन ग्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस ग्रमफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या त्यायौजित्य नहीं है;

ग्रतः ग्रज्ञ, उक्त प्रधितियम की धारा 10-क के श्रतुमरण में निर्वाचन श्रायोग एतद्वारा उक्त श्री रमेश चन्त्र को समद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा श्रथमा विधान परिषद के सदस्य चुने जान और हाने के लिये इस ग्रादेण की नारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिये निर्राहन थोबिन करना है।

[स॰ राज॰ वि॰ म॰ / 49 / 72 (32)]

New Delhi, 11th June, 1974

ORDER

- S.O. 1911.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramesh Chander, S/o Shri Goru Ram Mina, Shakti Chiktsa Kendir Chandpole Bazar, Jia Lal Munsi Ka Rasta, Jaipur City, Rajasthan a contesting candidate for General Election held in March, 1972 to the Rajasthan Legislative Assembly from 49-Bairath Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;
- 2. And whereas, the said candidate even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;
- 3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramesh Chand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. RJ-LA/49/72 (32)]

का. ग्रा. 1912.— यत, निर्वाचन भ्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये हरियाणा विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये 76-फनेहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रनन सिह, प्राम व पो० ग्रा० फनेहाबाद, जिला हिसार हरियाणा, लोक प्रनिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमा द्वारा भ्रपेक्षित भ्रपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में ममफल रहे हैं;

ग्रीर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिवे जाने पर भी, भ्रपनी इस भ्रमफलना के लिये कोई कारण भ्रववा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, श्रीर निर्वाचन भ्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस भ्रमफलना के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

ग्रत ग्रम, उक्त भ्रोधिनियम की धारा 10-क के भ्रमुमरण में निविचन आयोग एनद्द्वारा उक्त श्री रतन सिंह की समद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा भ्रयवा विधान परिषद के सदस्य कुने जाने भ्रीर होते के लिये इस भ्रादेश की नारीख से तीन वर्ष की कालाबाध के लिये निर्माहत घोषित करनाहै।

[म० हरि०-वि० मं० 76/72(15)]

- S.O. 1912.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rattan Singh, S/o Shri Shingara Singh, Village and Post Office Fatehabad District Hissar, Haryana a contesting candidate for General Elections to the Haryana Legislative Assembly held in March, 1972 from 76-Fatehabad constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;
- 2. And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rattan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-1 A/76/72 (15)]

त्र्यावेश

नई विल्ली, 13 जून, 1974

का. बा. 1913——यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि सार्च, 1972 में हुए बिहार विशास सना के लिए निर्वासत के निए 274-व दन कि सरी (धिंग्जार) सभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाते उम्मोदबार श्री धनन्त लाल रजवार, प्राप्त धावती, पार खालार बेर्न्सा, भारा चापू, जिना धनवाद (बिहार), लाक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमा हारा प्रोक्षित प्रयो निर्वाचन घ्ययों का काई भी लेखा दाखिल करने में प्रमुक्तर रहे है,

धौर, यत, जनत जम्मीदवार ने, जसे सम्यक भूवना विये जाने पर भी, भ्रापनी इस ग्रासकता के लिए कोई कारण भ्रापना स्पष्टीकरण नहीं दिया है, भौर निर्वाचन ग्रायोग का यह भी समाधान हा गया है कि जसके पास इस ग्रासकलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

ग्रातः ग्राब, उक्ष्म श्रिवित्यम, की धारा 10-क के ग्रानुसरण में निर्वाचन ग्रायोग एत्राद्वारा उक्त श्री ग्रानन्त लाल रजवार का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा ग्रायका विधान परि-पद के सदस्य चुन जा ग्रीर होने के निए इस ग्रादेण की नारील से नीन वर्ष की कानाकों के निए निर्माटन ग्रांचिन करना है।

|म० बिहार-वि०स०/274/72(52)]

ORDER

New Delhi, the 13th June, 1974

S.O. 1913.—Whereas the Election Commission is satisfied that Anant Lal Rajbar, Village Dhobni, P.O. Khamarbendi, District Dhanbad (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 274 Chandankiary (SC) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the die notice has not given any reason or explanation for the failure and the Flection Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the sald Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anant Lal Rajbar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/274/72(52)]

का. ग्रा. 1914.—यन., निर्वाचन श्रायाम का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये बिहार विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये 276-बाघसारा सभा निर्वाचन के बेह्न से बुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ग्रार० पी० राय, स्वार्टर न० 619-3ए, बोबारो स्टील सिटी, जिला धनबाद (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व ग्रिधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाये गये नियमा द्वारा श्रीक्षेत्र श्रपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में श्रमफल रहे है.

श्रीर यतः, उक्त उम्मीदवार, ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, श्रपनी इस श्रमफलता के लिये कोई कारण श्रथवा स्पर्प्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन श्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके पास इस श्रमफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्य नहीं है;

श्रतः श्रव, उक्त श्रिशित्यम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन श्रायोग एसद्वारा उक्त श्री श्रार० बी० राय का समद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा श्रथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के सिये क्रम श्रावेश की नारीय से सान वर्ष की कालाविध के लिये निर्यादन घोषिन करना है।

[स॰ बिहार वि॰ स॰/276/72(50)]

S.O. 1914.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri R. P Roy, Quarter No. 619-IIIA Bokaro Steel City, District Dhanbad (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 276-Baghmara constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due rotice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri R. P. Roy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/276/72 (50)]

का. प्रा. 1915 — यत निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 276 बाप- मारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने बाले उम्मीदबार श्री रामता प्रसाद सिंह, ग्राम बिणुनपुर, पोठ जलपुरा, जिला घारा, शाहाबाद (बिहार), लाक प्रतिनिधिन्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीम बनाए गए निसमा द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यया का काई भी लेखा दाखिल करने में प्रसफल रहे हैं,

श्रीर यत , उकत उम्मीयबार ने, उसे सम्यक सृजना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, श्रीर निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकिस्य नहीं है;

अत अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुगरण में निर्वाचन आयोग एत्रवारा उक्त श्री रामना प्रसाद सिंह को समक्ष के किसी भी सदन के किसी राज्य की विवान सभा प्रयवा विधान परिषद के सदस्थ चुने जाने और दानों के लिये इस आदेश की तारीख़ में नीत अर्प की काला-विधा के लिये निर्माहन धोषिर करना है।

[सं० बिहार वि० स०/276/72(51)]

S.O. 1915.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramta Parsad Singh, Village Bishunpura, P. O. Jalpura, District Arrah, Shahbad (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 276 Baghmara constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason of justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramta Parsad Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/276/72(51)]

मादेश

नई दिल्ली 15 जूर, 1974

का द्वा. 1916 — यतः, निर्वाचन ग्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुये हरियाणा विद्यान सभा के लिये निर्वाचन के लिये 42 वेशी सभा निर्वाचन केने में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भगवाना, ग्राम वाधाुर पो० वेशी, जिला रोहनक (हरियाणा), लोक प्रतिनिधित्व भाधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा भ्रयेक्षित प्रपत्ने निर्वाचन ज्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करन में भ्रमफण रहे हैं।

श्रीर, यत; उक्त उस्मीदवार, ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, श्रमनी इस श्रमफलना के लिये काई करण श्रथवा स्वव्दीकरण बही दिया है, और निर्वाचन श्रायाम का यह भी समाधान हो गया है कि उस के पास इस श्रमफलना के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं श्रन, श्रम, उक्त ब्रधिनियम की धारा 10 क के बनुसरण में निर्वाचन श्रायोग एतद्वारा उक्त श्री भगवाना को संसद के किसी भी सर्वन के या किसी राज्य की विश्वान सभा श्रथमा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस ब्रादेश की नारीख से तीम वर्ष की काला-विध के लिये निर्राहत बोषित करना है।

[स० हार० जि० स०/42/72(16)]

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1916.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagwana, Village Baghpur, Post Office Beri, District Rohtak, (Haryana) a contesting candidate for General Elections to the Haryana Legislative Assembly held in March, 1972 from 42-Beri constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act 1951 and the Rules made thereunder;

2. And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagwana to be disqualified for being chosen, as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/42/72 (16)]

का० प्रां० 1917.----पतः, निर्वाचन भाषोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 254-इन्दौर IV निर्वाचन केल में कृमान लड़ने नाले उम्मीदवार श्री पोषट लाल बछाराम 1/3 छोटी खाल टोली, पुरोहित लॉज, इन्दौर, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनिथम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा भ्रपेक्षित अपने निर्वाचन क्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में प्रमफल रहे हैं;

भीर, यतः, उक्त उम्मीदशार भे, उसे सस्यक सूचना दिये जाने पर भी, धपनी इस भ्रमफलमा के लिए काई कारण भवना स्पब्टीकरण नहीं दिया है भीर, निर्माचन श्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके पास इस ग्रमफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौजित्य नहीं है;

चन प्रव, उक्त प्रधिनियम, की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वा-क्त आयोग एनद्द्वारा उक्त श्री पोपट क्छाराम को संयद के किसी भी सबन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विद्यान परिषद् के सदस्य कृत जाने और होने के लिए इस घादेश की मारीख से तीन वर्ष की कालाबधि के लिए निर्रोहन घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-रि०स०/254/72/(40)]

S.O. 1917.—Whereas the Election Commission is, satisfied that Popatlal Bachharam, 1/3, Chhoti Gwal, Toli, Purohit Lodge, Indore (Madhya Pradesh) who was a contesting candidate for election to the Madhya Pradesh legislative Assembly from 254-Indore IV constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act. 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and

the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Popatlal Bachharam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No, MP-L $\Lambda/254/72(40)$]

भादेश

मई दिल्ली, 1 भूलाई, 1971

कां बां 1918.— यत., निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि सार्च, 1971 में हुये उड़ीमा विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये 43 बन्की सभा निर्वाचन केल से चुनाव लड़तेव वाले उम्मीदवार श्री कुपासिन्धु बेहेरा, प्राम तथा पोस्ट तालाबस्ता, जिला कटक लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाये गये नियमां द्वारा प्रपेक्षित प्रपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में धमकन रह है;

ग्रीर यतः, जन्म उम्मीदवार ने, जसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, ग्रपनी इस भ्रमफलना के लिये कोई कारण भ्रयता स्पटीकरण नहीं दिया है, श्रीर निर्वाचन श्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस भ्रमफलना के लिये कोई पर्याप्त कारणया न्यायीवित्य नहीं है,

श्रन, श्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 10 के के श्रनुमरण में निर्वावन श्रायान एनक्दारा उक्त श्री कृपामिन्धु बेहेरा को समद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा श्रथवा विधान परिषद के सदस्य खुने जाने श्रीर होने के लिये इस श्रावेश की नारीक्ष में तीन वर्ष की कालाविश्व के लिये निर्माहन धोषिन करता है।

[सं० उद्दीसा-वि० म०/43/71]

ORDER

New Delhi, the 1st July, 1974

S.O. 1918.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Krupasindhu Behera, Village and P.O. Talabasta, District Cuttack, a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from, 43-Banki constituency, held in March. 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Krupasindhu Behera to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/43/71]

भादेण

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1974

कार्रकार 1919. — यत , निर्धाचन घायोग का समाधान हो गया है कि भार्च, 1972 मेंहुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 4-शिकापुर (अनुरुजार) निर्वाचन-केन्ने में चुनाव लड़ने वॉल उम्मीदयार श्री धर्मदेव प्रसाद, ग्राम-पार चनपटिया, चम्पारण बिहार) लाक प्रतिनिधित्व श्रिधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित श्रपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में ग्रमफल रहे है;

श्रीर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना विये जान पर भी, अपनी इस असफलना के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीचित्र्य नहीं है;

भ्रत, श्रव, उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के श्रनुसरण में निर्वा-चन भ्रायोग एतक्द्वारा उक्त श्री धर्मदेव प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा श्रथवा विधान परिषद् के सबस्य चुने जाने भ्रीर होने के लिए इस श्रादेण की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरहित धाषित करना है।

म्रादेश से.

[स० बिहार-वि०स०14/72(57)]

ORDER

New Delhi, the 12th July, 1974

S.O. 1919.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dharandeo Prasad, Village & P.O. Chanpatia, Champaran (Bihar) who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 4-Shikarpur (SC) constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dharamdeo Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-1 A/4/72(57)]

मावेश

नई विल्ली 15 जुलाई, 1971

कां श्रां 1920.—यत , निर्वाचन ग्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्धाचन के लिए 17-मधुबन निर्वाचन के से खुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लकुर गिरिजा नन्दन मिह, ग्राम मधुबन, पो० गुलबारा, चम्पारण लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो हारा ग्रपेक्षित ग्रपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में ग्रमफल रहे हैं;

और यत , उकत उम्मीदवार ने, उसे सस्यक सूचना दिय जाने पर भी, भ्रपनी इस भ्रमफलना के लिये कोई कारण भ्रथवा स्पटीकरण नहीं दिया है, भीर, निर्वाचन भ्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस भ्रमफलना के लिए कोई पर्याप्त कारणया न्यानीचित्र्य नहीं है,

ग्रन श्रम, उक्त प्रधिनियम, ती धारा 10-क के ग्रन्सरण में निर्वा-चन आयाग एनवृद्धारा उक्त श्री ठाकुर गिरिजा नन्दन सिष्ठ की समय के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा ग्रथवा विधान परिषय के सबस्य चुने जाने भीर होने के लिए इस घारेश की नारीख स तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्माहन घोषित करना है।

[सं० बिहार-वि०स०/17/72(58)]

ORDER

New Delhi, the 15th July, 1974

S.O. 1920.—Whereas Election Commission is satisfied that Shri Thakur Girja Nandan Singh, Village Madhuban, P.O. Gulwara, Champaran who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly 17-Madhuban constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Thakur Girja Nandan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House or Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/17/72(58)]

श्रावेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1974

का० ग्रा० 1921.—यतः, निर्वाचन भायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37-माझी निर्वाचन -अंत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीद्यार श्री विरन्ध सिह, ग्राम व पो० दुमरी, जिला सरन लाक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा सद्धीन बनाए गए नियमो हारा ग्रवेक्षित रीति पे ग्रापन निवचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में ग्रसकृत रहे है,

श्रीर, प्रतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अध्यावेदम पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन श्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस श्रासफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौजित्य नहीं है;

ग्रतः श्रव, उक्त श्रधिनियम, की धारा 10-क के श्रनुसरण में निर्वाचन श्रायोग एतद्कारा उक्त श्री विरोन्द्र सिंह को ससद के किसी भी सदत के या किसी राज्य की विधान-सभा श्रथवा विधान परिषद् के सबस्य चुने जाने श्रीर होने के लिए इस श्रावेश की नारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निर्हित घोषित करना है।

[सं० बिहार-वि० स०/37/72 (59)]

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1974

S.O. 1921.—Whereas the Election Commisson is satisfied that Shri Virendra Singh, Village & P.O. Dumri, District Saran who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 37-Manjhi constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election

expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Flection Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Flection Commission hereby declares the said Shri Virendra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/37/72(59)]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1974

का॰ शा॰ 1922.—लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1930 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदेन गिम्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्वाचन श्रायोग, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र की सरकार से परामर्श से श्री टी॰ टी॰ जोसेफ के स्थान पर, उस संघ राज्य क्षेत्र के कलक्टर एवं विकास प्रायुक्त श्री सी॰ रामऊ, ग्राई॰ ए॰ एम॰ को तारीखा 10 जुलाई, 1974 (पूर्वाक्ष) से ग्रमले ग्रादेशों तक लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के नियं मुख्य निर्वाचन ग्राफिसर के रूप से एनद्द्वारा नाम-निर्वेशित करता है।

[म॰ 154/लक्ष/74] ए॰ एन॰ मैन, मचिव

New Delhi, the 18th July, 1974

S.O. 1922.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Administration of the Union Territory of Lakshadweep, hereby nominates Shri C. Ramou, I.A.S., Collector-cum-Development Commissioner of the Union Territory, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory with effect from the forenoon of the 10th July. 1974 and until further orders vice Shri T. T. Joseph.

[No. 154/IMA/74]A. N. SEN, Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Accounts and Expenditure) Bombay, the 21st June, 1974

CORRIGENDUM

S.O. 1923.—In the statement of Affairs of the Reserve Bank of India, Issue Department for the week ended 21st December, 1973, published in Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India dated 26th January, 1974, the following corrigendum may be noted on page 238, the figures 57,29,64,37,000 shown under the head Assets may be read under Column 3 as total liabilities 57,29,64,37,000

[Ref Gen. No. 734/4-73/74]
(Sd.) Illegible,
Chief Accountant,

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 13 जून, 1974

भ्राय-कर

काल्या 1924.—केन्द्रीय सरकार प्राय कर प्रधिनियम, 1961 (1861 का 43) की धारा 2 के खड़ (44) के उपखड़ (III) द्वारा प्रदल्त प्राप्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस० एस० प्रसाद जो केन्द्रीय सरकार के राजपितन प्रधिकारी है, उक्त प्रधिनियम के अधीन कर वसूली प्रधिकारी की प्रक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करनी है।

- 2. म्राधिमूचना स० 58 (ए० स० 40 4/52/71 म्राई० टी० सी० मी०) तारीख 22 फरवरी, 1471 के भ्राधीन की गई कर बसूली म्राधिकारी के रूप में श्री सीताराम शरण की नियुक्ति उस नारीख से रह की जाती है जिस तारीख को श्री एस० एस० प्रसाद कार्यभार ग्रहण करने है।
 - 3. यह सूचना 15 जून, 1974 से प्रवृत होंगी।

[स॰ 644 (एफ॰ स॰ 104/16/74-म्राई॰ टी॰ सी॰ सी॰]

New Delhi, the 13th June, 1974 INCOME TAX

- S.O. 1924—In exercise of the powers conferred by subclause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises Shri S. N. Prasad, who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. The appointment of Shri Sitaiam Shaian as Tax Recovery Officer made under Notification No. 58 (F. No. 404/52/71-ITCC) dated 22nd February, 1971 is hereby cancelled with effect from the date Shri S. N. Prasad takes over.
- 3. This notification shall come into force with effect from 15th June, 1974.

[No 644 (F No 404/16/74-ITCC)]

नई विल्ली, 20 जून, 1974

श्रायकर

शांकार 1925. -- केन्द्रीय संरकार भायकर श्रिष्ठित्यम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खड़ (44) के उपखंड (III) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री ए० श्रीक्षर मेनन ग्रीर के० के० मुकुमारन जो केन्द्रीय सरकार के राजपितत श्रिकारी है को उक्त श्रिधित्यम के ग्रिक्षीत कर-वसूली श्रिष्ठकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करनी है।

- 2. श्रिष्टिम्बना स० 177 (फा० स० 404/245/72-श्राई टीसीसी) नारीख 8 सिनम्बर, 1972 के श्रिशीन श्री ए०ए० रयान की श्रीर श्रिष्ठिम्बना स० 381 (फा० स० 404/76/73--श्राईटीसीसी) नारीख 15 जून, 1973 के श्रिशीन श्री बी० रिव बालन की की गयी नियुक्तिया 20 जून, 1973 से रह की जानी हैं।
 - यह ग्रिधिसूचना 20 जुन, 1974 से प्रवृत्त होगी।

[स० 650 (फा० स० 404/140/74 श्राईटीसीसी]

New Delhi, the 20th June, 1974

INCOME TAX

- S.O. 1925.—In exercise of the powers conferred by subclause (ni) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises S/Shri A. Sreedhara Menon and K. K. Sukumaran who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.
- 2. The appointments of Shrl A. A. Byan made under Notification No. 177 (F. No. 404/245/72-ITCC) dated 8th September, 1972 and Shri B. Ravibalan under Notification No. 381 (F. No. 404/176/73-ITCC) dated 15th June, 1973 are cancelled with effect from 20th June, 1974.
- 3. This Notification shall come into force with effect from 20th June, 1974.

[No. 650 (F. No. 404/180/74-ITCC)]

नई दिल्ली, 21 जून, 1974

काठ आठ 1926.— केन्द्रीय सरकार, ध्रायकर, ध्राधिनयम, 1961 (1961 का नड) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (III) द्वारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करने हुए सर्वश्री बीठ डीठ बतुर्वेदी, एस० एस० शर्मा, एस० पीठ सिंह धीर पीठ एन० सांगी को जो केन्द्रीय सरकार के राजपश्चिम ध्रिधिकारी है, उक्त श्रिधिनयम के ध्रधीन कर वसूली, ध्रिधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. प्रशिम्चना मं० 278 (फा० स० 404/131/71-प्राई टी सीसी) तारीख 18 सितम्बर, 1971 के प्रधीन श्री टी॰ डी॰ चान्दना की, प्रधिम्चना म॰ 218 (फा॰ मं॰ 404/13/71-प्राई टी सी सी) तारीख 14 जुलाई, 1971 के श्रधीन की गई श्री एस॰ एस॰ सबसेना की, प्रधिम्चना मं० 172 (फा॰ स॰ 404/13/71 प्राईटीसीसी) सारीख 7 जून, 1971 के श्रधीन की गई श्री रोगन लाम की श्रीर श्रधिस्चना म॰ 22 (फा॰ मं॰ 404/131/71 श्राई टी सी सी) तारीख 14 जुलाई, 1971 के श्रधीन की गयी श्री एस॰ एन॰ चतुर्वेदी की नियुक्तिया पहली जुलाई, 1974 से रह की जानी है।

3---यह श्रधिसूचना पहली जुलाई, 1974 से प्रवृक्त हैं।गी।

[स॰ 652 (फा॰ म॰ 404/110/74---माईटीसीसी)]

New Delhi, the 21st June, 1974

- S.O. 1926.—In exercise of the powers conferred by subclause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authrises S/Shri B. D. Chaturvedi, S. S. Sharma, S. P. Singh and P. N. Mago, who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.
- 2. The appointments of S/Shri T. D. Chandna, made under Notification No. 278 (F. No. 404/131/71-ITCC) dated 18th September, 1971, Shri S. S. Saxena made under Notification No. 218 (F. No. 404/131/71-ITCC) dated 14th July, 1971, Shri Roshan Lal made under Notification No. 172 (F. No. 404/131/71-ITCC) dated 7th June, 1971 and Shri S. N Chaturvedi made under Notification No. 220 (F. No. 404/131/71-ITCC) dated 14th July, 1971 are cancelled with effect from 1st July, 1974.
- 3. This notification shall come into force with effect from 1st July, 1974.

[No. 652 (F. No. 404/110/74-ITCC)]

नई विल्ली, 26 जन, 1974

कारुझां 1927.—-श्रिधिनियम 1961 (1961 का 13) की धारा 2 के खंड (44) के उपचंड (III) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करने हुए, के द्वीय सरकार श्री भी के सीक हजारिका की, जो केन्द्रीय सरकार के राजपित्रन के धिषारी है, उक्त प्रक्षिनियम के अवीन कर बसुली अधिकारी की गिलियों का प्रयोग करने के लिये प्रक्षिकृत करती है।

> [मं० 659 (फा० स० 404/193/74 माई टी सी मी)] टी॰ मार० भग्रवाल, उप मचिव

New Delhi, the 26th June, 1974

- S.O. 1927.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises Shri B. C. Hazarika who is a gazetted officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. The appointment of Shri R. K. Dutta made under notification No. 16 (F. No. 404/22/71-ITCC) dated 1st February, 1971 is cancelled with effect from the date Shri B. C. Hazarika takes over from him.
- 3. This notification shall come into force with effect from the date Shri B. C. Hazarika takes over.

[No. 659 (F. No. 404/193/74-ITCC)] T. R. AGGARWAL, Dy. Secy.

सीमा-शुल्क नई दिली, 3 अगस्त, 1974.

का. आ. 1928.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का (2) की धारा 6 इवारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विस्त मंत्रालय (राजस्व' और बीमा विभाग) की अधिसूचना स. 163-सीमा शुल्क तारीख 20 विसम्बर, 1969 को अधिकांत करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को, जहां कहीं भी वे तैनात हों, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविधिट में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क अधिकारियों के कृत्य सौंपती हैं और निदंश देती हों कि एसा प्रत्येक अधिकारी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सीमा-शुल्क अधिकारी के कृत्यों का प्रयोग करोगा।

	सारणी						
ऋम सं०	अधिकारियो का पदाभिदान	सीमा-शुल्क श्रीविनियक, 1962 के उपबन्धों के श्रधीन इत्य					
1	2	3					
1	सभी कमाण्डेट, उप कमाण्डेट श्रीर सहायक कमाण्डेट	 (1) घारा 100 से 104 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) 106, 107, 109 और 110 के अधीन कृत्य और 					

(2) धारा 105 स्त्रीर 108 के घ्रधीन एसे स्थानो पर क्रन्य जहां सीमा-णुरूक और केन्द्रीय उष्पाद-णूरूक के अधीक्षक के या उससे ऊपर के रैक का कोई ध्रधिकारों सैनान नहीं है।

 सभी सूत्रेदारमेजर, सूत्रेदार फ्रीर उप निरोक्षक । धारा 100 से 104 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) 106, 107, 109 ग्रीर 110 के अधीन क्रत्य।

 सभी प्रधान कांस्टेब्ल और नायक । धारा 100, 102, 106 थ्रोर 110 के अधीन कृत्य ।

[मं 63/फा॰ स॰ 6/1/70-एस॰ मी॰ 2]

डी. सरूप, अवर सचिव.

CUSTOMS

New Delhi, the 3rd August, 1974

S.O. 1928.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. 163 customs dated the 20th December, 1969 the Central Government hereby entrusts to the officers of the Border Security Force mentioned in column 2 of the Table below, wherever posted, the functions of an officer of customs specified in the corresponding entry in column 3 of the said Table and directs that each such officer shall exercise the functions of an officer of customs within the local limits of his jurisdiction.

TABLE

S. No	Designation of officers	Functions under the pro- visions of the Customs Act, 1962
1	2	3
1.	All Commandants, Deputy Commandants and Assistants Commandants.	(1) Functions under sections 100 to 104 (both inclusive), 106, 107, 109 and 110 and
		(2) functions under sections 105 and 108 in places where no officer of cus- toms of the rank of Superintendent of Cus- toms and Central Excise or above is stationed.
2.	All Subedar Majors, Subedars and Sub- Inspectors.	Functions under sections 100 to 104 (both inclusive), 106, 107, 109 and 110.
3.	All Head Constables and Naiks.	Functions under sections 100, 102, 106 and 110.

[No. 63. F. No/6/1/70-LCII] D. SARUP, Under Secy. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

मादेश

संपदा गुस्क

नई दिल्ली, 28 जून, 1974

का॰ प्रांव 1929.—संपदा णुल्क प्रधिनियम, 1953 (1953 का प्रधिनियम 34) की धारा 1 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुवे केन्द्रीय मरकार, नीचे की मारणी के स्तस्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेजों के महायक ग्राय कर प्रायुक्तों को संपदा शुल्क नियंत्रक, ग्रंपील, के रूप में नियुक्त करती है जिनके मुख्यालय नीचे की सारणी के स्तस्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट स्थानों पर हागे —

भारणी

क०सं∘	भहायक भ्रायकर भ्रायुक्त भ्रपील		संपदा शुरुक नियंत्रक, भ्रापील
1	2		 3
1. 看	ि रेज, पटना ।		पटना ।
2. T	ाची रेंज, रांची।		राची ।
3. Y	तमलपुर रेंज, भागत्रपुर ।	-	भागलपुर ।

यह द्वारोश 8 जुलाई, 1974 से प्रभावी होगा।

[सं० 52/1974/फा० सं० 301/125/73-ई० औ०]

वी० डी० झाखारकर, ग्रथर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDER

ESTATE DUTY

New Delhi, the 28th June, 1974

S. O. 1929.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (Act XXXIV of 1953), the Central Government hereby appoint Assistant Commissioners of Income-Tax of the ranges specified in column 2 of the Table below as Appellate Controllers of Estate Duty with Head-Quarters at place as specified in column 3 of Table below:—

TABLE

-				
	S.No	o. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax.	Appellate of Estate	Controller Duty
	1.	2.		3.
	1,	B—Range, Patna		Patna
	2.	Randhi Range, Ranchi.		Ranchi.
	3, 1	Bhagalpur Range, Bhagalpu	r.	Bhagalpur

This order shall have effect from 8th July, 1974.

[No. 52/1974/F. No. 301/125/73-E.D.]

V. D. WAKHARKAR, Under Secy.

रिज**र्व बैंक श्रां**फ़ इंडिया

का॰ आ॰ 1930.—— रिजर्थ बैंक भ्रॉफ इंडिया भ्रधिनियम 1934 के भ्रनुसरण में जुलाई 1974 की 12 तारीख की समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा (इणू विभाग) नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1974

देयलाएं,	रूपये	रुपये	श् रास् तियां	रूपये	रुपप्रे
बै किंग विभाग में रखें हुए, नोट	43,06,40,000		सोने का सिक्का श्रौर बुलियन ' (क) भारत में रखा हथा	182,53,05,000	=
संचलन में नोट , ,	6477,76,07 000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ विदेशी प्रतिभृतिया	166 73 97,000	
जारी किये गये कुल नोट .		6520,82,17,000	সায়		349,27,02,000
			रुपये का सिक्का भारत सरकार की रुपया प्रतिभृतिया देणी विनिमय विल श्रोर दूसरे		8,44,15,000 6163,11,30,000
कुल देवसाएं .		6520,82,47,000	वाणिज्य-पन्न कुल म्रास्तिया		6520,82,47,000
भारील : २२ जनाई १०२४					प्रार० के० हजारी, जनगर् को र

नारिखाः १७ जुलाई 1974

उप गवर्नर

12 जुलाई, 1974 को रिज़र्व बैंक ग्रॉफ इंडिया के वैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं		रुपये	भ्रास्तिया	रुपये
चुकतापूर्ण		5,00,00,000	नोट	43,06,40,000
भ्रारक्षित निधि		150,00,00,000	रुपयेकासिक्का	4,45,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण			छोटा सिक्का	2,76,000
(बीर्घकालीन कियाए) निधि		284,00,00,000	खरीदे गय भुनाये गये बिल	
रोष्ट्रीय कृषि ऋण			(क) वेणी	262,68,92,000
(स्थिरीकरण) निधि		95,00,00,000	(ख) विवेशी	
राष्ट्रीय श्रीकोगिक ऋण			(ग) सरकारी स्वजाना बिल	160,73,37,000
(दीर्घकालीन क्रियाए) निधि		265,00,00,000	विदेशों में रखा हुन्ना बकाया*	548,80,01,000
जमाराशिया			निवेश ^क	339,65,40,000
(क) मरकारी			ऋण ग्रौर अग्रिम :	
े (i) केन्द्रीय सरकार .		50,09,78,000	(i) केन्द्रीय सरकार की .	
(ii) राज्य मरकारे .		22,96,18,000	(ii) राज्य सरकारों को‡ .	115,08,50,000
(ख) बैके			ऋण ग्रीर ग्रग्निम	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक		532,76,52,000	(i) श्रनुमूचित वाणिज्य बैंको को @	339,25,85,000
(ii) ग्रनुसूचित राज्य सहकारी अँक		21,45,25,000	(ii) राज्य सहकारी बैकों को $@@$	158, 49, 16, 000
() 311			(iii) दूसरोको	27,49,45,000
(iii) गैर ध्रनुसूचिम राज्य सहकारी बैंक		1,55,03,000	राष्ट्रीय कृषि ऋणे (दीर्घकालीन कियाए) निधि से ऋण	
2.1			ग्रग्रिम ग्रौर निर्वेष	
(iv) भ्रन्य वै क		1,01,84,000	(क) ऋणभ्रौरस्रग्रिम — -	
, ,			(i) राज्य सरकारों को	67,87,32,000
			(ii) राज्य सहकारी बैं कों को .	15,36,16,000
			(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंको को .	
			(iv) कृषि पुनीवस निगम को	64,00,00,000
(ग) म्रन्य		544,02,53,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरां मे निवेश	11,13,14,000
,			रोब्द्रीय कृषि ऋण (स्थिनीकरण) निधि से ऋण ग्रीर	
देय बिल		97,77,50,000	ग्रसिम	
			राज्य सहकारी वैंकों को ऋण श्रीर अग्रिम .	52,03,88,000
घन्य देयमाण्		462,55,61,000	राष्ट्रीय श्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	
·			से ऋण, ग्रग्रिम ग्रौर निवेश	
			(क) विकास बैक को ऋण भ्रौर प्रग्रिम	178,69,55,000
			(ख) विकास शैंक द्वारा जारी किये गये वांद्रो/डिवेंचरों	
			में निवेश	
			अन्य भ्रास्तियां	148,75,62,000
रुपये	+	2533,20,24,000	रुपयें .	2533,20,24,000

*नकदी, ब्रावधिक जमा श्रीर श्रस्पकालीन प्रतिभूतियाँ भामिल है ।

ध्यया।चल ६। @@दगप्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कियाए) निधि और राप्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रद≖ ऋण श्रीर भग्निम गामिल नही है।

> [र्सं o क o 10/1/74-वी o ग्रो o I] ग्राप् के o हजारी, उप गवर्नर

तारीखः 17 जुलाई, 1974

^{**}राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय श्रीद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि मे से किये गये निवेश शामिल नहीं है।

[्]रेगट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाए) निधि ने प्रदेश ऋण और अग्निम णामिल नहीं हैं, परंतु राज्य सरकारा को दिये गये अस्थायी स्रोवरङ्गाधट शामिल हैं।

[@] হিন্ত वं भैक आफ़ इंडिया श्रधिनियम की धारा 17(1)(ग) के श्रधीन श्रनुस्चित वाणिज्य बैंको को मीयादी बिलों पर श्रयिम दिये गये 142,85,73,000 हपये णामिल है।

RESERVE BANK OF INDIA

S.O 1933.—An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 12th day of July 1974.

(ISSUE DEPARTMENT)

New Delhi, the 20th July, 1974

			<u> </u>		
LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSE (>	Rs	Rs.
Notes held in the Banking Department Notes in circulation Total Notes issued	43,06,40,000 6477,76,07,000	6520,82 ,47,000	Gold Coin and Bullion: (a) Held in India (b) Held outside India Foreign Securities Total Rupee Coin Government of India Rupee Securities Internal Bills of Exchange and Other Commercial paper	182,53,05,000	349,27,02,000 8,44,15,000 6163,11,30,000
Total Liabilities		6520,82,47,000	-		6520,82,47,000
Total Edgentiss	 -			R.K. HAZARI,	

Dated the 17th day of July 1974.

Statment of the Affairs of the Reserve Bank of InJia, Banking Department as on the 12th July 1974

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes Rupec Coin	43,06,40,000 4,45,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin Bills Purchased and Discounted:—	2,76,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	(a) Internal (b) External (c) Government Treasury Bills	262,68,93,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Balances Held Abroad* Investment** Loans and Advances to:-	548,80,01,000 339,65,40,000
National Industrial Credit		(i) Central Government	
(Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(ii) State Governments ā: Loans and Advances to:	115,08,50,000
Deposits:-		(1) Scheduled Commercial Banks [†]	339,25,85,000
(a) Government		(ii) State Co-operative Banks‡	158,49,16,000
(i) Central Government	50,09,78,000	(iii) Others	27,49,45,000
(ii) State Governments	22,96,18,000	Loans, Advances and Investments from National	
(b) Banks (i) Scheduled Commercial Banks (ii) Scheduled State Co-operative Banks	532,76,52,000 21,45,25,000	Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund (a) Loans and Advances to:- (1) State Governments	67,87,32,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,55,03,000	(ii) State Co-operative Banks (iii) Central Land Mortgage Banks	15,36,46,000
(iv) Other Banks	1,01,84,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	64,00,00,000
<i>、,</i>		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,13,14,000
(c) Others Bills Payable	544,02,53,000 97,77,50,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
·		Loans and Advances to State Co-operative Banks	52,03,88,000
Other Liabilities	462,55,61,000	Loans Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	178,69,55,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	148,75,62,000
RUPEES	2533,20,24,000	RUPEES	2533,20,24,000

^{*} Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

^{**} Excluding Investments from the the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

^{*}Includes Rs. 142,85,73,000 advances to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

[‡]Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

कार आरं 1931.— रिशर्व बैंक प्रॉफ इंडिया प्रिवित्यम, 1931 के अनुसरण में जुलाई 1974 की 5 तारीख़ की समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा इस् विभाग नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1974

वेयसाए	नपय	रपर्य	<mark>प्रा</mark> स्तियां	मपये	रुपये
वैंकिंग विभाग में रखें हुए नोट	25,48,99,000		सोने का सिक्का श्रीर बुलियन :		
			(क) भारतमे रखा हुन्ना .	182,53,05,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुन्रा		
सचलन में नोट	6484,28,34,000		विदेशी प्रतिभृतियां .	166,73,97,000	
			A13 .		349,27,02,000
			रुपये का सिक्का		7,38,33,000
जारी किये गये कुल नोट		6509,77,33,000	भारत सरकार की रुपया प्रतिभतिया		6153,11,98,000
			वेणी विनिमस क्षिल श्रीर दूसरे याणिज्य-पत्न		• •
कुल देयताएँ	-	6509,77,33,000	— कृत प्रास्तियाँ .		6509,77,33,000

तारीख: 10 जुलाई, 1974

12 जुलाई, 1974 को रिजर्व बैंक ग्रांफ इंडियां के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाए का विवरण

वेयनाएं		रुपये	ग्रास्तियां	रुपये
वकता पूंजी		5,00,00,000	नोट , , ,	25,48,99,000
ष्प्रौरक्षित निधि .		150,00,00,000	कपर्येकासिक्का	5,33,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण			छोटा सिक्का	2,64,000
(दीर्धकालीन कियाए) निधि .		284,00,00,000	खरीदे भीर भुनाये गये बिल	•
राष्ट्रीय कृषि ऋण		,	(क) देणी	269, 11, 87, 000
(स्थिरीकरण) निधि		95,00,00,000	(ख) विदेशी	
राष्ट्रीय ग्रौद्योगिक ऋण		,,.	(ेग) सरकारी खजाना खिल	114,31,28,000
(दीर्घकालीन क्रियाए) निधि .		265,00,00,000	विदेशों मे ग्लाहबाबकाया*	548,92,04,000
(याजनातानानानानानानानानानानानानानानानानाना		200,00,00,00	नियेग**	349,58,88,000
जमारासयाः── (क) सरकारी			ऋण भ्रीर प्रग्रिम	010,00,00,00
(क) सर्पारा		89,51,47,000	(i) केन्द्रीय सरकार का	
3-1/	•	15,23,22,000	(ii) राज्य सरकारों को†	119,75,59,000
	•	13,23,22,000	्राप्त प्रति । पार्च प्रस्कार का । ऋण ग्रीर श्रीम :	1111, 13, 30, 00
(ख) वैक		500 05 05 0 00	ा अर्था अर्था — (i) श्रनुसूचित वाणिज्य वैकों को ‡ .	205 04 95 00
(i) भ्रनुसूचित वाणिज्य बैंक		508,87.87,000	(1) अनुसामन वार्णिय बन्ता कार्	395,64,85,00
(ii) ग्रनुँसूँचित राज्य सहकारी बैक		21,20,50,000	(ii) राज्ये सहकारी बैंको को @ .	160,59,90,000
			(iii) दूसरो को	26,64,70,00
(iii) गैर ग्रनुसूचित राज्य सहकारी बैक	•	1,51,18,000	राष्ट्रीय केषि ऋणे (वीर्षकालीन कियाएं) निधि से	
			ऋण , श्रम्भि धौर निवेश	
(iv) ग्रन्थ बैक		1,10 12,000	(क) ऋण भौर प्रग्रिम ≔—	
			(i) राज्य सरकारों की	67,87,34,00
			(ii) राज्य सहकारी वै कों को	15, 19, 37, 000
			(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैको का	
			(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम की .	64,00,00,00
(ग) भ्रन्य		529,09,65,000	(ख) केन्द्रीय भृमिबंधक बैंको के डिबेंचरों में निवेश	11,13,14,00
वेय विल		90, 10, 80, 000	राष्ट्रीय कृषि ऋणं (स्थिरीकरण) निधि मे ऋण	
44 (40)		, , ,	धौर प्रग्रिम र	
			राज्य सहकारी बैकों का ऋण श्रीर श्रमि .	52,56,95,000
म्रन्य देयनाए		503,62,85,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वीर्घकालीन कियाएं) निधि से	
આવ્ય વગવાલું કે		000,02,00,000	ऋण, श्रायम भौर निवेश	
			(क) विकास बैंक को ऋण ग्रीर यग्रिम	178,69,56,000
			(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडो/डियेचरो	2.0,00,0-,0-
			में निवेश	
			श्रन्य धास्तियां	159,65,23,000
स्पयं		2559, 57, 66, 000	स्पर्ये .	2559,57,66,00

^{*}नकदी, ग्राप्रधिक जमा श्रौर म्रस्पकालीन प्रतिभृतिया शामिल है ।

^{**}राष्ट्रीय ऋण (दीर्घकालीन कियाएं) निधि श्रीर राष्ट्रीय श्रीद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन कियाए) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं। †राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन कियाए) निधि से प्रदक्त ऋण श्रीर श्रीयम शामिल नहीं हैं, परंतु राज्य गरकारों को विये गये श्रम्थायी। श्रीघरप्रापट शामिल है।

[्]रीरिश्वं बैंक शाफ इक्ष्या श्रीधनियम की धारा 17(4)(ग) के श्रक्षीन श्रनुसूचित वाणिज्य वैंकों को मियादी जिलो पर अग्निम विधे गये 157,53,73,000/-इपये गामिल है।

⁽ঐ राब्दीय भूषि ऋण (दीर्घकासीन कियाए) निधि भीर राब्दीय ६/णि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदल ऋण और ग्रामिस सामित नहीं है। एस० जनसाथन, শर्जनर

[[]स० क० 10/1/74-की०धी० I]

ष० य० मीरक दानी, भ्रवर सचिव ।

S.O. 1931.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 5th day of July 1974

	•				
— LIABILITIES	Rs	Rs.	ASSETS	Rs	R
Notes held in the Banking Department	25,48,99,000		Gold Coin and Bullion:		
•			(a) Held in India	182,53,05,000	
Notes in circulation	6484,28,34,000		(b) Held outside India Foreign Securities	166,73,97,000	
Total Notes issued		6507,77,33,000	Total Rupee Coin		349,27 () ',000') 7,38,33,000
			Government of India Rupee Securities		6153,11,98,00 0
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		• •
			т		
Total Liabilities		6509,77,33,000	Total Assets		6509,77,33,00
				S. JAGANNATH	IAN, Governor.

Dated the 10th day of July 1974.

Statement of the Affairs of the Seserve Bank of India, Banking Department as on the 5th July 1974

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes Rupee Coin	25,48,99,000 5,33,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin Bills Purchased and Discounted:	2,64,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	284,00,00,000	(a) Internal (b) External (c) Government Treasury Bills	269,11,87,000 114,31,28,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	95,00,00,000	Balances Held Abroad *	548,92,04,000 349,58,88,000
National Industrial Credit		(i) Central Government	
(Long Term Operations) Fund	265,00,00,000	(ii) State Governments@ Loans and Advances to:—	119,75,59,000
Deposits:-		(i) Scheduled Commercial Banks [†]	395,64,85,000
(a) Government		(ii) State Co-operative Banks‡	160,59,90,000
(i) Central Government	89,51,47,000	(iii) Others	26,64,70,000
(ii) State Governments	15,23,22,000	Loans, Advances and Investments from National	
(b) Banks		Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(i) Scheduled Commercial Banks	509,87,87,000	(1) Loans and Advances to:-	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	21,20,50,000	(i) State Governments	67,87,34,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,51,18,000	(ii) State Co-operative Banks (iii) Central Land Mortgage Banks	15,49,37,000
(iv) Other Banks	1,10,12,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	64,00,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank De- bentures Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	11,13,14,000
(c) Others	320,90,65,900		
Bills Payable	90,40,80,000	Loins and A lvances to State Co-operative Banks Loans, Advances and Investments from National	52,56,95,000
		Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Journal I Advances to the Development Bank	173,69,56,000
		(b) Investment in bonds/Debentures issued by the Development Bank	
Other Liabilities	503,62,85,000	Other Assets	159,65,23,000
RUPELS	2559,57,66,000	RUPEES	2559,57,66,000

^{*} Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

Dated the 10th Day of July, 1974.

^{**} Excluding Investments from the National Agricultural Credit (1 mg Ferm Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

id Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Coshi (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

Findludes Rs. 157,53,73,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India. Act.

¹ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Coefficient Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

वाणिज्य मंत्रालय

श्रावेश

नई विल्ली, 3 भ्रागस्त, 1974

का॰ आ॰ 1932—पन भारत के निर्मान व्यापार के विकास के लिये मुद्रण स्थाही का निर्मात से पूर्व क्वालिटी नथा निरीक्षण के ग्रधीन लाने के लिये किनम्य प्रस्ताव निर्मात (क्वालिटी नियलण अर्थि निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उप-नियम (2) जारा यथा-पैक्षिन भारत मरकार के बाणिज्य मलालय के भ्रावेश स० का॰ आ॰ अ३२, तारीख 1 दिसम्बर, 1973 के ग्रधीन भारत के राजपत, भाग 2, खड़ 3, उपखट, (11), नारीख 1 दिसम्बर, 1973 से पृष्ट 3908-3909 पर प्रकाणिन किए गए है ——

न्नीर यत. उनसे सभाव्यत. प्रधावित होने वाले सभी व्यक्तियों में उक्त प्रादेश के सरकारी राजपन्न में प्रकाणित हाने की तारीख में 30 दिन के भीतर प्राक्षेप ग्रीर सुझान मागे गए थे.

भीर यत[.] उक्त राजपद्म भ्रादेश जनता को 14 दिसम्बर, 1973 उपलब्ध करा दिया गया था :

श्रीर यत. उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त श्राक्षेपो श्रीर सुझावा पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

भ्राप्त, श्राब, केन्द्रीय सरकार, निर्मात (क्वालिटी नियल्लण श्रीर निरीक्षण) श्रिधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा ७ द्वारा प्रदत्त णिक्तमों का प्रयाग करने हुए, निर्मात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्मात क्यापार के विकास के लिये ऐसा करना श्रावश्यक तथा समीचीन है :--

- (1) श्रश्चित्त्वित करती है इस श्रादेश के उपावध में यिनिर्दिग्ट मुद्रण स्याही निर्यात से पूर्व क्यालिटी नियवण श्रीर निरीक्षण के श्रशीन होगी.
- (2) मुद्रण स्याही के निर्यात (क्वालिटी नियत्नण श्रीर निरीक्षण) नियम, 1974 के श्रनुसार क्वालिटी नियंत्रण श्रीर निरीक्षण के उस प्रकार को विनिदिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसी मुद्रण स्याही पर लागु होगा;
- (3) उक्त मुद्रण स्थाही के लिये क्रेना तथा विशेता के बीच करार पाए गए सर्विदा के विनिवेंशों को मानक विनिवेंशों के रूप में मान्यता देनी हैं,
- (1) श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसी मुद्रण स्थाही के निर्यान का तब तक प्रतिरोध करती है जब तक कि उसके प्रत्येकपरेषण के साथ निर्यात (बवालिटी नियत्नण और निर्यक्षण) क्रिधिनियम 1963 की धारा 7 के श्रन्तर्गत स्थापित निर्यात निरीक्षण श्रिभिकरणों में से किसी श्रिभिकरण द्वारा दिया गया इस श्राणय का प्रमाण पत्न न हो कि मुद्रग्गस्याही का परेषण बवालिटी नियत्वण श्रीर निरीक्षण संबंधी शतों का पूरा करता है और निर्यात योग्य है।

७. इस आदेण की कोई भी आत स्थल समुद्र या वायु मार्ग बारा भावी क्रेनाओं का मुठण स्थाही उन तमूनों के सद्भावपूर्वक निर्धात करने पर लागू नहीं होंगी।

उपाबन्ध

- ा विस्र प्रेस स्थाशी
- तीया ग्राफिक स्याही

3. श्राफसेट स्याती

- 4 फलेक्सोग्राफिक स्याही
- 5 ग्रव्युचार/इंटागेलिया स्याष्ट्री
- 6. मेटल डेकोरेटिंग स्याही
- 7. स्कीन प्रोसेस स्याही
- 8 इलैक्ट्रोस्टेटिक स्याही

[सं० 6 (8)/7 अ-नि० नि० तथा नि० मं०]

MINISTRY OF COMMERCE ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1974

S.O. 1932.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting printing inks to quality control and inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule II of the Export (Qual') Control and Inspection) Rules. 1964, at pages 3908-3906 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st December, 1973, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O 3323, dated the 1st December, 1973;

And whereas, objections and suggestions were invited within thirty days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette Order was made available to the public on the 14th December, 1973;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

- (1) notifies that printing inks specified in the Annexure to this Order shall be subject to quality control and inspection prior to export;
- (2) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Printing Inks (Quality Control and Inspection) Rules, 1974 as the type of quality control and inspection which shall be applied to such printing inks prior to export;
- (3) recognises the specifications of the contract as agreed upon between the buyer and the seller as the standard specifications for the said printing inks;
- (4) prohibits the export, in the course of international trade, of such printing inks, unless every consignment thereof is accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies, established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, to the effect that the consignment of printing inks satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is exportworthy.
- 2. Nothing in this Order shall apply to the bonafide export by land, sea or air of samples of printing inks to prospective buyers.

ANNEXURE

- 1. Letterpress inks.
- 2. Lithographic inks.
- 3. Offset inks.
- 4. Flexographic inks.
- 5. Gravine/intaglio inks.
- 6 Metal docorating inks.7. Screen process inks.
- 8. Flectrostatic inks.

का० ग्रा० 1933,---केन्द्रीय सरकार, नियति (क्वालिटी नियंत्रण ग्रीर निरीक्षण) ग्रिधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवन भ हो का प्रयोग करने हुए, निम्निलिखित नियम बनानी है, श्रर्थात् ----

- मिक्षण्त नाम श्रीर प्रारम्भ--(1) इन नियमो का संक्षिण्त नाम मुद्रण स्याही निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण श्रीर निरीक्षण) नियम, 1974 है।
- (2) ये 3 सितम्बर, 1971 को प्रश्न होगे।
- - (क) 'ग्रधिनियम' में निर्यात (क्वालिटी नियन्नण ग्रीर निरीक्षण) ग्रिधिनियम, 1963 (1963 का 22) ग्रभिन्नेत हैं ;
 - (ख) 'श्रिभिकरण' से श्रिशितयम की धारा 7 के श्रशीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई, धौर दिल्ली में स्थापित किए गए निर्यात निरीक्षण श्रिभिकरणों में से कोई भी श्रिभिकरण श्रीभ-प्रेस है।
 - (ग) 'मुद्रण स्याही' से निम्नलिखित मुद्रण स्याही तथा उनके मान्द्र ग्रभिप्रेत है, ग्रयति:--
 - भेटरप्रेस स्याही
 - लीथोग्राफिक स्याही
 - 3. श्रोफसेट स्याही
 - 4 फलेक्सोग्राफिक स्याही
 - प्रब्युमर/इन्टागेलियो स्याही
 - 6. मेटल डेकोरेटिंग स्याही
 - स्कीन प्रामेस स्याही
 - इलेक्ट्रोस्टेटिक स्याही
 - (ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से सलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- 3. क्वालिटी नियंत्रण——(1) मृद्रण स्याही का क्वालिटी नियंत्रण उत्पाद के विनिर्माण, परिरक्षण तथा पैक करने की विभिन्न ध्रवस्थाओं में निम्नसिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाएगा, ध्रथांतृ :—
- (1) कय किए गए तथा कच्चे माल संबंधी नियंत्रण
 - (क) ऋय विनिर्देश, विनिर्माता क्षारा प्रयोग किए जाने वाले कच्छे मालो के गुण धर्मों का समावेश करते हुए श्रधिकथित किए
 - (ख) अय किए गए माल के स्वीकृत परेषणों के साथ यातों विनिर्माता के कम विनिदेशों की अपेकाओं की पुष्टि करते हुए प्रदाय कत्ती का परखा तथा निरीक्षण का प्रमाण-पत्न होगा, ऐसी दणा में विणिष्ट प्रदाय-कर्ता के लिए विनिर्माता द्वारा कम से कम 10 परेषणों में एक बार परखा याा निरीक्षण प्रमाणपत्न की णुढता जांचने के लिए समय-समय पर जांच की जाएगी, या अध्य किए गए माल की कारखाने के भीतर की प्रयोगणाला में या किसी बाहरी प्रयोगणाला में या परीक्षा-गृह में निर्यामत परस्त्र तथा निरीक्षण किया जाएगा।
 - (ग) निरीक्षण या परस्य किए जाने के लिए लिया जाने वाला नमूना श्रमिलेखित श्रन्वेषण पर श्राक्षारित होगा।
 - (ध) निरीक्षण या परस्य किए जाने के पश्चान् स्वीकृत तथा धस्कीकृत

- माल को ग्रलग-ग्रालग करने मे ग्रीर शस्त्रीकृत माल के निपटान के लिए व्यवस्थित ढंग ग्रापनाएं जाएंगे।
- (क) पूर्वोक्त नियत्नणों के सम्रोध में पर्याप्त अभिलेख नियमित श्रीर व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।
- (ii) प्रक्रिया नियक्षण---(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निनिर्देश प्रधिकथित किए जाएंगे।
- (ख) प्रक्रिया विनिर्देण मे ग्रिश्चिम्पिन प्रिक्रियाच्यो को नियन्निन करो के लिए उपस्कर ध्रीर उपकरण सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं दी जाएगी ।
- (ग) वितिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किए गए नियंत्रणों के सत्यापित करने की सम्भावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएगे ।
- (iii) उत्पाद नियलण--(क) विनिर्माता केपास यह जाच करने के लिए कि क्या उत्पाद इस श्रिधिनियम की धारा 6 के श्रन्तर्गय मान्य विनिर्वेशों के श्रनुरूप है या तो उसकी श्रपनी परख सुविधाएं होगी या जहां ऐसी परख सुविधाएं हो वहां उसकी पहुंच होगी।
- (खा) परस्त्र ग्रौर निरीक्षण के लिए लिया जाने वाला नमूना ग्रीभ-लिखिन ग्रन्वेषण पर ग्रीधारित होगा ।
- (ग) प्रत्येक बैच से बानगी स्वरूप नमूने लिए जाएंगे । बड़े नमूने को दो बराबर परख नमूनो मे बाट दिया जाएगा । परख के ऐसे एक नमूने की विनिर्माता द्वारा, उत्पाद की ध्रपेक्षा में लिए परख की जाएगी तथा दूसरा उसकी विशास्त्रियों सहित सदर्भ नमूने के रूप से कम-से कम छह मास तक ध्रारक्षित रखा जाएगा।
- (घ) नमूना लिए जाने नथा की गई परख के सम्बन्ध में पर्याप्त श्रिभिलेख नियमित एवं व्यवस्थित रूप में रखे जाएगे।
- (इन्) उत्पादन की जाच करने के लिए नियन्नण के न्यूनतम स्तर वे होगे जा इन नियमों की ग्रानुमूची में विए गए हैं।
- (iv) परिरक्षण नियंत्रण—(क) उत्पादन को मौसम की वशाम्रो के प्रतिकृल प्रभाव से बचाने के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत विनिर्देश प्रधिकथित किए जाएंगे।
- (ख) उत्पाद भण्डारकरण तथा ग्रिभिवहन के दौरान भली-भाति परिरक्षित किया जाएगा ।
- (v) पैकिंग करने सम्बंधी नियन्नण---(1) उत्पादों को पैक करने सब्बधी ऐसे नियंत्रणों जो श्रनुसूची में उल्लिखिन है को पूरा करने की दृष्टि से पैक करने संबधी व विनिर्देण श्रधिकथित किए जाएंगे।
- (2) निरीक्षण—निर्यात किए जाने के लिए अशियत मुद्रण स्याही का निरीक्षण यह सुनिर्धिचन करने की दृष्टि में किया जाएगा कि मुद्रण स्याही इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देणों के अनुरूप हैं।
- 4 निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) मुक्रण स्याष्ट्री के परेषण के निर्यात का इच्छुक निर्यात-कर्ता अपने ऐसा करने के आणय की लिखित सूचना अभिकरण को देगा तथा ऐसी सूचना के साथ एक घोषणा-पक्ष भी देगा कि मुक्रण स्याष्ट्री का परेषण विनिर्माण नियम 3 में अधिकथित क्वालिटी नियक्षण उपायो का प्रयोग करने हुए,

किया गया है या किया जा रहा है भीर परेषण १० पारा के लिए मान्य त्रिनिर्देणों की श्रपेक्षाओं के श्रनरूप है।

- (2) निर्यात कर्ना प्रभिकरण को परेषण पर लगाए गए पहचान चिहन नी देगा।
- (3) उप नियम (1) के प्रधीन दी गई प्रत्येक सूचना नथा घोषणा प्रभिक्रण के कार्यालय में, विनिर्माता द्वारा, परेषण के प्रेषित किए जाने के कम से कम 2 दिन पत्रले पहुच जाती चाहिए।
- (1) उप-नियम (1) के अधीन दी गई सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण अपना यह समाधान हो जान पर कि विनिर्माण की पित्रिया के दौरान नियम 3 में येथा उपनिधन पर्याप्त क्वालिटी नियसणों का प्रयोग किया गया है निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर आरी किए गए आदेशा के अनुसार परेषण का निरीक्षण करगा।
 - (5) यदि ऐसे निरीक्षण के पण्चान्, ग्राभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाली मुद्रण स्याष्टी का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो बह उप-नियम (3) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर निर्यात कर्ना को एसा प्रमाणपत्न दे देगा कि परेषण क्ष्वास्तिटी नियतण और निरीक्षण की शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात याग्य है।
- परन्तु जहां श्रभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहा वह उक्त सात दिनों की श्रवधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पह देने से इकार कर देगा तथा उसके लिए वारण बताने हुए निर्यात-वर्ता को ऐसे इकार की सूचना देगा।
- 5 निरीक्षण का स्थल—इन नियमो के फ्रन्तर्गत प्रत्येक निरीक्षक केवल विनिर्माता के परिसर पर ही किया जाएगा ।
- 6 निरीक्षण णुल्क—प्रत्येक परेषण के लिए त्यूनतम बीस रुपण माल्ल के प्रधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक परेषण के पोतपर्यन्त नि गुल्क मूल्य के प्रत्येक एक मौ रुपण के लिए चालीस पैसे की दर से फीस निर्यात-कर्ता हारा प्रभिकरण को इन नियमों के प्रधीन निरीक्षण णुल्क के रूप से दिया जाएगा।
- 7 धर्पील—(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत अधिकरण हारा प्रमाण-पन्न देने से इंकार कर देने में व्यथित काई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे हकार की सूचना प्राप्ति से दम दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वम प्रयोजन के लिए नियुक्त कम में कम तीन विशेषज्ञों के पेसल को अपील कर सकेगा।
- (2) विशेषज्ञा के पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
 - (3) पैनल के लिए गणपूर्ति तीन होगी।
 - (4) ऐसी ग्रंपील के सबध में पैनल का विनिध्चय प्रन्तिम होगा।
- (5) भ्रापील उसकी प्राप्ति होने के पन्त्रेल दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

सनुसूर्वी (स्त्रड 3 देखिए)

(1) उत्पाव में लिए नियंत्रण-स्तर

कम म०	म पेक्षा <i>एं</i>	निर्देश	जाच मी ग्रावृत्ति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1	स्प .	इस प्रयोजन के लिए मान्य मानक विनिर्देश	∽	
2	छपाई के बाद रग	n	"	भाफसेट, नीथो तथा लेटर प्रेस स्याही के लिए मानक छपाई से निश्चित किया जाना।
3	मोड/वर्ण .	n	н	"
4	प्रगादना .	n	11	"
5	फिभिण	,,	n	,,,
6	व्यापान/म्रारपारहो जाना	7	"	11
7	भ्रतिरोध/चिपचिपाहट तथा ब हाव .	"	"	जैसा भी लागू हो, माध्यम या रंग पट्टिका चाक् द्वारा ।
8	फैनाय की तीव्रना	"	n	मानक प्रेषण मापकद्वारा ।
9	चिपकन .	n n	11	जैसा भी लागू हो माध्यमद्वारा ।
0	सूस्त्रने काममय .	n	,,	जैमा भी नागू हो
	सवधित प्रगाइता/ विभिष्ट गुरूत्व .	"	n	मानकपरस्य ।
. 2	मुद्रण परस्य .	"	प्रत्येक दसवा वै प	
. 3	भासजन	n	प्रत्येक बैच	तरल स्याहियो ग्रीर धातुकी सजावटी घस्तु- ग्रो के लिए ।

2 इस प्रयोजन के लिए प्रध्येक बैच 14 अवराधन मान्य मानक विनिर्देश 15 प्रतिरोध परखे.--(क) कृतिम प्रकाश प्रतिरोधन (ख) जल प्रतिरोधन (ग) श्रय्कलीप्रतिरोधन (ष) भ्रम्भ प्रतिराधन (इ) ग्रन्कोहल प्रतिरोधन (च) विलायक प्रति जहालागृहो । गधन (छ) माम भौर चर्बी प्रतिरोधन (ज) साबुन प्रति-रोधन (झ) ममाला प्रति-राधन (ण) चर्षण प्रति-राधन (ट) फाइनटेन घोल मे खराबी ,,

_ _ _ _

2 पैक करने सबधी नियक्षणों के स्तर

16 विश्वत विशेषताए

2 । पैज और डिज्बे प्रच्छी फिनिश वालेहा तथा देखने मे भच्छे लगें।

प्रत्येक दसवा

बैच

इसैयट्रोग्टेटिक

म्याही लागूबैचा।

2 2 ष्टिब्बे लीक-रोबी भ्रौर श्रभिबहन के दौरान चढ़ाने उतारने का सहन करने योग्य पर्याप्त मजबूत हो ।

- 2 3 पैकेजो के ग्रन्दर के डिब्बे इस प्रकार से पैक किए जाएगे कि ग्रापस से न टकराए ।
- 4 निम्नलिखित सूचना प्रत्येक डिब्बे पर या उमापर लगे शेवाश पर बी जाएगी ——
 - (क) माल का नाम ।
 - (ख) विनिर्माता का नाम ग्रीर ट्रेप्ट मार्क, यदि कोई हो ।
 - (ग) विनिर्माण का मास ग्रौर वर्ष ।
 - (घ) माल की मात्रा ।
 - (ड) कोड में या श्रन्यथा बैच मख्या नाकि ग्राभिलेखामें विनिर्माण का बैच जाना जा सके ।

[मं ० 6(8) / 7 3- नि ० नि ० तथा नि ० सं ०]

- S.O. 1933.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely —
- 1 Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Printing Inks (Quality Control and Inspection) Rules, 1974
 - (2) They shall come into force on 31d September 1974, 51 GI 74-3

- 2 Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires, ---
 - (a) "Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
 - (b) "Agency' means any one of the Export Inspection Agencies, established under section 7 of the Act at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi;
 - (c) "printing inks" means the following printing inks and their concentrates, namely —
 - 1 Letterpress inks
 - 2 Lithographic inks
 - 3 Offset inks
 - 4 Flexographic inks
 - 5 Gravure/intaglio inks
 - 6 Metal decorating inks
 - 7. Screen process inks
 - 8 Electrostatic inks
 - (d) "Schedule" means the schedule appended to these rules.
- 3 Quality Control —(1) The quality control of printing inks shall be ensured by affecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the product, namely
 - (I) Purchased and raw material control—(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used
 - (b) The accepted consignments of the purchased material shall be either, accompanied by the supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications of the manufacturer in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the manufacturer for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificates or the purchased material shall be regularly tested and inspected either in the laboratory within the factory or in an outside laboratory or test house
 - (c) The sampling for ispection or test to be carried out shall be based on the accorded investigation
 - (d) After the inspection of test is carried out, systematic methods shall be adopted in sagregating the accepted and rejected materials and for disposal of the rejected materials.
 - (e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained
 - (ii) Process control.—() Detailed process specification shall be laid down by the manufacturer for different processes of manufacture
 - (b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification
 - (c) Adequate records shall be maintained to ensure the possibility of verifying the controls exercised during processes of manufacture
 - (iii) Product Control—(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities of shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to specifications recognised under section 6 of the Act
 - (b) Sampling for test and inspection to be carried out shall be based on the recorded investigation

- (c) Representatives sample shall be drawn from each batch. The bulk sample shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested by the manufacturer for the requirement of the product and the other shall be reserved as referce sample along with its particulars for at least six months.
- (d) Adequate records in respect of sampling and tests carried out shall be regularly and systematically maintained.
- (c) The minimum levels of control to check the products shall be as given in the Schedule to these rules.
- (iv) Preservation control.—(a) Detailed specifications shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effect of weather conditions.
 - (b) The product shall be well preserved both during the storage and the transit.
- (v) Packing control.—Packing specifications shall be laid down with a view to satisfying the controls mentioned in the Schedule for packing of the products.
- (2) Inspection. The inspection of printing inks intended for export shall be carried out with a view to ensuring that the printing inks conform to the specifications recognised for the purpose.
- 4. Procedure of inspection.—(1) The exporter intending to export a consignment of printing inks shall give intimation in writing of his intention to do so to the Agency and submit along with such intimation, a declaration that the consignment of printing inks has been or is being manufactured by exercising quality control measures laid down in rule 3 and that he consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for the purpose.
 - (2) The exporter shall also furnish to the Agency, the identification marks applied on the consignment.
 - (3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall teach the office of the Agency not less than seven days prior to the despatch of the consignment, from the manufacturer.

- (4) On receipt of the intimation and declaration under subrule (1), the Agency, after satisfying itself that during the process of manufacture, adequate quality control as provided in rule 3, has been exercised, shall carry out the inspection of the consignment in accordance with the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time
- (5) If after inspection, the Agency is satisfied that the consignment of printing inks to be exported complies with the requirements of rule 3, it shall, within seven days of the receipt of intimation and declaration under sub-rule (3), issue a certificate to the exporter to the effect that the consignment satisfies the conditions relating to quality control and inspection and its exportworthy:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

- 5. Place of inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out at the premises of the manufacturer.
- 6. Inspection fee.—Subject to a minimum of rupees twenty only for each consignment, a fee at the rate of forty paise for every hundred rupees of f.o.b. value of each such consignment for every hundred rupees of f.o.b. value of each such consignment shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee under these rules.
- 7. Appeal— (1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not loss than three persons, appointed for the purpose by the Central Government.
 - (2) The panel will consist of at least two-thirds of nonofficials of the total membership of the panel of experts.
 - (3) The quorum for the panel shall be three.
 - (4) The decision of the panel on such appeal shall be final.
 - (5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

SCHEDULE

(See Clause 3)

(1) Levels of control for products

Sl. No.	Requirement			Requirement Reference		Frequency of checks	Remarks		
1		2	: -				3	4	5
1.	Арреатапсе			,	•	•	Standard specification recognised for the purpose	Every batch	
2.	Colour on draw	down				•	n	D	For offset, litho and letterpress inks, to be determined from standard drawdown.
3.	Shade/Hue						2)	,,	"
4.	Strength .						,,	,,	.,
5.	Finish .						***	,,	**
6.	Strike through						**	"	
	Consistency/visc						17	"	By instrument or palette knife as applicable.
8.	Fineness of disp	ersion	n ,				"	7)	By standard grinding gauge,
	Tack							,,	By instrument as applicable.
10.	Drying time						,,	,,	As applicable.

1

]	2	·	3	4	5
11.	Relative density/specific gravity		Standard specification recogni- sed for the purpose	Every batch	Standard Tost.
12.	Printing Tost		"	Every 10th batch	
13. 14.	Adhoslon Blocking		n	Every batch	For liquid inks & metal decorating products.
15.	Resistance tests— (a) Resistance to artificial light (b) Resistance to Water (c) Resistance to alkalı (d) Resistance to Acid (e) Resistance to Alcohol (f) Resistance to Solvents (g) Resistance to Wax and Fat (h) Resistance to Soap (i) Resistance to spices (f) Resistance to Rubbing		11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		. Where applicable.
16.	(k) Resistance to Broakdown tain Solution	in Foun-	" 	Every 10th batch	Applicable for electrostatic inks.

(2) Levels of control for packing

- 2.1 The package and containers shall be well tinished and shall have a good presentability.
- 2.2 The containers shall be leakproof and of sufficient strength to withstand handling during transit.
- 2.3 The inner containers within the package shall be so packed as to aviod collisions amongst them.
- 2.4 The following information shall be given on each container or the label, applied to it:—
 - (a) Name of the material.
 - (b) Manufacturer's name and trade mark, if any.
 - (c) Month and year of manufacture.
 - (d) Quantity of the material.
 - (o) Batch number in code or otherwise to enable the batch of manufacture to be traced from records.

[No. 6(8)/73-LI & EP]

का० ग्रा० 1934.---निर्यात (क्वालिटी नियत्रण ग्रीर निरीक्षण) ग्रिशिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रगोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, नेल-रिहिन चावल की भूमी का निर्यात (क्वालिटी नियत्रण ग्रीर निरीक्षण) नियम, 1966 में ग्रीर मणोधन करने के लिए निम्नलिखिन नियम एनद्द्वारा बनाती है, ग्रिथीत :---

- (1) इस नियमो का नाम नेल-रहित खाबल की भूमी का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण श्रीर निरीक्षण) सणोधन नियम, 1974 है। (2) ये नियम राजपत्न मे प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- (3) तेल-रहिन खादल की भूगी का निर्यात (क्वालिटी नियम्नण ग्रीर निरीक्षण) नियम, 1966 में, नियम 4 के उप-नियम (3) में, खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, ग्रर्थान् ----
 - "(2) गैम-बद भावरणो के भीतर 72 घटो की प्रभावन भ्रवधि सहित एल्यूमिनियम फोसफा**४ड की** 9 गाम/ टन की माला का प्रयोग करके।"

[**म** 6 (10) / 74 – नि नि नि नथा नि म]

- S.O. 1934.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of De-oiled Rice Bran (Quality Control and Inspection) Rules, 1966, namely.—
 - (1) These rules may be called the Export of De-oiled Rice Bran (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1974.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 In the Export of De-oiled Rice Bran (Quality Control and Inspection) Rules, 1966, in sub-rule (3) of rule 4, for clause (ii) the following clause shall be substituted, namely:—

 "(ii) Allummium phosphide by using a dose of 9 grams/tonne with an exposure period of 72 hours under gastight covers."

[No. 6(10)/74-EI&EP]

का० थ्रा० 1935.——निर्यात (क्वालिटी नियम्नण ग्रीर निरीक्षण) श्रिष्टिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, रबड़ की बर्फ की पैलियों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में ग्रीर मणाधन करने के लिए निम्नलिखन नियम बनाती है.

- (1) इन नियमों का नाम रबष्ट की बर्फ की यैलियों का निर्यात (निरीक्षण) सणोधन नियम, 1974 है।
 - (2) ये नियम राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्ष होगे।
- रबड़ की बर्फ की थैंलियों का निर्मात (निरीक्षण) नियम, 1966
 में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, ग्रथित .--
 - "7. प्रपील——(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के स्रधीन असि-करण द्वारा प्रमाणपत्र देने से इकार कर देने से व्यथित कीई व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की ससूचना पान्त होने से दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयाजन के लिए नियुक्त किए गए त्रिशेषज्ञों के पैनल का अपील कर सकेंगा जिससे कम से कम लीन व्यक्ति हांगे।

- (2) ऐसे पैनल में, विशेषकों के पैनन की कुल सवस्थता के कम से कम दो-तिहाई गैर-मरकारी सबस्य होगे।
- (3) ये पैनल की गणपूर्वि तीन होगी।
- (4) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अतिम होगा।
- (5) श्रपील, उसके प्राप्त हाने में पुन्द्रह दिस के भीतर निपटा दी जाएगी।

[स॰ ६(६)/७4-नि॰ नि॰ तथा नि॰ स॰]

- S.O. 1935.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Ice Bags (Inspection) Rules, 1966.
- 1. (1) These rules may be called the Export of Rubber Ice Bags (Inspection) Amendment Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. In the Export of Rubber Ice Bays (Inspection) Rules, 1966, for rule 7 the following rule shall be substituted, namely:—
 - "7. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of exports consisting of not less than three persons, appointed for the purpose by the Central Government,
 - (2) The panel will consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the panel of experts.
 - (3) The quorum for the panel shall be three.
 - (4) The decision of the panel on such appeal shall be final. -
 - (5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt."

[No. 6 (5)/74-EI&EP]

का० गा० 1936.——निर्यात (क्यांग्लिटी निर्यातण ग्रीर निरीक्षण) ग्रिधि-नियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवत्त मिन्नियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रखड़ बैल्टिंग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में ग्रीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है

- (1) इन नियमो का नाम रबड़ बैहिटग का निर्यात (निरीक्षण) सणोधन नियम, 1974 है।
 - (2) ये नियम राजपन्न में प्रकाशन की नारीख को प्रवृत्त होंने।
- 2. रखड़ की बैल्टिंग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में, नियम 7 के स्थान पर, निम्निलिखिन नियम रखा जाएगा, प्रथान .--
 - "7. भ्रपील——(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन प्रभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्न देने में इंकार कर देने से व्यक्षित
 कोई व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दस
 दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए
 नियाल किए गए विशेषकों के पैनल को अपील कर सकेगा,
 जिससे कम से कम तीन व्यक्ति होगे।
 - (2) ऐसे पैनल में, विशेषकों के पैनल की कुल सदस्यला के कम से कम दो-निहाई गैर-सरकारी सदस्य होगे।

- (3) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी।
- (4) ऐसी ऋषील पर पैनल का विनिण्चय ऋतिम होगा।
- (5) ग्रापील, उसके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[म० ७(5)/74-नि० नि० तथा नि० सं०]

- S.O. 1936.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Beltings (Inspection) Rules, 1966.
- 1. (1) These rules may be called the Export of Rubber Beltings (Inspection) Amendment Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. In the Export of Rubber Beltings (Inspection) Rules, 1966, for rule 7 the following rule shall be substituted, namely:—
 - "7. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons, appointed for the purpose by the Central Government.
 - (2) The panel will consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the panel of experts.
 - (3) The grorum for the panel shall be three.
 - (4) The decision of the panel on such appeal shall be final.
 - (5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt."

[No. 6 (5)/74-EI&EP]

का० आर 1937. — निर्याम (क्वानिटी नियंत्रण और निरीक्षण) प्रिध-नियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदम्न शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, रखड़ के वस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में भीर मणोधन करने के लिए निस्नलिखित नियम बनाती है:

- 1 (1) इन नियमां का नाम रबड़ के दस्तानों का निर्यात (निरी-क्षण) भगोधन नियम, 1974 है।
 - (2) ये नियम राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2 रखड़ के दस्तानो का निर्यात (मिरीक्षण) नियम, 1966 में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखन नियम रखा जाएगा, अर्थान् :----
 - "7 अपील—→(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्न देने से इंकार कर देने से व्यक्षित कोई व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए विशेषजों के पैनल को अपील कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन व्यक्ति होंगे।
 - (2) ऐसे पैनल मे, विशेषकों के पैनल की कुल सदस्यता के कम स कम दो-निहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

- (3) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी।
- (4) ऐसी भ्रपील पर पैनल का विनिम्चय भ्रतिम होगा।
- (5) भ्रापील, उसके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[स॰ 6(5)/74-नि॰ नि॰ नथा नि॰ स॰]

- S.O. 1937.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Gloves (Inspection) Rules, 1966.
- 1. (1) These rules may be called the Export of Rubber Gloves (Inspection) Amendment Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. In the Export of Rubber Gloves (Inspection) Rules, 1966, for rule 7 the following rule shall be substituted, namely :-
 - "7. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (3) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of exports consisting of not less than three persons, appointed for the purpose by the Central Government.
 - (2) The panel will consist of at least two-third of nonofficials of the total membership of the panel of
 - (3) The quorum for the panel shall be three.
 - (4) The decision of the panel on such appeal shall be final.
 - (5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

[No. 6 (5)/74 EI&[P]

का० द्या० 1938.--निर्यात (क्वालिटी नियन्नण ग्रौर निरीक्षण) मधि-नियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त मिन्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रबड की बैल्टों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में ग्रीर मणोधन करने के लिए निम्नलिखिल नियम बनाती है :

- । (1) इन नियमों का नाम रखंड की बैक्टो का निर्यात (निरीक्षण) संगोधन नियम, 1974।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाणन की तारीख का प्रयुत्त हांगे .
- 2. रबड़ की बैस्टों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, श्रर्थात →-
 - ''७. ग्रापील---(।) नियम ⊿ के उप-नियम (5) के ग्राधीन ग्राभि-करण द्वारा प्रमाण-पन्न देने से इकार कर देने से व्यक्षित, कोई व्यक्ति, उसे ऐसे इकार की ससूचना प्राप्त हाने से दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार धारा इस प्रयाजन के लिए नियवत किए गए विशेषकों के पैनल का श्रपील कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन ध्यक्ति होगे।
 - (2) ऐसे पैनल से, विशेषकों के पैनल की बूल सबस्यता के कम से कम दो-निहाई गैर सरकारी भदस्य होंगे।

- (3) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी।
- (4) ऐसी भ्रपील पर पैनस का विनिश्चय भ्रतिम ३।गा ।
- (5) अपील, उसके प्राप्त होते से पन्डह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

[स० ५(५)/७ ।- नि० नि० नथा नि० मं०]

- 8.0. 1938.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Belts (Inspection) Rules, 1966.
- l. (1) These rules may be called the Export of Rubber
- Belts (Inspection) Amendment Rules, 1974.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. In the Export of Rubber Belts (Inspection) Rules, 1966, for rule 7 the following rule snall be substituted,
 - "7. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons, appointed for the purpose by the Central Government.
 - (2) The panel will consist of at least two-third of nonofficials of the total membership of the panel of experts.
 - (3) The quorum for the panel shall be three.
 - (4) The decision of the panel on such appeal shall be final.
 - (5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

[No. 6 (5)/74-EI&EP]

का० मा० 1939.---निर्यात (क्वालिटी नियत्नण भीर निरीक्षण) प्रधि-नियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रखड़ की गर्म पानी की बोतलो का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 में और सणाधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:

- া. (।) इन नियमो का नाम रबड़ की गर्म पानी की बोतलों का निर्यात (निरीक्षण) सणोधन नियम, 1974 है।
 - (2) ये नियम राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवस होगे।
- 2. रबड़ की गर्स पानी की बोतला का निर्यात (निरीक्षण) नियम 1966 में, नियम 7 के रूथान पर, निम्नुलिखन नियम रखा जाएगा. प्रर्थान --
 - "7 अपील--(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के प्रधीन ग्राभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्न देने से इंकार कर देने से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसे इकार की समुचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए विशेषको के पैनल का श्रपील कर सकेगा जिस में कम से कम मीन व्यक्ति होगे।
 - (2) ऐसे पैनल में, थिणेयज्ञों के पैनल की कूल सदस्यता के कम में कम दो-तिहाई गैर भरकारी सदस्य होगे।

- (3) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी।
- (4) ऐसी भ्रपीन पर पैनल का विनियचय भ्रपिम होगा।
- (5) अप्रील, उसके प्राप्त हाने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ! [स० 6(5)/74-नि० नि० तथा नि० स०]
- 8.0. 1939.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection) Rules, 1966.
- 1. (1) These rules may be called the Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection) Amendment Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. In the Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection) Rules, 1966, for rule 7 the following rule shall be substituted, namely:—
 - "7. Appenl—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of exports consisting of not less than three persons, appointed for the purpose by the Central Government.
 - (2) The panel will consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the panel of experts.
 - (3) The quorum for the panel shall be three.
 - (4) The decision of the panel on such appeal shall be final.
 - (5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt."

[No. 6 (5)/74-EI&EP]

कार भार 1940.— निर्यात (क्यालिटी नियतण भीर निरीक्षण) भ्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 झारा प्रदत्त सकिनयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कायर मैंटिंग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 में भीर सणाधन करने के लिए निस्नलिखित नियम बनानी है, भर्थात् :-

- 1 (1) इन नियमो का नाम कायर मैटिंग निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 है।
- (2) ये नियम राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवस होंगे।
- 2 कायर मेटिंग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, ग्रर्थान् :---
 - 8. प्रपील——(1) नियम 7 के प्रश्नीन प्रभिक्तरण द्वारा प्रमाण-पन्न देने से इकार कर देने से व्यथित काई व्यक्ति, उसे ऐसे इकार की समूचना प्राप्त होने से दम दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए यिशोयकों के पैनल की श्रपील कर सकेगा जिससे कम से कम तीन व्यक्ति होंगे।
 - (2) ऐसे पैनल मे, विशेषका के पैनल की कुल सवस्थता के कम से कम थो-लिहाई गैर-सरकारी सवस्य होंगे।
 - (3) पैनल की गणपूर्ति तीन हागी।
 - (4) ऐसी ध्रेपील पर पैनल का विनिध्चय ध्रतिम होगा।
 - (5) श्रपील, उसके प्राप्त हाने सं पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

[ग० 6(5)/7 1-नि० नि० तथा नि० स०] म० कु० बी० भटनागर, ग्रार मिन्न

- 9.0. 1940.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Coir Mattings (Inspection) Rules, 1972, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Export of Coir Mattings (Inspection) Amendment Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. In the Export of Coir Mattings (Inspection) Rules, 1972, for rule 8 the following rule shall be substituted, namely:—
 - "8. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under rule 7, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons may be constituted for the purpose by the Central Government.
 - (2) The panel will consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the panel of experts.
 - (3) The quorum for the panel shall be three.
 - (4) The decision of the panel on such appeal shall be final.
 - (5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt."

[No. 6(5)/74-EI&EP]

M. K. B. BHATNAGAR, Under Secy.

भ्रान्तरिक व्यापार विभाग नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1974

का॰ गा॰ 1941.— कंन्द्रीय सरकार, अग्निम सिवदा (विनियम) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दि ग्रेन, राइस ए०ड आयलसीड् सर्वेन्ट्रम एसांशियेशन, बस्वई द्वारा मान्यता के लिए किये गए भावेदन पर वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके विचार कर लेने पर, और भपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना ज्यापार के हिन में और लाक हिन में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त गांवित्यों का प्रयोग करने हुए उक्त एसांशियेशन का म्गफली की गिरी की अग्निम सविदायों की बावल 10 अगस्त 1974 में 9 भगस्त 1975 तक (जिसमें ये दांनो दिन भी सम्मिलन है) की एक वर्ष भी कालाविध के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एनद्द्वारा प्रवन्त मान्यता इस गर्न के प्रध्यधीन है कि उक्त एमोशियोगन वायदा बाजार भायोग द्वारा समय समय पर दिये जाने जाले नियेशो का प्रमुपालन करेगा।

[फाइल म० 12(6)-ग्रा०व्या०/74]

DEPARTMENT OF INTERNAL TRADE New Delhi, the 19th July, 1974

S.O. 1941.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission—the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act. 1952 (74 of 1952) by the Grain, Rice & Oilseeds Merchants' Association, Bombav and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of

the said Act, recognition to the said association for a further period of one year from the 10th August, 1974 to the 9th August, 1975 (both days inclusive) in respect of forward contracts in groundnut kernels.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(6)-IT/74]

कारुआर 1942.— केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीम दि आगरा मर्बेन्ट्स चेम्बर लिर, आगरा द्वारा मान्यता के लिए दिये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग से परामर्ग करके, विचार कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हिन से और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्न मानित्यों का प्रयोग करने हुए उक्त चेम्बर को गृइ की अग्रिम संविद्याओं की बावत 10 अग्रम्न, 1974 से 9 अगस्त, 1975 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलन है) की एक वर्ष की कालाविध के लिए मान्यता प्रदान करनी है।

2. एतक्कारा प्रदत्न मान्यता इस गर्त के ग्रध्यधीन है कि उक्त चेस्बर वायवा बाजार ग्रायोग कारा समय-समय पर विये जाने वाले ग्रान्पालन करेगा।

> [फाइल मं० 12(7)-ग्रा॰व्या०/74] यु० एस० राणा, सयुक्त निवेशक

S.O. 1942.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Agra Merchants' Chamber Limited, Agra, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period of one year from the 10th August, 1974 upto the 9th August, 1975 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted in subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(7)-IT/74] U. S. RANA, Jt. Director

उप-मुख्य नियंत्रक, ग्रायात-निर्यात का कार्यालय

कौचीन, 18 मार्च, 1974

का० आ० 1943.—सर्वश्री सोनीक्षोन लेबोरेट्रीज, चन्नानिकाकू बाकघर द्वारा कुक्षीमटटम, केरल को बेन्जलडिहाइड के बासान के लिए वास्तविक उपयोजना श्रेणी के धन्तर्गन 7293/- रुपये (सान हजार दो सौ चौरानवे रुपये मास्र) के लिए एक लाक्सेंस संख्या: पी/एस/1720427/ ब्रार/एम एन/44/ई/33-34, बिनांक 17-7-72 प्रकान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेस की सीमाशुल्क नियासी प्रति की प्रतृत्तिः के लिए इस प्राधार पर प्रावेदन किया है कि 2265/- रुपये (वो हजार दो सौ पैसठ रुपये मान) करना शेष रहते हुए मूल लाइसेस खो गया। प्रम्थानस्थ हो गया है। इस वार्व के समर्थन में प्रावेदक ने निर्धारित प्रपत्न में एक शपथाल दाखिल किया है।

मैं मंतृष्ट हं कि लाउमेंन सख्या पी/एम/1720127/श्रीर/एम एल/44/ ई/33-34, दिनाक 17-7-72 की मूल मीमाशुल्क निकासी प्रति श्रांशिक उपयोग होने के बाव खा गई/ श्रम्थानम्थ हो गई है और निदेश देता हं कि इसकी अनुलिपि प्रति श्रांबदक को जारी की जाए।

[सख्या 4/74/एसएसआई]

भार० जयराम नायदू, उप-मुख्य नियलक

OFFICE OF THE DY. CHIEF CONTROLLFR OF IMPORTS AND FXPORTS

Cochin, the 18th March, 1974

S.O. 1943.—M/s. Sonebon Laboratories, Channanikadu P.O. Via Kuzhimattom, Kerala was granted licence number P/S/1720427/R/ML/44/E/33-34 dated 17-7-72 for Rs. 7294 (Rupees seven thousand two hundred and ninety-four only), for Benzaldehyde under Actual Users category.

They have applied for duplicate customs purposes copy of the said licence on the ground that the original licence has been lost/misplaced, with unutilised balance of Rs. 2265 (Two thousand two hundred and sixty five only). In support of the claim, the applicant has filed an affidavit in the prescribed form.

I am satisfied that the original Customs purposes copy of the licence No. P/S/1720427/R/ML/44/E/33-34 dated 17th July, 1972 has been lost/misplaced, partly utilised, and direct that a duplicate Customs copy of the said licence be issued to the applicant.

[No. 4/74/SSI]

R. JAYARAM NADU, Dy. Chief Controller

फरीवाबाद, 24 मार्च, 1974

श्रादेश

कार ग्रांत 1944.—सर्वश्री राका साइकल इन्डस्ट्रीज, 850, मुराधपुरा, गिल रोड, मिललरगंज, लुधियाना को सामान्य सुद्रा क्षेत्र से बम्बई पंजीयन पत्तन के लिए सभी प्रकार की कोडिट गीट कटिंग ग्रीर नुकसवाली गीट को छोड़कर, एम०एम० गीट कटिंग ग्रीर सीधी लम्बाई में नुक्सवाली गीटम अथवा कायल्स के भायात के लिए 5,000/- ६० का एक भायान लाइसेस संख्या: पी/एस/8566569/सी/एक्सएक्स/46/जे/33-34, दिनांक 24-1~73 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिप सीमाण्लक निकागी प्रयोजन प्रति भीर मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस भाधार पर आवंदन किया है कि इस लाइसेंस की मृल सीमाण्लक निकासी प्रयोजना प्रति ग्रीर मृद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है। मांगे यह बनाया गया है कि लाइसेंस का बिलकुल उपयोग नहीं किया गया था।

इस तर्क के समर्थन से धावेदक ने एक शपथ-पन्न वाखिल किया है। मैं संनुष्ट ह कि लाइसेंस सख्या पी/एस/8566569/सी/एक्स एक्स/ 46/ज/33-31, विनान 24-1-73 की मूल सीमाशृल्क निकासी प्रयोजन प्रति और सूद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देना ह कि धावेदक का मूल लाइसम रह करने हुए लाइसेंस की धानुलिपि सीमा-शृल्क निकासी प्रयोजन प्रति और मृद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी साहिए।

[सळवा र्षा/द्यार-28/एएम/72/एनयू/एयू/पीबी/डीसीमीणफ] के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियसक

ORDER

Paridabad, the 24th March, 1974

S.O. 1944.—M/s. Raka Cycle Industries 850-Muradpura, Gill Road, Miller Ganj Ludhiana were granted an import licence No. P/S/8566569/C/XX/46/J/33-34, dated 24-1-73 for Rs. 5,000 issued under G. C. R. for the item M. S. Sheet Cutting and defective sheets in straight length or in coils excluding all coated sheet cutting and defective sheet with the Port of Registration Bombay. They have applied for duplicate Custom Clearance Purpose copy and Exchange Control Purpose Copy of the Import licence on the ground that the original Custom Clearance Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of this licence have been lost. It is stated that the licence were not utilised at all.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Custom Clearance Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of import licence No. P/S/8566569/C/XX/46/J/33-34 dated 24-1-73 have been lost and direct that the duplicate licence in Custom Clearance Purpose Copy and Exchange Control Purpose copy should be issued to the applicant in cancellation of the original.

[No. P/R. 28/AM/72/NU/AU/PB/DCCF] K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक ग्रायात-निर्यात का कार्यालय) श्रावेश

बम्बई, 23 जनवरी, 1974

का० ग्रा० 1945.— मर्वश्री स्टेनियम इण्डस्ट्रीज, ग्रगहरी इन्डस्ट्रियल इस्टेट ग्राफ इन्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राफ केत्रम् रांड, योगेण्वरी (इस्टेट), बम्बई को निम्नलिखित शर्नों के ग्रधीन 5 एम एम से कम मोटाई की मी० ग्राग्० मी० ए० णीटम् के भायात के लिए 46,667 स० का एक लाइसेम स० पी/ए/8025795/प्रार/एम एल/38/बी/31-32 दिनांक 16-3-71 स्वीकृत किया गया था :—

''यह लाइसेंस इस गर्त के ग्रधीन जारी किया जाता है कि इसके म्रन्तर्गत स्रायानित माल की सभी मदो का उपयोग लाइसेंस धारी के उस कारलानें में जिस का पता उस भावेदन पक्ष मे विया गया है जिसके मद्दे लाइसेंस जारी किया गया है, और उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है, या प्रन्य किसी भी विनिर्माता एकफ के कारखाने मे संमाधित किया जा सकता है किन्तु उसके किसी भी भाग को किसी भी भ्रत्य पार्टी को बेचने, प्रयोग करने या भ्रत्य किसी भी विधि से प्रयोग करने की भ्रनुमित नही दी जाएगी । लेकिन, किसी भ्रन्य के कारखाने में संसाधित किए गए ऐसे माल का प्रयोग लाइसेसधारी द्वारा लिए गए विनिर्माण कार्यों में ही किया जाएगा। लाइसमधारी लाइसेंस के मद्दे धायासित माल के उपयोग भीर उपयोग का निर्धारित विधि से लेखा रखेगा । प्राधिकारी या किसी द्वारा বিলিডিট্রেল श्चन्य सम्बद्ध प्रोधिकारीको उसके के भीतर प्रस्तुत करेगा।"

- श्रीर ऐिसे लेखे को प्रयोजक मत्यक्ष्वात् उन्हे एक कारण बनाओं मुचना २४० 1/२९/७२[/]ब्राई एण्ड । एस /इन्फ/ ५५३, दिनाक 16-3-1973 यह पृष्ठते हुए जारी की गई थी कि 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेस को श्रायात (नियंत्रण) श्रादेश 1955 की धारा 9 की उप-धारा (ए) तथा (सी) के मनुसार क्या न रद्व कर दिया जाना चाहिए ग्रीर वह इस ग्राधार पर कि लाइसेस जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जारी किया गया था वह उसे पूरा नही करेगा धौर यह कि लाइसेंस सीठए०सी० जिसमें घाडम्बर-पूर्ण खपन दिल्बाई गई है उसे प्रस्तुत करके धोखे से प्राप्त किया गया है भीर यह कि वे उद्योग ग्रायुक्त को जबकि उसके स्टाफ द्वारा उनके कारस्त्राने का निरीक्षण किया गया था सी०ए०सी०की एक प्रक्ति को सत्यापन के लिए प्रस्तृत करने मे ग्रसमर्थ रहे थे ग्रीर यह कि उन्होंने उक्त लाइसेंस के मद्दे उस माल का ग्रायात किया है जो उनके भन्तिम उत्पाद के निर्माण के लिए ग्रावश्यक नहीं ग्रीर यद्यपि यह भी मान लिया जाए कि एम० एस० बी० पी० प्लेट्स से ध्रन्तिम उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है । फिर भी जितनी माला मे उन्होंने भ्रायात किया है वह उनकी स्नावस्थकका से कहीं ज्यादा है।
- 3. उत्पूर्वन कारण बनान्नो सूचना के जवाब में सर्वश्री स्टेनियस इण्ड-स्ट्रीज, बम्बई ने ध्रपने पत्न विनांक 12-9-1973 में विस्तृत विवरण भेजा था और ध्रधोहस्ताक्षरी के साथ व्यक्तिगत मुनवाई के लिए भी कहा था भौर उसके लिए उनके प्रतिनिधि को 5-9-1973 का दिन नियत कर दिया गया था । ध्रपने उपर्युक्त जवाब में ध्रौर व्यक्तिगत सुनवाई के समय, फर्म ने यह नर्क दिया :---
 - (1) कि उन्होंने अपने आयात आवेदन पत्न के साथ सी० ए० मी० की सूल प्रति प्रस्तुत कर दी थी और जब उद्योग आयुक्त के निरीक्षक ने कारखाने का निरीक्षण किया तो उसी की प्रति उपलब्ध नहीं थी । लेकिन उनके उपभोग और उत्सदन का निरीक्षक का दिखा दिया गया था । उनके कारखाने में क्षम सब गड़बड़ होने के कारण सी०ए०सी० की प्रति अस्थानस्थ हो गई थी ।
 - (2) यह कि उन्होंने उस माल का प्रायान किया है जो निश्चित रूप से उनके अस्तिम उत्पाद के लिए आवश्यक है। जहां तक माला का मंबंध है उन्हें अपनी योजना के मुकाबले में अपने निर्माण कार्यों के लिए उनकी अधिक श्रावश्यकता है। आयातित माला की खपत के लिए उनके पास आवश्यक मशीन और क्षमता है।
 - (3) व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई थी कि जब उद्योग आयुक्त के स्टाफ द्वारा मिरीक्षण किया गया उस समय वे इस स्थिति में नहीं थे कि वे सी०ए०सी० को दिखा सकें। चृकि म तो वह उस समय उप-लब्ध थी और न ही उसे बाद में ही विखाया गया था क्योंकि बाद में इसके बारे में उनसे मही कहा गया था।
 - (4) व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उतके द्वारा यह भी बताया गया कि स्रायातित माल के सबध में वास्तविक उपभीग का प्रका नहीं उठता क्योंकि विषयाधीन माल प्रभी तक सीमा-गुरूक द्वारा रिहा नहीं किया गया है।
 - (5) उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्होंने केवल उतनी मान्ना में ही झायात किया है जो उनकी समान्य अध्यम के लिए आवश्यक है भीर जिसके

लिए माल के समाधन के लिए उनके पास पर्याप्त मणी न है।

4 प्रश्नोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भानि जांच करली है श्रीर इस परिणाम पर पहुंचा है कि उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मही श्रीर युक्तियुक्त नहीं है चिक उद्योग श्रायुक्त ने यह प्रमाणित किय। है कि 1969-1970 के दौरान उनकी उपमाण क्षमता 10 से 20 टम से स्रिक्षित नहीं लागी जबकि उत्तर द्वारा श्रायुक्त-मार्च, 1971 के लिए स्वातान आवेदन पत्न दिनांक 29-12-70 के साथ प्रस्तुत किए गए सीर् मीर्म 1969-70 के दौरान उपभोग 132-342 टन मुस्स्य मे रिवार गई है। इस का मनलब यह हुआ कि उन्होंने विषया धीन लाई-। ग्राटन्वरपूर्ण श्रीर भठे उपभोग ने श्राधार पर प्राप्त किए है।

5. ऊपर की कंडिका मे जो कुछ बनाया गया है उसे ध्यान से एखने हुए मधोहस्ताक्षरी सतुन्द है कि विषयाधीन लाइसेन रद्द प्रथवा प्रत्यथा कप से अप्रभाविन किया जाना चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी प्रायान (नियंत्रण) प्रावेश 1955 की धारा 9 उप-धारा (ए) (मी मी) के ग्रन्तर्गन प्रवत्त प्रधिकारो का प्रयोग कर मर्वेश्री स्टेनियस इन्डस्ट्रीज बस्बई के नाम 46,667 रूपये के लिए जारी किए गण लाइसेन स० पी/ए/8025795/आर/एमएल/38/बी/31-32, दिनोक 16-3-1971 को एनवद्गरा रदद करना है।

[संख्या 1/89/72/म्नाई एण्ड एस/एन्फ/106] बी० सी० बनर्जी, उप-मुख्य नियक्तक

OFFICE OF THE CHIÉF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

Bombay, the 23rd January, 1974

S.O. 1945.—A licence No. P/A/8025795/R/ML/38/B/31-32 dated 16-3-71 of the value of Rs. 46,667 for import of CRCA Sheets below 5 mm in thickness was issued to M/s. Stanyous Industries. Aghadi Industrial Estate, Off. Industrial Estate, Off. Caves Road, Iogeshwari (Fast), Bombay subject to the conditions as under:—

"The licence is issued subject to the condition that all items of goods imported under it, shall be used only in the licence holder's factory, at the address shown in the application against which the licence is issued, and for the purpose for which the licence is issued or may be processed in the factory of another manufacturing unit, but no portion thereof shall be sold to any other party or utilised or permitted to be used in any other manner. The goods so processed in another factory shall, however, be utilised in the manufacturing processes undertaken by the licensee The licensee shall maintain a proper account of consumption and utilisation of the goods imported against the licence in the prescribed manner and produce such account to the sponsoring authority or any other concerned authority within such time as may be specified by such authority".

2. Thereafter, a show cause notice No. 1/89/72/I&S/Enf/553 dated 16-3-1973 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licence in their favour should not be cancelled in terms of sub-clauses (a) and (cc) of Clause 9 of the Imports (Control) Order, 1955 on the grounds that the licence will not serve the purpose for which it was issued and the licence has been obtained fraudulently by producing C A O. showing inflated consumption and that they were not able to produce a copy of the C A C to the Industries Commissioner for verification when the factory was visited by his staff and that they have imported against the said licence, goods which may not be required for the

manufacture of their end product and the quantity imported is far in excess of their requirement even if it is assumed that the end products can be manufactured from the M.S.B.P. Plates

- 3 In response to the aforesaid show cause notice, M/s Stanyous Industries, Bombay had by their letter dated 12-9-1973 furnished a detailed explanation and had also asked for personal hearing with the undersigned which was allowed to their representative on 5-9-1973. In their said reply and it the time of personal hearing, the firm contended -
 - (1) That they had submitted the original copy of the CAC with their import application and that copy of the same was not traceable when the Industries Commissioner's Inspector visited their factory for inspection. But their consumption and production was shown to the Inspector. Copy of the C.A.C. was misplaced as there was Labour Union trouble in their factory.
 - (2) That they have imported the material which is definitely required for the manufacture of their end products. As far as the quantities are concerned they require for their manufacturing activities more than as per their plan. They have the necessary machineries and capacity to consume the quantity imported.
 - (3) At the personal hearing it was confirmed by them that at the time of visit of the Industries Commissioner's staff they were not in a position to show CAC as it was not traceable nor was it shown later on as the same was not asked thereafter.
 - (4) It was also pointed out by them at the personal hearing that the question of actual consumption in respect of the imported material does not arise because the material in question has not yet been released by the customs
 - (5) They also confirmed at the personal hearing that they have imported only such quantity as is required for normal consumption for they have got sufficient machinery installed for processing the meterial.
- 4. The undersigned has carefully examined the said representation and has come to the conclusion that their explanation is not correct and convincing as the Industries Commissioner has certified that during the period 1969-70 then consumption capacity would not be more than 10 to 20 tons whereas the CAC submitted with their import application dated 28-12-70 for AM-1971 shows the consumption during 1969-1970 as 132-342 tons. This means that they have obtained the hence in question on the basis of inflated and false consumption
- 5. Having regard to what has been stated in the preceeding paragraph, the undersigned is satisfied that the licence in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore, the undesigned, in exercise of the powers vested in him under clause 9 sub-clauses (a) and (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licence No. P/A/8025795/R/ML/38/B/31-32 dated 16-3-1971 for Rs. 46,667 issued in favour of M/s. Stanyous Industries, Bombay.

[No 1/89/72/I&S/Enf/106] B C BANERJEF, Dy. Chief Controller,

मुख्य नियत्रक, स्रायान-निर्यात का नार्यालय स्रादण

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1974

कारणी 1946.—विस्टेट ट्रेडिंग कारणीरेशम झाफ देखिया लिरु, नई दिल्ली को रेज-क्लाइमर स्पेयमें के झायात के लिये राज्य व्यापार निगम/सुकाब समझौते के झधीन 5,20,000/-क्पये (पाच लाख बीस हजार रुपये माझ) मूल्य का एक झायान लाइसेंस संरु जी/टी/24/3969 दिनाक 27-4-74 प्रदान किया गया था । उन्होंने लाइमेन्स की प्रनृतिर्णि (दोनों प्रतियां) जारी करने के लिए इस साधार पर आवेदन किया है कि मल लाइमेंस (दोनों प्रतियां) उन से खो गया/ग्रस्थानस्थ हो गया है । लाइसेंस (दोनों प्रतियां) उन से खो गया/ग्रस्थानस्थ हो गया है । लाइसेंस्थारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस्थ रिर्स भी धनराणि को उपयोग किए बिना ही खो गया। ग्रस्थानस्थ हो गया है ग्रीर वह किसी भी सीमा ण्या प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं विया गया था।

अपने तर्क के गमर्थन में आवेदक ने एक शपथ पस्न वाँखिल किया है। अधोजस्माक्षरी सनुष्ट है कि मूल लाइसेंस संव जी/टी/24/3969 दिनाक 27-4-74 (दोनो प्रतियां) खो गया/प्रस्थानस्थ हो गया है और निदंश देती है कि उसकी अनुलिप प्रति (दोनो प्रतियां) उनको जारी की जानी चाहिए । मूल लाइसेंस (दोनो प्रतियां) रह्द किया जाना है । लाइसेंस की अनुलिप प्रति श्रलग से जारी की जा रही है

का० **प्रा० 1446.**— संख्या एस० टी० सी०/ग्राई० ग्रार० एस० ए० मी०-2/74-75 ग्रार० एस० सेल/1219

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 19th July, 1974

S.O. 1946.—The State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi were granted an Import Licence No. G/T/2413969, dated 27-4-74 under STC/Sukab Agreement for the Import of Raise climber-Spares etc. valued at Rs. 5,20,000 (Rupees Five Lakh and Twenty Thousand only). They have requested for the issue of Duplicate copy (both copies) of the licence on the ground that the Original licence (both copies) has been lost/misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence lost/misplaced after the utilization of Rs. Nil and the licence was not registered with any customs authorities.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Original Licence No. G/T/2413969, dated 27-4-74 (both copies) have been list/misplaced and directs that a duplicate copy (both copies) of the said licence should be issued to them. The Original Licence (both copies) is cancelled. Duplicate copy of the licence is being issued separately.

fF. No. STC/IRMAC-2/74-75/RM Cell/1219]

प्रादेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1974

कारणार 1947 — वि प्रोपेक्टम एंड इक्षिय मेंटम कार्पोरेशन प्राफ इडिया सिर, नई विल्ली को मोवियत समाजवादी गणतव सुष में 39,313 रुपये मूल्य के प्रयोगशाला परीक्षण उपस्कर, नियन्नण घानक और प्रकाणीय प्रोजिंगो, वैश्वानिक उपकरणो और धानु परीक्षण मणीनरी के प्रायान के लिए एक लाइसेंस संख्या जी/टी/2397659, दिनांक 31-1-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की प्रनृतिपि जारी करने के लिए इस ग्राधार पर प्रावेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/ग्रस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंस धारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस किसी भी पनन से पंजीकृत नहीं कराया गया है। उन्होंने लाइसेंस का बिलकुल भी उपयोग नहीं किया है।

ध्रपने वांबे के समर्थन में घाबेदक ने एक णपथपत्र दाखिल किया है। ध्रधोहरूनाक्षरी संनुष्ट है कि लाइसेस संख्या जी/टी/2397659, दिनांक 31-3-73 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है धौर निदेश देती है कि इसकी ग्रनुलिपि प्रति उनको जारी की जानी चाहिए। लाइसेस की मूल प्रति एनदद्वारा रह की जाती है।

लाइसेंस संख्या जी/टी/2397659, विनाक 31-1-1973 की प्रनृलिपि धलग से जारी की जा रही हैं।

> [सन्त्रा एमटीसी/यूएमएमग्रार-27/72-73म्बारएमसैल/1223] कुमारी एस० कें० उस्मानी, अप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 1974

S.O. 1947.—The Projects & Equipments Corporation of India Ltd., New Delhi were granted licence No. G/T/2397659, dated 31-1-73 for the import of Laboratory Testing Equipment, Control Measuring and Optical Instruments, Scientific Apparatus and Metal Testing Machinery from USSR to the value of Rs. 39,313. They have requested for the issue of Duplicate Exchange Control Copy of the above licence on the ground that the Original Exchange copy of the above licence have been lost/misplaced. It has been further reported by the licensee that the licence has not been registered with any port. They have not utilised the licence at all.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Original Exchange copy of the Licence No. G/T/2397659, dated 31-1-73 has been lost and direct that Duplicate Exchange copy of the said licence should be issued to them. The Original copy of the licence is hereby cancelled.

The duplicate copy of the licence No. G/T/2397659, dated 31-1-73 is being issued separately.

[F. No. STC/USSR-27/72-73/RM Cell/1223] MISS S. K. USMANI, Dy. Chief Controller

मावेश

नई विल्ली, 19 जुलाई, 1974

का०ग्रा० 1948. — सर्वेश्री श्राचार्यं इलैक्ट्रोनिक्स लि०, धाट रोइ, नागप्र--440002 मैटम के विनिर्माण टेमीविजन प्रभान उपस्करों के भाषात के लिए 32,000 मुल्य का एक ग्रायान लाइसेंस सं० पी/मी/2064652/ग्रार/के के/45 एच/33-31/सी जी-3, दिनांक 3-10-72 प्रदान किया गया था। उन्होने उक्त लाइसेंस की ग्रनुलिपि प्रति के लिए इस ग्राक्षार पर ग्रावेदन किया है कि मूल लाइसेंस (लाइसेंस की कैंवल सीमाश्लक निकासी प्रति) सीमाणुरूक कार्यालय, अस्बर्ध में पंजीकृत कराने के बाद धीर 17,429.80 रूपये (मनरह हजार चार सौ उन्सीस रूपये ग्रम्मी पैसे) मान्न का भ्राणिक उपयोग करने के बाद खो गई/नष्ट हो गई है । श्रव श्रनुलिपि प्रति की श्रावण्यकता 14,570 स्पर्य की ग्रेष धनराणि को पूरी करने के लिए है। इस तर्क के समर्थन में ग्रावेदक ने एक शपथ पत्न दाखिल किया है।

नदनुसार, मैं सनुष्ट हं कि मूल लाइसेंस (लाइसेंस की सीमाणुस्क निकासी प्रति) खो गई है। इस लिए यथासणीधिन श्रायान (नियंत्रण) श्रादेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (मी सी) द्वारा प्रदत्त श्रिष्ठकारों का प्रयोग करने हुए सर्वेश्वी श्राचार्य इनैक्ट्रोनिक्स लि०, नागपुर को जारी किया गया उक्त लाइसेंस सं० पी/मी/2064652 श्रार/केके/45/एख/33-34/सी जी-3, दिनांक 31-10-1972 एनद्द्वारा रद्व किया जाता है।

[सन्त्या 6(28)/72-73/मी० जी० 3/1923] एस० ए० पोषन उप-मुख्य नियंत्रक, कृते मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, 19th July, 1974

S.O. 1948—M/s Acharya Flectronics Ltd., Ghat Road Nagpur-440002 were granted an import licence No P/C/2064652/R/KK/45/H/33-34/CG III., dated 31-10-1972 for Rs 32,000 for the import of capital equipments for the manufacture of TV Sets. They have applied for a duplicate copy of the said licence on the ground that the original licence (Customs copy of the licence only) has been lost destroyed after having been registered with Customs House at Bombay and utilised partly for Rs 17,429.80 (Rupes Seventeen thousand four hundred and twenty nine and paise eighty). The duplicate copy now required is to cover the balance of Rs 14,570. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit.

I am accordingly satisfied that the original licence (Customs copy of the licence) has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said licence No P/C/2064652/R/KK/45/H/33-34/CG. III dated 31-10-1972 (Custom copy only) issued to M/s Acharya Electronics Ltd., Nagpur, is hereby cancelled.

[F. No. 6(28)/72-73/CG III/1923]

S. A SESHAN, Dy. Chief Controller

for Chief Controller

श्रीग्रोगिक विकास, विज्ञान तथा श्रीद्योगिकी मन्नालय

(श्रीबागिक विकास विभाग)

भारतीय मानक सम्था

नर्द दिल्ली, 15 जुलाई, 1974

कार भार 1949. —समय समय पर समांधित भारतीय मानक सम्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रथिकारों के प्रनुसार नीचे श्रनगुची में जिस IS 2477—1970 के व्यौरे दिए गए हैं उसके उपबन्धों के में मानक चिन्ह के उपयोग में गित लाने के उद्देश्य में परीक्षात्मक रूप में मणाधन किया गया है। इस सणाधन के द्वारा भारतीय मानक के श्रनुरूप बने मान की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़िया और यह सणोधन तुरत्त ही लाग हा जाएगा।

ग्रनसूची

त्रम भारतीय मानक की सख्या धौर णीर्षक जिसके उपबन्धा में सणाधन किया गया भारतीय मानक के उपबन्धों में किए गए सणोधन का विधरण सख्या

1 2 3

1. IS 2477-1970 कथे पर रखकर हाथ से खलाये जाने वाले रोटरी धृलन खण्ड 1.2 1 को सणोधिल करके निम्नलिखित रूप दिया गया है - यत की विश्विष्टि (पहला पुनरीक्षण) जिल्लोधर जड़न के साथ एक वक्ष पढ़ी लगाई जा सकती है जिसके द्वारा मणीन बड़े भाराम के साथ वक्ष की सहायता से टिकी रहती है।'

[म०मी० एम० डी०/134]

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY (Department of Industrial Development) INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 15th July, 1974

S 0.1949—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modification to the provisions of IS: 2477-1970, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This modification shall come into force with immediate effect:

SCHEDULE

SI No and Title of Indian Standard, the Provisions
No. of which have been Modified

1 2 3

1. IS: 2477-1970 Specification for hand rotary duster, shoulder mounted type (First Revision)

Clause 12 I has been amended to road as follows:—
"A breast plate may be fitted with the blower assembly so that the machine may rest comfortably on the chest of the operator"

[No CMD/13.4]

कार्थार 1950— समय समय पर संशाधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) बिनियम, 1955 के विनियम 3 के उनियम (1) के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रमुखार नीचे प्रमुखी में जिस IS 560—1969 भारतीय मानक के ब्यौर दिए गए है उसके उपबन्धों में मानक चिन्ह के उपयोग में गिल तान के उद्देश्य के परीक्षात्मक रूप में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के ब्रारा भारतीय मानक के अनुरूप बने माल की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह संशाबन तुरन्त क्षी लागू हो जाएगा।

2090 THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 3, 1974/SRAVANA 12, 1896 PART II-ग्रनुसुची भारतीय मानक के उपबन्धों में किए गए मशोबन का विवरण क्रम भारतीय मानक की भुख्या और शीर्षक जिसके उपबन्धों में सणोधन किया गया संख्या 1. IS 560-1969की ० एच० सी०, तकनीकी और परिष्कृत की विशिष्टि (दूसरा पैकिए में सब्धित खण्ड 4.1 को सशोधित करके निम्नलिखित अप पुनरीक्षण) विया गया है "यह पदार्थ ग्राहक ग्रीर सब्नायर के बीच हुए समझौते के भनमार भागे बनाए प्रकार के साफ सुखे धारको में बद किया जाए ये धारक मृद्र इस्पात, टिनप्लेट, फाइबरबोर्ड या लकडी के बने पालीइथाइलीन का ग्रस्तर लगे हो, या बिट्मेन सिझाए श्रीर पोली-इयाइलीन के ग्रस्तर लगे ग्रथवा श्रिना ग्रस्तर लगे बोहरे हैसियन बोरे हो, या ऐसे दोहरे हैसियन 300 प्रा० वाले औरे हो जिनके दोनो फ्रांर हर परत पर 90 ग्रा॰ प्रति वर्ग मीटर बिटुमेन से 60 ग्रा० का काफ्ट कागज चिपकाया हुआ। हा श्रथवा कम से कम 300 गेज मोटे पोलीइथाडलीन के प्रस्तर लगे उपचारित ए-ट्विल वाले [स॰ सी॰ एम॰ डी॰/134] एस० के० सेन, महानिवेशक S.O. 1950.—In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation (4) of regulation 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, modifications to the provisions of IS: 560-1969, details of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have tentatively been made with a view to expediting the use of the Standard Mark, without in any way affecting the quality of goods covered by the relevant standard. This notification shall come into force with immediate effect: SCHEDULE

		SCHEDOLE
Sl. No.	No. and Title of Indian Standard, the Provisions of which have been Modified	Particulats of the Modifications made to the Provisions
	2	3
1.	IS: 560-1969 Specification for BHC, technical and refined (Second Revision)	The existing clause 4.1 pertaining to packing has been modified to read as follows: "The material shall be packed in neat and dry containers made of mild steel, thiplates, fibreboard or wood lined with polyethylene liner, or in double hessian bags with bitumenized and with or without polyethylene liner or in double hessian bags 300 g on both sides interlined with 60 g kraft paper bonded with 90 g/m* of bitumen on each run or in treated A-twill jute bags with a polyethylene liner of at least 300 gauge as agreed between the purchaser and the supplier".
		

[No. CMD/13:4]

S. K. Sen, Director General

नर्ष दिल्ली, 16 **जु**लाई, 1974

कार आर 1951.— भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्छ) थिनियम 1955 के विनियम 1 के अनुसार भारतीय मानक सम्था द्वारा श्रधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम 3 के उपविनियम (1) क प्रनृसार प्राप्त श्रधिकार के श्रधीन यहा श्रनुसूची में दिए भारतीय मानको के संशोधन जारी किए गए है .—

	किए गए है	3 11 3 11 11 11 (1)	म न्स् वो	ार के अधान यहा अनुसूचा म ।दए, भारताय	111111	1 7	संसायन
क्रम सं स् था	• 5.1	जिम राजपन्न में भारतीय मा तैयार होने की सूचना छपी थी उसकी स० श्रीर दिनांक	नक्त सणोधन की सख्या श्रौर दिनाक	सणाधन का सक्षिप्त विवरण	 लागू	होने क	 ो तिथि
1	2	3	4	÷ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	, .	6	
1.	IS · 2 2 4—1965 मामान्य कार्य के लिए फाउड़ियों में प्रमुक्त कच्चे लोहे (कोक) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	त दिनाक 9 स्रप्रैल 1966	स० 1 दिसम्बर 1972	खंड ए—− ।. 1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है	1	विसम्बर	1972
2	.IS . 273–1961 कृदाली ग्रीर धुरमुस की विभिष्टि (पुन- रीक्षित)		स० 3 दिसम्बर 1972	सारणी 1 फ्रौर खण्ड 6 , 3 के स्थान पर नई सारणी श्रौर खण्ड दिए गए हैं ।	1	दिसम्बर	1972

_ I	2	3	4	5	6	
3.	IS: 375-1963 मुख्य कने- क्यान भ्रीर सहायक वार्यारण के लिए चिन्ह नथा व्यवस्था (पुनरीक्षित)	विनांक 12 धक्तूबर	सं० I नवस्थर 1972	(पृष्ठ 7, खंड 4.1.1)—खंड के श्रन्त में निम्नलिखित वाक्य औड़ लीजिए :—→ 'ऐसी स्थितियों में निर्माता कनेक्शनों पर पहचान के लिए स्पष्ट निशान, लगाएगा।'	े 1 नेबम्बर	1972
4	IS: 484-1970 म्नेहक पदार्थों के लिए एलुमिनियम स्टियरेट की विमिष्टि (पहला पुनरीक्षण)		म० 1 दिसम्बर 1972	(पृष्ठ 3, खण्ड 0 , 4 पॅक्ति 1) 3 . 3 . 2 के स्थान पर बी 3 . 2 कर लीजिए ।) दिसम्बर	1972
5.	IS . 693-1965 वानिमासूत कैम्ब्रिक रोधित केबलों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	एस०ग्रो० 2037 दिनांक 9 जुलाई 1966	सं० 2 जनवरी 1973	सारणी 2 का संशोधन किया गया है।	1 जनथरी	1973
6.	IS: 1554 (भाग 2)— 1970 पी वी मी रोधित (भारी इ्यूटी) बिजली के केबलों की विशिष्टि (पुन- रीक्षित) भाग 2 3 3 कि वो से 11 कि वो तक की कार्य- कारी बोल्टना के लिए	एस०झो० 3542 विनांक 25 सितस्बर 1971	स० 1 दिसम्बर 1972	(1) खंड 0 3 के नीचे वर्तमान ध्रनीपचारिक सारणी के स्थान पर नई सारणी दी गई है। (2) खण्ड 1, 1, 4. 2, 4. 3, 5. 4. 1, 7. 2, 7 4. 2 8. 3 भीर 10. 15 का संगोधन किया गया है। (3) खण्ड 1. 1, 1 के नीचे की टिप्पणी के स्थान पर नई टिप्पणी दी गई है। (4) खण्ड 4. 5 के ध्रन्त में एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है। (5) (पूष्ट 8, खण्ड 5. 4. 2) — को हटा दीजिए। (6) (पूष्ट 10, सारणी 3)— सद एपर लगा (*) तारा चिन्ह और सारणी के नीचे दिया मंतब्य हटा दीजिए।	1 दिसम्बर	1972
	IS: 1667 → 1971 टॉफी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)		सं० 1 जनवरी 1973	[पृष्ठ 6, सारणी 1, स्तम्भ 4, क्रमसंख्या (7) के सम्मुख]—2.0 के स्थान पर 3.0 कर सीजिए।	1 जनवरी	1973
	IS: 1714-1460 पणुत्रों के श्राष्ट्रार में खली की बानगी लेने तथा परीक्षण की पञ्चतिया	एस०भ्रो० 570 दिनांक 18 मार्च, 1971	सं० 4 जनयरी 1973	(1) खण्ड 5.1 का संशोधन किया गया है। (2) खण्ड 10.2 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है।	1 जनवरी	1973
1	IS: 1753-1967 केबलों के लिए एलुमिनियम चालकों की विणिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ्झां० 3734 दिनांक 21 श्र क्तूब र 1967	म ० 3 दिसम्बर 1972	 (1) सारणी 2 का संशोधन किया गया है। (2) खण्ड 12.1.1 के स्थान पर नया खण्ड विया गया है। (3) खण्ड 12 2.1 का मशोधन किया गया है। 	1 दिसम्बर	1973
	IS . 1849–1967 चूने की भट्टियों के डिजाइन नथा सस्यापन की रीनि संहिना		म० । विसम्बर 1972	प्रथम मुख पृष्ठ, पृष्ठ 1 भ्रौर 3 में दिए शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक दिया गया है।	1 दिसम्≇र	1972
	IS: 1942 1968 पणु घाहार पूरक के रूप में हक्की के चूरे की विणिष्टि		स० 1 दिसम्बर 1972	खण्ड एफ 2.1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है ।	1 दिसम्बर	1972
नुः ;	IS : 2082–1965 भंडारण- मा स्वचासित बिजली के पानी के श्रीटरों की विशिष्टि (पुन- रीक्षित)		स० 2 जनवरी 19 7 2	(1) खण्ड 4 1 1, 4.2.1 क्योर 5.5 कें स्थान पर नए खण्ड दिए गए हैं। (2) पृष्ट 7 पर (‡) चिन्ह वाली टिप्पणी कें स्थान पर नई पाद टिप्पणी दी गई है।	। जनवरी	1973

1		3	4	5	6
				(3) खण्ड 4 1.2, 4.2 9.1, 6.1, 9.3.5, 9.3.6, स्रोग सी~1.2.2 का संगोधन किया गया है।	
				(₁) [पुष्ठ 8 (*) नाराकित पाद्र–ाटप्पणी] इसमें (पुतरीक्षित) के स्थान पर (दूसरा पुतरीक्षण) कर लीजिए ।	
				(5) नए खण्ड 8, 1, 3 झीर 9, 1, 2, 2 जोडे गए हैं।	
13	. IS: 2148-1968 बिजली के उपकरणों के ज्वालासह खोल की विशिष्टि (पुनरोक्षित)	=	म० 2 जनवरी 1973	 (पृष्ठ 12, सारणी 2 सी, टिप्पणी 1 पंक्ति 2) "threads of six" के स्थान पर "threads or six" कर लीजिए। 	1 जनवरी 1973
				 श्राकृति 1 के तीचे टिप्पणी 2 के स्थान पर नई टिप्पणी दी गई है। 	
				 ब्राकृति 2 के स्थान पर नई ब्राकृति दी गई है 	1
				4 आकृति 3 के नीचे टिप्पणी 1 भौ र खण्ड	
				4. 2. 1. 3, 5. 1. 1, 5. 1. 3, 5. 3. 3 4,5. 9 फ्रीर 10. 1 का मंशोधन किया गया है :	
				5. (ণুষ্ঠ 32 দ্মান্ত নি 14)—	
				"A' = flame proof terminal box" "B' = flame proof terminal box	
	JS: 2151-1962 मक्का के मंकुर की खली की विणिष्टि	एस० झो० 3447 विनोक 17 नवस्यर 1962]	सं० 1 जनवरी 1973	 खण्ड बी-2, 1 का समोधन किया गया है। <li 1="" के="" खण्ड="" गी-2,="" दिया<br="" नया="" पर="" स्थान="">गया है। 	1 जनवरी 1973
15.	IS: 2347-1966 घरेल प्रेगर कुकर की विशिष्टि पुनरीक्षित	एस० ग्रो० 469 दिनौक 11 फरवरी 1967	सं० 1 दिसम्बर 1972	नया खण्डे 5,2,4 ओड़ागया है।	1 दिसम्बर 1972
16.	IS: 2386 (भाग 4)-1963 कंक्रीट की मिलावे (रोड़ियों) की परीक्षण पद्धतियां: भाग 4 मशीनी गुण	विनांक 30 मई	सं० 1 नवस्वर 1972	खण्ड 6.7 के नीचे समीकरण चिन्ह के स्थान पर नया समीकरण चिन्ह लगा विया गया है।	1 नवम्बर । 972
17-	IS: 2516 (भाग 2 प्रतुमाग 1)-1966 ए सी घारा क्रेकर की विणिष्ट, भाग 2 परीक्षण प्रतुमाग 1, 1000 वोस्ट मे प्रमाधिक वोस्टता वाले	एम ः भो ० 1759 दिनांक 20 म ई 1967	सं० ८ जनवरी 1973	 (पृष्ठ 15, खण्ड 6.8.1.3, पिनत 2)— "Recovery" के स्थान पर 'rated" कर सीजिए। खण्ड 9.3 (की) के स्थान पर नया आण्ड विया गया है। 	1 जन वरी 1973
18.	IS : 2838-1964 सामान्य कार्यों के लिए स्टोनवेयर के	एस० घो० 2033 विनांक 17 जुलाई	मं० 1 विसम्बर 1972	खण्ड सी 4.1 के स्थान पर नया खण्ड विया गया है।	1 विसम्बर 1972
19.	धारको की विणिष्टि । I1 : 2839∼1964 भौद्योगिक स्टोनवेयर की विणिष्टि ।	1965 एस० मो० 2729 दिनोक 4 मितम्बर 1965	सं० 1 दिसम्बर 1972	खण्ड मी-4. 1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है।	1 विसम्बर 1972
2 0.	IS: 2842-1964 इस्पात तैयार करने के कार्यों के लिए बुनियादी कच्चे लोहे (कोक) की विशिष्टि।	एस० घो० 1152 दिनांक 10 घरैन 1965	सं० 1 मवस्थार 1972	खण्ड ए-1.1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है।	ı विसम्बर 1972

I 	2	3			6
21.	IS : 3148-1967 धातु की खिसकथां (स्लाइट) घट- खनियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।	एस० ग्रो० 520 दिनांक 10 फरवरी, 1968	सं० ! दिसम्बर 1972	 (पृष्ठ 10, खण्ड 9.1, पंक्ति 3) मैं— 'Appendix H' के स्थान पर 'Appendix J' कर लिया जाए (पृष्ठ 22, परिणिष्ट एन में)— 'Appendix H' के स्थान पर 'Appendix J' कर लिया जाए धौर खण्डों की संख्या उसी हिसाब से बदल ली जाए। (पृष्ठ 7, खण्ड 5.1 (जी)—धंत में निम्त-लिखन नई अपेक्षा जोड लीजिए: '(h)' Resistance to deform tion of me 	1 दिसम्बर, 1972 ~ onth slider
				 नया खण्ड 5.1.7 जीवा गया है। नया परिणिष्ट एच खण्ड जी-3.1 के बाद जोड़ा गया है। 	
22.		एम० ग्रो० 2246 दिनाक 30 जुला ई , 1966	सं० 1 दिसम्बर, 19 7 2	यर्समान खण्ड 8 2 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है स्रौर पाद-टिप्पणी हटा दी गई है ।	1 दिसम्बर, 1972
23.	IS: 3347 (भाग 4 अनुभाग 2)-1967 ट्रांमफामंर की पोर्सलेन की बुणबंदियों के माप: भाग 4, 24 कि नो तक की बुणबंदियों के लिए खण्ड 2 धानु के पुर्जे।	एस० ग्रों० 2766 दिनांक 10 श्रगम्त, 1968	र्मं० 1 दिसम्बर, 1972	नयालाण्ड 1,1,1 जोडागयाहै। 	ा दिसम्बर, 197
2 4.	IS: 3347 (भाग 5, अनुभाग 2)-1967 द्रांसफार्मर की पोर्सलेन सुशबदियों के माप: भाग 5, 36 कि वो तक की सुशबदियों के लिए खण्ड 2 धातु के पुजें।	एस० भ्रो० 2766 विनांक 10 भ्रगस्त, 1968	मं० 1 नवम्बर, 1972	(पृष्ट 6 में 16, खण्ड 3 भीर 4)—— 36 / 250 बृणभदी रेटिंग के लिए धातु के पुर्जी का उल्लेख जहां भी भाया है, हटा दीजिए ।	1 नवम्बर, 1972
2 5.	IS: 3400 (भाग 2)-1965 वस्कनीकृत रबड़ की परीक्षण पदमियां भाग 2 कठोरता।		सॅं० 1 नवम्बीर, 19 7 2	खण्ड 5.2 के स्थान पर नमा खण्ड दिया गया है।	1 नवम्बर, 1972
26.		एस० भ्रो० 211 दिनांक 21 जनवरी, 1967	मं० 1 जनवरी, 1973	खण्ड 2.1 (मी) 3.3 2 और 3 3.3 का संशोधन कियागया है।	1 जनवरी, 1973
27.	IS : 3626–1966 वर्षे कायल वाले लिपटवा रस्सो की विणिष्ट	षम० ग्रो० 3818 दिनांक 17 दिसम्बर, 1966	मं० 2 नवम्बर, 1972	 खण्ड 3. 2, 9. 2 और सारणी 3 का संगोधन किया गया है। (पृष्ठ 5, खण्ड 8, शीर्षक में)—वर्तमान णीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित कर लीजिए। 	1 नवम्बर, 1972
				''8. Tests on wires before maki 3. सारणी । के तीचे की टिप्पणी स्थान पर नई टिप्पणी दी गई है।	ng''
28.	IS : 3959–1966 देह के पाउडरों की विशिष्टि ।	एस० ग्रो० 1972 दिनांक 10, जनवरी 1967	मि० 1 जनवरी, 1973	 (पृष्ठ 4, खण्ड 3.3)— इस खण्ड को पाद टिप्पणी सहित हटा दीजिए और वर्तमान खण्ड 3.4 का कर्माक बदलकर 3.3 कर लीजिए। खण्ड ए-8.2.1 और ए-8.2.2 का संगो- धन किया गया है। 	
				 नए खण्ड 0 3 और 4.2.1 असम: खण्ड 0.2 और 4 2 के बाद जोड़े गए हैं और 	

. 1	2	3	4	5	6
29	IS : 4039 (भाग 2) - 1968 निर्यात के लिए मिले-मिलाए कपड़ों की पैकेजबंबी करने की मंहिता : भाग 2 वायुयान मे जाने योग्य पैकेजबंदी ।		सं० 1 जनवरी, 1973	वर्समान खण्ड 0 3 तथा 4.2.1 के कमांक बदलकर 0.3.1 झौर 4.2.2 कर दिए गए है। 4. नया खण्ड 1.1.1 जोड़ा गया है। खण्ड 2.1.1, 3.1 झौर 3.2 का संगोधन किया गया है।	1 जनवरी , 1973
30	IS: 10981967 चृना पोल्मोलाना मिश्रण की विशिष्टि		मं० । दिसम्बर, 1972	खण्ड 3 . । के बाद एक नई टिप्पणी ओड़ी गई है।	1 दिसम्बर, 1972
31.	IS: 4288-1967 1100 बोल्ट में मनीधक बोल्टना की रेटिंग बाले पी बी मी रोधित भ्रौर पी बी सी खाल बाले टोस एलूमिनियम चालको बाले केबल	दिनांक 10 फरवरी, 1968	मं० 1 जनवरी, 1973	 खण्ड 4.2, 4.3 भीर 8.4 के स्थान पर नए खण्ड दिए गए है। (पृष्ठ 9, खण्ड 7 1) श्रंतिम नात्य को हटा दीजिए। 	1 जनवरी, 1973
32-	IS: 5020-1969 हेमाटाइट कच्चे (पिंग) लोहे की वि- गिष्टि ।		सं० 1 नवस्बर, 1972	(पुष्ट 5, श्वण्ड ए-1.1 पंक्ति 2)~- blast furnace के स्थान पर furnace कर लीजिए।	1 नवम्बर, 1972
33.	IS: 5021—1969 ग्रम्लप्रितिः रोधो उच्च मिलिकांन कच्चे (पिग) लोहे की विभिद्धि।		स ० 1 नवस्त्रर, 1972	(पृष्ठ 5, खण्ड ए-1.1 पंक्ति 2) 'blast furnace'' के स्थान पर ''furnace'' कर सीजिए।	1 नवस्कार, 1972
34.	IS: 5038-1969 घरेलू रेफीजेरेटरों के लिए बर्फ जमाने की ट्रेकी विशिष्टि।		मं० 1 विसम्बर, 1972	सारणी 1 का मंशोधन किया गया है।	1 दिसम्बर, 1972
35.	IS: 5297-1969 पर्यक्लो- रोइषाइलीन (टेट्राक्लोरोइथा- इलीन), तकनीकी की विणिष्ट	एस० घ्रो० 1236 विनांक 4 घ्रप्रैल, 1970	सं० 1 जनवरी, 1973	सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1 जनवरी, 1973
36.	IS: 5519-1969 भूरे मोहे कीं इली चीजों की बिना छूट घानी नापों में घट बढ़।		स० 1 नवम्बर, 1972	मारणी 2 और 3 का मंत्रोधन किया गया है।	1 नवस्बर, 1972
	IS: 5571-1970 खमरनाक स्थानो के लिए बिजमी के उपकरणों के चुनाव की मार्ग- वर्शिका।		सं० 1 विसम्बर, 1972	खण्ड 3 2.1 भौर 3.3.1 का संशोधन किया गय है।	ा 1 दिसम्बर, 1972
	IS : 5591—1969 क्लोरो- वेजीन की विशिष्टि ।	एस ः प्रो ० 3015 दिनाक 14 श्रगस्त, 1971	सं० 1 जनवरी, 1973	सारणी 1 का संगोधन किया गया है।	1 जनवरी, 1973
	IS . 5680–1969 चिकित्सा उपयोग के लिए रबड़ की नली की विशिष्टि ।		सं० 1 विसम्बर, 1972	खण्ड 4, 3, 1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है।	1 विसम्बर, 1972
:	IS. ६० ४८–1970 गर्म डुबाऊ छूटने वाले ग्रम्थायी सक्षाप्प रोक पदार्थं की विज्ञिष्टि।	एस० मो० 398 दिनाक 5 फरवरी, 1972	मं० 1 दिसम्बर, 1972	खण्ड 0.2, 0.3, 2.1.2 भीर सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1 दिसम्बर, 1972
1	IS:62281971 अञ्चा निकलने वाले मुर्गीके झंडों के परीक्षण यंत्रकी विभिष्टिः।		स० 1 जनवरी, 1973	'norrow' के स्थान पर 'narrow' कर लीजिए।	1 जनवरी, 1973

इन भारतीय मानकों की प्रतियां, भारतीय मानक संस्था, 9 बहाबुरणाह जफर मार्ग, नई दिल्ली और उसके शाखा कार्यालयों, (1) 534 सरदार बल्लभ भाई पटेल रोड, बम्बई-1 (2) चौरगी ऐप्रोज, कलकत्ता-13 (3) जनरल पैटर्म रोड, मद्रास-2 (4) 117/418 बी सर्वोदयनगर कानपुर (5) 5-9-201/2 चिरागधाली क्षेत हैदराबाद-1 (6) 'साधना' नूर मोहम्मद शेख मार्ग, खानपुर महमदाबाद-1 (7) एफ व्लाक यूनिटी बिल्डिंग, नर्रामहराज स्ववायर बगलीर-2 भीर (8) बी मी भाई बिल्डिंग (तीसरी मंजिल) गांधी मैदान, पूर्वी पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। [मैं० सी० एम० की०/13:5]

New Dolhi, the 16th July, 1974

S.O. 1951. -In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

SCHEDULE

SI. No.	No and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notifi- cation in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the Amendment	Brief particulars of the Amendment	Date from which the Amendment shall have effect
1	2	3	4	5	б
1.	IS: 224-1965 Specification for foundry pig iron (coke) for general purposes (Second Revision)	S.O. 1081 dated 9 April 1966	No. 1 Dec 1972	Clause A-1.1 has been substituted by a new one	1 Dec 1972
2.	IS: 273-1961 Specification for picks and beaters (Revised)	S.O. 1893 dated 12 Aug 1961	No. 3 D∞ 1972	Table 1 and Clause 6.3 have been substituted by new ones.	1 Dec 1972
3.	IS: 375-1963 Marking and Arrangement for switchgear bus-bars, main connections and auxiliary wiring (Revised)	S.O. 2877 dated 12 Oct 1963	No. 1 Nov 1972	(Page 7, Clause 4.1.1) — Add the following sentence at the end of the Clause: 'In such cases the manufacturer shall clearly identify the connections.'	1 Nov 1972
4.	IS: 494-1970 Specification for aluminium stearate for lubricants (First Revision)		No. 1 Dec 1972	(Page 3, clause 0.4 line 1) Substitute 'B-3.2' for '3.3.2'.	1 Dec 1972
5,	IS: 693-1965 Specification for varnished cambric insulated cables (Revised)		No. 2 Jan 1973	Toble 2 has been amended	1 Jan 1973
6.	IS: 1554 (Part II)-1970 Specification for PVC insulated (heavy duty) electric cables Part II for working voltages from 3.3 kV up to and including 11 kV		No. 1 Dec 1972	 (i) Existing informal table under clause 0.3 has been substituted by a new one. (ii) Clauses 1.1, 4.2, 4.3, 5.4.1, 7.2, 7.4.2, 8.2, 8.3 and 10.15 have been amended. (iii) Note under clause 1.1.1 has been substituted by a new one. (iv) A new Note has been added at the end of clause 4.5. (v) (Page 8, clause 5.4.2) — Delete (vi) (Page 10, Table 3) — Delete the asterisk '(*) mark against item (a) and the corresponding explanation at the foot of the Table. 	1 Dec 1972
7.	IS: 1667-1971 Specification for toffees (First Revision)		No. 1 Jan 1973	[Page 6, Table 1, Col 4, against Sl. No. (vii)] — Substitute '3.0' for 2.0'.	1 Jan 1973
8.	IS: 1714-1960 Methods of sampling and test for oilcakes as livestock feed	S.O. 570 dated 18 Mar 1961	No. 4 Jan 1973	(i) Clause 5.1 has been amended (ii) Clause 10.2 has been substituted by a new one	1 Jan 1973
9.	IS: 1753-1967 Specification for aluminium conductors for insulated cable, (First Revision)	S.O. 3734 dated 21 Oct 1967	No. 3 Dec 1972	(i) Table 2 has been amended (ii) Clause 12.1.1 has been substituted by a new one (iii) Clause 12.2.1, has been amended	1 Dec 1972
10.	IS: 1849-1967 Code of practico for dosign and installation of line kilns		No. 1 Dec 1972	Title on first cover page, pages 1 and 3 has been substituted by new one.	1 Dec 1972
11.	IS: 1942-1968 Specification for bone-meal as livestock feed supplement (First Revision)		No. 1 Dec 1972	Clause F-2.1 has been substituted by a now one	1 D∞ 1972
12.	IS: 2082-1965 Specification for storage type Automatic electric water heaters (Revised)	S.O. 2246 dated 30 Jul 1966	No. 2 Jan 1973	 (i) Clause 4.1.1, 4.2.1 and 5.5 have been substituted by now ones. (ii) Foot-note with (†) mark on page 7 has been substituted by a new one. (iii) Clauses 4.1.2, 4.2.9.1, 6.1, 9.3.5.1, 9.3.6 and C-1.2.2 have been amended, (iv) [Page 8, foot-note with (*) mark] — Substitute '(second revision)' for '(revised)' (v) New clauses 8.1.3 and 9.1.2.2 have been added. 	1 Jan 1973

		·			
1	2	3		5	6
13.	18: 2148-1968 Specification for flameproof enclosures of electrical apparatus (First Reivslon)	S O. 3728 dated 13 Sep 1969	No. 2 Jan 1973	 (i) (Page 12, Table 2-C, Note 1, line 2) - Substitute 'threads or six' for 'threads of six'. (ii) Note 2 under Fig. 1 has been substituted by a new one. 	1 Jan 1973
				 (ni) Fig. 2 has been substituted by a new one (iv) Note I under Fig. 3 and Clauses 4.2.1 3, 5.1.1, 5.1.3, 5.3.3.4, 5.9 and 10.1 have been amended (v) (Page 32. Fig. 14) - Substitute 'B=Flame proof terminal box' for 'A = Flameproof terminal box'. 	
14.	IS: 2151-1962 Specification for Maize germ ofleake	S.O. 3447 dated 17 Nov 1962	No. 1 Jan 1973	(i) Clause B-2.1 has been amended (ii) Clause G-2.1 has been substituted by a new one	1 Jan 1973
15.	IS: 2347-1966 Specification for domestic pressure cookers (Revised)	S.O. 469 dated 11 Feb 1967	No. 4 Doc 1972	New clause 5.2.4 has been added	1 Dec 1972
	IS: 2386 (Pt IV)—1961 Methods of Test for aggregates for concrete Part IV mechanical properties		No. 1 Nov 1972	Equation under clause 6.7 has been substituted by a new one	1 Nov 1972
17.	IS: 2516 (Pt II/Sec I)—1966 Specification for alternating	S.O. 1759 dated 20 May 1973	No. 2 Jan 1973	(i) (Page 15, clause 6, 8, 1, 3, line 2) Substitute 'rated' for 'recovery'.	l Jan 1973
	current circuit-breaker Part II tests Section 1 voltage not exceeding 1000 volts	·		(ii) Clause 9.3 (b) has been substituted by a new one	
18.	IS: 2838—1964 Specification for stoneware containers for general purposes—	S.O. 2033 dated 17 July 1965	No. 1 Dec 1972	Clause C-4.1 has been substituted by a new one	1 Dec 1972
19.	IS: 2839—1964 Specification for industrial stonware;	S.O. 2729 dated 4 Sep 1965	No. 1 Da. 1972	Clause C-4.1 has been substituted by a new one	1 Dec 1772
20.	IS: 2842—1964 Specification for basic pig iron (coke) for steel making purposes	S.O. 1152 dated 10 Apr 1965	No. 1 Nov 1972	Clause A-1.1 has been substituted by a new one	l Nov 1972
21.	IS: 3148—1967 Specification for metallic slide fasteners (First Revision)		No. 1 Dec 1972	 (i) (Page 10, clause 9.1, flue 3)—Substitute 'Appendix J' for 'Appendix H'. (u) (Page 22, Appendix H)—Substitute 'Appendix J' for 'Appendix H' and change the clause numbers accordingly. 	1 Dec 1972
				 (iii) [Page 7, clause 5.1 (g)]—Add the following new requirement at the end; '(h) Resistance to deformation of mouth of slider.' 	
				 (iv) New clause 5.1.7 has been added (v) New Appendix 'H' has been added after clause G-3.1. 	
22	IS: 3317–-1965 Specification for needles, hypodermic	S.O. 2246 dated 30 Jul 1966	No. 1 Dec 1972	Existing clause 8.2 has been substituted by a new one and the foot-note has been deleted,	1 Dec 1972
23,	IS: 3347 (Part IV/Sec 2)1967 Dimensions for porcelain trans- formers bushings Part IV 24 kV bushings Section 2 metal parts		No. 1 Dec 1972	New clause 1.1.1 has been added	1 Dec 1972
24.	18: 3347 (Part V/Sec 2)—1967 Dimensions for porcelain trans- formers bushings Part V 36 kV bushings Section 2 metal parts		No. 1 Nov 1972	(Page 6 to 16, clauses 3 & 4)—Delete reference to metal parts for 36/250 bushing rating wherever it occurs.	1 Nov 1972
25.	IS: 3400 (Part II) —1965 Methods of test for vulcanized rubbers Part II hardness		No. I Nov 1972	Clause 5.2 has been substituted by a new one	1 Nov 1972
26.	IS: 3532—1966 Specification for chemical cotton for mitrocellulose		No. 1 Jan 1973	Clauses 2.1(b), 3.3,2 and 3.3.3 have been amended	l Jan 1973
27.	IS: 3626—1966 Specification for locked coil winding ropes	S.O. 3818 dated 17 Dec 1966	No. 2 Nov 1972	 (i) Clause 3.2, 9.2 and Table 3 have been amended (ii) (Page 5, clause 8, heading)—Substitute the following for the existing heading: '8. Tests on wires before rope making' (iii) Note under Table 1 has been substituted by a 	1Nov 1972

		JAZETTE OF			
ı	2	3	4	5	6
28.	1S: 3959 1966 Specification for skin powders	S.O. 1972 dated 10 Jan 1967	No 1 Jan 1973	(i) (Page 4, clause 3.3)—Delete this clause along with the foot-note and re-number the existing clause 3.4 es 3.3.	1 Jan 1973
				(n) Clauses A3.2.1 and A-8.2.2 have been amended	
				(m) New Clauses 0.3 and 4.2.1 have been added after clauses 0.2 and 4.2 respectively and the existing clauses 0.3 and 4.2.1 have been re-numbered as 0.3.1 and 4.2.2	
				(iv) New clause 1.1.1 has been added	
∡9 .	18: 4039 (Part II)~-1968 Cod. for packaging of ready-mall- garments intended for export Part II airworthy packaging		No. 1 Jan 1973	Clauses 2.1.1, 3.1 and 3.2 have been amended	1 Jan 1973
30	15: 4098—1967 Specification for lime-pozzolana mixture	S.O. 2654 dated 5 Aug 1967	No. 1 Dec 1972	A note has been added under clause 3.1	1 Dec 1972
31.	IS: 4288 -1967 Specification for	S.O. 520 dated	No. 1	(i) Clauses 4.2, 4.3 and 8.4 have been substituted by	l Jan 1973
	PVC-insulated and PVC-sheathed solid aluminium conductored cables of voltage rating not exceeding 1 100 volts	10 I-cb 1968	Jan 1973	new ones (11) (Page 9, Clause 7.1, last sentence)—Delete.	
32.	IS: 5020-1969 Specification for hematite pig iron	S O. 2330 dated 14 Jan 1969	No. 1 Nov 1972	(Page 5, clause A-1.1, line 2)—Substitute 'furnace' for 'blost-furnace'.	1 Nov 1972
33.	18:5021 -1969 Specification for acid-resisting high-silicon pig non	S.O 2330 dated 14 Jun 1969	No. 1 Nov 1972	(Page 5, chase A-1.1, line 2) -Substitute 'furnace' for 'blast furnace.'	l Nov 1972
34.	1S: 50381969 Specification for ice cube trays for domestic refrigerators	S O. 3929 dated 27 Sep 1969	No.1 Dec 1972	Table 1 has been amended	1 Dec 1972
35,	18:5297-1969 Specification for per-chloroethylene (tetrachloroethylene), technical		No. 1 Jan 1973	Table I has been amended	I Jan 1973
36.	IS: 55191969 Deviations for untoleranced dimensions of grey iron castings		No. 1 Nov 1972	Table 2 and 3 have been amended	1 Nov 1972
37	IS · 5571—1970 Guide for selection of electrical equipment for hazardous areas	S.O. 2110 dated 29 May 1971	No.1 Dec 1972	Clauses 3.2.1 and 3.3.1 have been amended	1 Dec 1972
	IS: 55911969 Specification for chlorobenzene	S.O 3015 dated 14 Aug 1971	No. 1 Jan 1973	Table I has been amended	1 Jan 1973
39.	IS + 56801969 Specification for rubber tubing for medical use	S.O 3544 dated 25 Sep 1971	No. 1 Dec 1972	Clause 4.3.1 has been substituted by a new one	1 Dec 1972
	IS: 6048—1970 Specification for temporary corrosion preventive, soft film, hot-dipping type		No. 1 Dec 1972	Clauses 0.2, 0.3, 2.1.2 and Table 1 have been amended	1 Dec 1972
	IS: 6228—1971 Specification for poultry egg fertility tester		No. 1 Jan 1973	(Page 4, clause 5.1, line 6) — abstitute 'narrow' for 'norrow'	1 Jan 1972
_				·	

Copies of these amendments are available for sale with the Indian Standards Institution, 'Manak Bhavan', 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1 and also its branch offices at (1) 534 Sardar Vallabbhbhai Patel Road, Bombay-71 (ii) 5 Chowinghee Approach, Calcutta-13 (iii) 54 General Patters Road, Madras-2 (iv) 117/418 B, Sarvodaya Nagar, Kanpur, (v) 5-9-201/2 Chirag Ali Lane, Hyderabad-1 (vi) 0-18 New Civil Hospital Amexe, Asarya, Ahmedabad-1 (vii) F Block, Unity Bldg, Narasimhataja Square, Bangalore-2, and (viii) B.C.I. Building (3rd Floor) Gandhi Maidan Last, Patna-4.

[No. CMD/13: 5]
A. K. GUPTA,
Deputy Director General

कृषि मनालय (कृषि विभाग)

भादण

नाई दिल्भी, १८ गुनाई, १९७४

कार आर 1952 स्केटियम (2) तथा नियम 12 के उप-नियम (2) तथा नियम 12 के उप-नियम (2) तथा नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुच्छेद (थ) द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया जा प्रयाग करने हुए राष्ट्रपति इसके हारा प्रदेश के हैं कि इस प्रादेश की प्रनुस्ती के स्तम्भ 1 में विनिदिष्ट सामान्य नेन्द्रीय सेवा रिकाट के प्रदेश के स्तम्भ 1 में सिनिदिष्ट साधिकारी कि स्तम्भ 4 में विनिदिष्ट दशें के लिए अनुणासन्त पाविवारी होता।

स न् भूची					
पद का ब्यौरा	नियक्ति प्राधिकारी	केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंष्ठण नथा प्रगील) नियमा- धली 1965 के नियम ।। के पद संख्याओं के सर्वर्भ में निर्धारित किए जाने वाले दण्ड तथा दण्ड निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी			
		प्राधिकारी	्रवण्ड		
1	2	3	4		
कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) (1) उन पदों के श्रतिरिक्त जिनके लिए राष्ट्रपति के सामान्य झथवा विशेष आदेश हारा विशिष्ट ब्ययस्था की गई है, के झलाबा कृषि विभाग में पद।	प्रशासन के कार्य-भारी संयु क् त मिलव	प्रशासन के कार्य-भारी सयुक्त सक्तिक	नभी		
(2) सिववालय के भ्रनावा अन्य ऐसे कार्यालयों के पद जिनके विभागाध्यक्ष नहीं है, उन पदों के भ्रतिरिक्ष्त जिनके लिए राष्ट्र- पति के सामान्य भ्रथवा विशेष भ्रादेश द्वारा विशिष्ट व्यवस्था की गई है।	प्रणासन के कार्यंभारी सप् वत सम्बि ध	प्रशासने के कार्यभारी सयुक्त समिव	मभी		

[न० 50-56/73 वाह्य स्था०-3] रा० सुब्रह्मणियम,

अक्षर मिचव

MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agriculture) ORDER

New Delhi, the 18th July, 1974

S. O. 1952.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9 and clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that in respect of the posts in the General Central Service, Class II, specified in column 1 of the Schedule to this Order, the authority specified in column 2 shall be the Appointing Authority and the authority specified in column 3 shall be the Disciplinary Authority in regard to penalties specified in column 4 thereof.

SCHEDULE

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose [with reference to item numbers in rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965].	
		Authority	Penalties
1	2		4
Ministry of Agriculture			
(Department of Agriculture)			
(i) Posts in the Department other than those in respect of which specific provision has been made by a general or special order of the President.	Joint Secretary incharge of Administration.	Joint Secretary incharge of Administration.	All
(ii) Posts in Non-Secretariat offices which have no Head of Depart ment, other than those in respect of which specific provision has been made by a general or special order of the President.	- Joint Secretary incharge of Administration.	Joint Secretary incharge of Administration.	All

[No. 50-56/73-E.E.III.] R. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

नौबहन ग्रौर परिवहन मंत्रालय (परिबहन पक्ष) नई दिल्ली, 20 गुलाई, 1974 (स्थापार पोत)

कां आ 1953.—नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के माथ पठित नाविक भविष्य निधि प्रिधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रवत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनदद्वारा श्री की ० एच० धन जी भाई को कैन्ट्रन ए० के० बंसल के स्थान पर नाविक भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड के सदस्य के तौर पर नियुक्त वरती

है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की श्राबिस्चना सक्ष्या मा० श्रा० स० 5266 दिनांक 11 नवस्वर, 1971 में निम्नलिखिन संशोधन करनी है, श्रर्थात:——

उक्त ग्राधिमूचना में शीर्ष सबस्यों के श्रंतर्गत श्रीर तत्सबधी प्रतिष्टि के स्थान पर निम्नलिखिन कम सं० ग्रीर प्रतिष्टि प्रतिस्थापित किये जाएँ, प्रयत्ति "७, श्री डी० एच० धन जी शार्ड, पोतस्वामियों के प्रतिनिधि"

[सं० एम० प्रब्लू ०एम० (5)/74-एम०टी०]

वि० वि० सुन्नह्मण्यम, उपसचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th July, 1974

(Merchant Shipping)

S.O. 1953.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), read with paragraph 3 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, the Central Government hereby appoints Shii D H Dhumbhoy as a member of the Board of Trustees of the Seamen's Provident Fund in place of Captain A. K. Bansal and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Trunsport Wing) S O No 5266 dated the 11th November, 1971, namely:—

In the said notification under the heading, "Members", for serial No 6 and the entry relating thereto, the following serial No and entry shall be substituted, namely:—

"6. Shri D H Dhunjibhoy-Shipowners' representative".

[No. MWS (5)/74-MT]

V. V. SUBRAHMANYAM, Dv. Secv.

MINISTRY OF I ABOUR

New Delhi, the 17th July, 1974

S.O. 1954.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 ot 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal (Central), Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the Canteen Stores Department (India) Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th July, 1974

BEFORE SHRI H. R SODHI, PRESIDING OFFICER, IN-DUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL), CHANDIGARH

Reference No 12/C of 1973

BETWEEN

The workman and the management of the Canteen Stores Department (India) Bombay.

Appearances:

Shii M. L. Basur—for the workman Shii Bhagirath Dass- for the management.

AWARD

Shri Din Daval Dhiman was employed as a Head Operator of Defence Services Cinema, Adampur (Punjab) but his services were ferminated on 6th April 1966. He raised a dispute with the management challenging the legality and propriety of the order of termination of his services and the Central Government by Notification No. 3/6/69-LRIII(IRI) dated 12-10-1973, published in the Gazette of India, referred to this Tribunal the following matter for adjudication:—

Whether the action of the management of Canteen Stores Department (India) Bombay in terminating the services of Shir Din Daval Dhiman, Ex-Head Operator of Defence Services (Inema, Adampur, with effect from the 6th April, 1966 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

2. In the claim statement filed by the concerned workman it was pleaded that false allegations of mis-conduct had been levelled against him and that the termination was in fact an unfair labout procuce. It was also pleaded that no enquity about the allegations made against him was even held and that termination was m violation of rules of natural justice. The termination order was stated to have cast a stigma on the

conduct of the workman. A written statement was filed by the Defence Services Cinema, Jullundur Cantt, as the concerned management. One of the pleas raised by the management is that the workman had accepted that the terms and conditions of his service would be governed by the Punjab Shops & Commercial Establishment Act, 1958, described hereinafter as Shops Act. The conduct of the workman is stated to have been unsatisfactory. It is admitted that no enquiry was held but the plea of the management is that no enquiry was necessary since the action had been taken against the workman under the aforesaid Act. There is no dispute that wages in lieu of one month's notice and other dues have not so far been received by the workman but the case pleaded by the management is that he refused to accept the money order. An additional plea taken by the management is that it is entitled to lead evidence before this Tribunal to prove the mis-conduct and unsuitability of Shit Din Dayal to be retained in service. On the pleadings of the parties, issues were framed on 2-1-1974 but they were subsequently modified on 1-2-1974. The amended issues are as follows:—

- (1) Whether the action of the management of Canteen Stores Department (India). Bombay in terminating the services of Shri Din Dayal Dhiman, Fx-Head Operator, w.c.f. 6-4-66 is justified?
- (2) If issue No. 1 is found against the management to what relief is the workman entitled?
- (3) Whether the management has complied with the provisions of Section 22 of the Punjab Shops & Commercial Establishments Act, 1958 and if not, what is its effect?
- (4) Relief.

As a matter of fact, no issue was pressed as a preliminary issue. On behalf of the management, three witness, namely, Shri Krishna Manon, Proprietor, Madras Hotel, Adampur, R.W.1, Shri S. k. Sharma, Manager Defence Crnema, R.W. 2, and Shri Karamji Singh, Operator of the Cinema, R.W. 3, were examined, Shri Bhagirath Dass, authorised representative of the management stated that this was the only evidence to be produced and even if the Tribunal wanted to give adjudication on merits about the alleged misconduct, the management had no other evidence to produce as the depositions of these three witnesses were enough to establish the un-suitabity and mis-conduct of Shri Din Dayal Dhiman, workman The workman examined Shri Jai Shankar, contractor A. 1, Shri Karamjit Singh, farmer, resident of V Chamon (Adampur), A.W. 2, Shri Gurbux Singh, Operator, Neelam Theatre, Chandigrah A.W.3 and himself went into the witness box as his own witness. I shall dispose of issues 1 and 2 first they are inter-connected and the main controversy is the subject matter of these two issues. Shri Bhagirath Dass strenuously urged that the workman accepted the terms of appointment as contained in Ext. R/5 and, therefore, he must be held to be governed only by the Shops Act and not by the Industrial Disputes Act so as to necessitate an enquiry into the alleged mis-conduct before his services could be terminated. I am afraid this contention is without substance. Before dealing with the legal aspect I must mention that the workman actually joined service in 1962 and it was almost a year thereafter that an appointment letter, Ext. R/5, dated 9-4-63 was issued to him wherein it is undoubtedly stated that his terms and conditions of service will be governed by the Shops Act even though the said Act was not applicable to that Cinema. The following extract from that letter needs to be reproduced for facility of reference:—

"Your terms and conditions of service will be governed by the Punjab Shops & Commercial Establishments Act, 1958 even though the said Act is not applicable to your Cinema."

'In case you are transferred to any of our other Cinemas your terms and conditions of Service will be governed by the Local Shops & Establishments Act of the State where that Cinema is located."

4 The workman accepted the terms as per letter Fat R/6, In the absence of evidence that Shops Act applied to the Cinema where Shii Din Dayal Dhiman was employed, more so when in the appointment letter itself it is clearly stated that the Act was not applicable to that Cinema, I have to proceed on the hypothesis—that the Act was not applicable—More-

over as to by what terms and conditions of service, the work man was intended to be governed should have been clearly conveyed to him in the appointment letter The workman had oined in 1962 and it was that time that contract of service was entered into the is nobody's case that the workman was taken in employment on the specific condition that terms and conditions of service would be regulated by the Shops Act The workman had already invested one year in service when the appointment letter was issued to him and he naturally submitted the typed reply signed by him saying that he was willing to accept those terms I cannot believe that Shir Din Dayal Dhiman would have, on receipt of the appointment letter taken up the Shops Act, read its provisions and then with a clear appreciation of the various provisions of the Act understood the terms and conditions of his service Assuming that the workman was governed by the provisions of the Shops Act I am still of the view that it does not follow that by accepting to be so governed, he had lost a right to seek protection under the Industrial Disputes Act and claim that before his services were terminated for some alleged mis conduct and a stigma cast on him, he should have been afforded a proper opprotunity to defend himself in a manner consistent with the Rules of natural justice Section 22 of the said Act on which reliance is pleaded on behalf of the management is in the following terms

- "22 (1) No employee shall be removed from service unless and untill one month's provisions notice of pay in lieu thereof has been given to him.

 Provided that
 - (a) no employee shall be entitled to the notice or pay in lieu thereof if he is removed on account of mis condut established on record,
- (b) no employee shall be entitled to one month's notice or notice pay unless and until he has been in the service of the employer continously for a period of three months

4 A contravention of this Section 22 is made an offence and a claim for salary in this regard has to be made within six months of the removal from service. In support of his contention, Shii Bhagii ath Dass has invited my attention to a judgment of Their I ordships of Supreme Court reported in 1961 ll-LLJ, P 94, facts of which are entirely different Several disputes arose in that case between the management of May and Bakei (India) Itd and their workman for accumulation of the privilege leave. The Delhi Shops and Establishments Act was applicable to this management. The Inbunal directed contrary to the provisions of the Delhi Shops & Establishments Act that recumulation of privilege leave shall be allowed upto a maximum not permitted by the said Act On an appeal being taken by special leave, heir Lordships held that it was not open to the Industrial Filbunal to have allowed accumulation of leave upto 12 weeks when accumula tion was only 30 days under the Delhi Shops Act. It is no where observed by Their Lordships that the privisions of the Industrial Disputes Act stood over ridden by the Shops Act What seems to have happened is that the Industrial Tribunal in its discretion in the matter of administration of social justice or for reason connected herewith took a view conting to a statute which was also applicable between the same management of the statute which was also applicable between the same management. nagement and the workman. No such situation arises in the present case The Shops Act does make any provision for an enquiry of bit an enquiry When a mis-conduct is alleged against an employee Section 22 of the Shops Act quoted above only provides for previous notice of the proposed removal of an employee from service or pay in lieu of such notice The scheme of the Shops Act is entirely different and not intended to absorate the Industrial Disputes Act. No such contention has indeed been advanced before me that the reference could not be legally made to this Tribunni, I am called upon to determine whether the action of the management in dismissing the workman was justified and this beyond dispute constitutes an industrial dispute. If there were anything in the Shops Act which prohibited an enquiry it could be said that I should be guided by such a special provision of law but there is no prohibition contained in the said Act. There may be cases where though an employee has been dismissed by the establishment of a shop still it does not create an in dustrial dispute but once the other pre requisites are found to exist and the dispute is an industrial dispute the manner of exercise of jurisdiction by the Industrial Tribunal or that type of tellet that he to be given to the aggreed workmen is not, in my opinion controlled by the Shops Act. In the in stant case numerous charges were made out against

workman as it appears from different stages. The letter of termination of services of the workman as issued by the Churman Board of Administration, is Ext. A/1 and is dated 4th April, 1966 though his services were actually terminated on 6.4.1966. The charges on which the order is based are stated in Ext. A/1 and it is worthwhile quoting relevant extract in extenso.

- 'I You stopped the running show on 20 March 1966 at about 1130 pm When this matter was reported to zonal Manager (Punjab), he conducted an enquiry, which revealed that you deliberately stopped the machine because you had seen Sarvashii Satish kumar and Bhupindui Singh going out of the Cinema and you expressed before the Assistant Operator and the Cabin Assistant that you should also have some rest. You therefore, took the law in your own hands and deserted your post of duty without consulting anyone. This enquiry has further revealed that
 - (a) You are on many occasions found to be under the influence of liquor—while on duty
 - (b) You are argumentative and pick up a quarrel with anyone who does not agree with you
- (c) You do not start the show at scheduled timings
- (d) You instigate the staff not to cooperative with the management
- 2 It is considered that in view of the foregoing you are not suitable to work in a defence organisation. The Ail lorce authorities have also approached us to have you removed from the Station.
- 5 The only explanation called from the workman was through letter Ext R/7 wherein reference is made to the incident of 20th March, 1966 when the cinema show stopped tot a short while. The workman wrote down his teply Lxt B 7/1 on the same piece of paper. The workman stated that he show was not stopped but the machine fulled resulting in the stoppage of the show hardly for 2-3 minutes. It appears that 5-6 days after the incident of the stoppage of the show the Zonal Manager, Shir O. P. Malhotra came. from Jullundur and made an on-the spot enquiry in which Shii Karamjit Singh, Cabin Assistant RW 3, made a state ment, Ext R/8 Some other members of the staff also appeared but Shri Din Dayal Dhiman was not associated in that enquiry Another surprising fact is that on the next day of the incident, i.e. on 21st March, 1966, warning, Ext R/3, was given to the workman on behalf of the Board of Administration The conduct of the workman was described as generally unsucisfactory and advice was tendered to him to change his behaviour to avoid being replaced by another hand. An assurance was demanded from him in writing There is no explanation coming forward as to why suddenly on necessity arose to serve such a warning on the next day of the alleged cinema incident. The final order of termination of services, Ext. A/1 contains a number of charges of mis conduct including general bad behaviour. Shir S. K. Sharma, R.W. 2, who was at the relevant time posted as Manager of the Chema and seems to be mainly responsible for securing the termination of the services of the workman made number of allecations against the latter. It is how-ever admitted by him that he made the complaints to the higher authorities on telephone and not in writing. He also admits that the services of the workman, were terminated for his conflued mis-conduct in my opinion, the charges he such that they cast stigma on the workman and in notions of fair play and justice, proper enquiry should have been conducted against the workman affording him an opportunity to defend before his services were terminated by way of punishment. The punitive action of the management is of punishment. The punitive action of the management is in violation of the well established rules of natural justice and cannot be sustained in any society governed by rule of
- 6 I would have expressed no opinion on the ments of the charges but in view of the insistence of Shri Bhagitath Dass that the evidence ar led by the management establishes misconduct of the workman and that I should hold accordingly I have no chore but to deal with this aspect of the cases as well. The first witness produced by the management is Shri Krishna Menon, RW 1 who deposes that he runs a

hotel at Adampui and that there was some altercation between him and Shii Din Dayal who would wash his clothes at the water pump from which the witness used to draw water. The witness objected to the washing of the clothes on which some altereation took place. It is specifically stated by him that there was no exchange of abuses and that both of them only shouted at each other. Even little estrangement that arose between the witness and Shri Din Dayal was set at rest by a compromise, Ext. R/1, brought about through the intervention of common friends. The witness admits that he and Shii Din Dayal have cordial relations. I fail to see how evidence of such a witness can be held to prove the mis-conduct of the workman. Next witness is Shi S.K. Shaima, R. W. 2, who is the main person concerned in working up the dismissal of Shri Dui Dayal. It is common ground between the parties that "I ARKI" picture with a very old print was being displayed on the screen in the evening show of 20th March, 1966 and that about 11.30 P.M. lights were switched on and the show suspended for a few minutes. The workman fixes the period as 2-3 minutes whereas Shri Sharma states that it was 4-5 minutes. Shri Sharma was not in the premises—when the show stopped and it was on the next day that he learnt short the inch onarma was not in the piemises—when the show stopped and it was on the next day that he learnt about the incledent. Shri karamjit Singh, R.W. 3, was working as an Assistant Operator with Shri Din Dayal and he is supposed to have made a complaint to Shri Sharma on the next day. The cause of the suspension of the show for few minutes as given by Shri Karamjit Singh is that he was directed by Shri Din Dayal to stop the miching on the ground the minutes. Shi Din Dayal to stop the machine on the ground that when the Manager, Shi S. K. Shatma, R.W. 2, had gone away on stioll and was not attending to the work, why should the workmen do then duty. Shri Sharma was posted at Adampur since September, 1965 and it is admitted that before 20th March 1966, no such incident ever took place I am not prepared to believe that Shri Din Dayal would have stopped the cinema only on the ground that the manager was not present on the premises. There must have been several occasions when the manager was absent but no show was ever stopped. The statements of Shri Karamjit Singh appears to be cooked one. Again Shri Sharma in his statement has levelled a number of charges against the workman though as conceded by him he never complained about any one of them to higher authorities in writing To me v prining Fyt. R/3 also seems to have been procured only to add to the heads of missconduct and to prepare the ground for termination of the services of the workman. Shri Sharma will have us believe that he always found Shri Dm Dayal dumk. It was his duty to deal with the workman much callier when he found the workman to be delinquent in the discharge of his duties and doing his job while drunk. The evidence of Shri Sharma rather condemns him more than the workman and I am not prepared to rely or the same. Moreover, there is no evidence to pinpoint that the cinema show was suspended not on account of breaking of the print but under directions of Shi Din Dayal. The only evidence of Shri Karamjit Singh in this regard is not worthy of credence. The other charges are also not proved by evidence unless—general statement of Shri Sharma is taken at its face value which I am not pre-pared to do—The workman has examined Shri Iai Shankar, I, who was the land lord of the house occupied by A.W I, who was the land lord of the house occupied by him. The statement of this witness is of negative value in a much as all that he stries is that he never saw any demonstration in which Shir Din Dayal raised solagans against Shir Sharma, R.W. 2, or any other person of the management. Shir Karamjit Singh, R.W. 2, is a dismissed employee of the respondent. He states that when picture 'Larki' was on he was on duty at the gate and went to Shir Din Dayal to find out the reason why lights were suddenly switched on. Shir Din Dayal is supposed to have disclosed to this witness that the film had broken. Shir Gurbus Singh. A.W. 3 is an Operator in Neelam Theater. Charligant Sinch. A.W. 3 is an Operator in Neelam Theatre, Chandigath under whom the workman Shri Din Dayal is at present The statement of this witness is of no help to empl, yed. whether new or old can break down whereas the case of the workman is that print of LARKI being old broke down. The workman himself went into witness box as A.W. 4 deposes that Shii Shaima and he were not pulling on nicely and the main ground of strained relations, according to him, was that Shri Sharmo wanted to help Shri Karamjit Singh, R.W. 3 against Shri Hari Dev whom the workman had brought from Hosharpur to work as his Assistant. The suggestion is that Shri Sharma wanted Shri Karamjit Singh. R.W 3, on a higher post in place of Shri Hari Dev. No value can be atta hed to this plea set up by the workman for the first time in his statement when he did not put the

same to Shi Sharma in the witness box. Anyhow, the builden was on the management to prove the mis-conduct of the workman and its own evidence being of no assistance in this regard the weakness of the evidence of the workman is of no significance. In the result I must hold that no mis-conduct of the workman has been proved by any cogent evidence produced before this Tribunal.

7 The last question which survives for consideration is as to whether I should direct reinstatement of the workman with full back wages. The workman has admittedly joined service in Neclam Cinema, Chandigath, since 21-8-71 and is still continution there. He cannot, therefore, be said to be without employment though the contention of the management is that soon after dismissal he joined service. Be that as it may, the workman is in service and to direct his reinstatement in such a case is not necessary. No doubt the service of the workman is of a civil nature but the control is by the Army authorities. To impose the workman on the employer in such a situation will not be conducive to discipline either. In these circumstances, I feel that the proper course for the Tribunal will be to exercise his powers under Section 11-A of the Industrial Disputes Act and award to the workman compensation for wrongful termination of his services instead of ordering his reinstatement. He joined service with the respondent on a consolidated pay scale of Rs. 125-8-205 with a starting salary of Rs. 125 as is evidenced from the appointment letter, Fxt. R/5. The workman has not given any indication in his statement were his total emoluments at the time of dismissal from service. Had the workman continued in service he could not be drawing more than Rs. 150 P.M. when his services were terminated. It was for him to have lead evidence or atleast deposed in his statement as to what were his total emoluments. The length of his un-employment before his joint the present service originally @ Rs. 125 is also somewhat uncertain. In such circumstances I feel that a total compensation of Rs. 5000 will meet ends of justice. The management is accordingly directed to make payment of the said amount within one month of the date of the publication of the award in addition to the costs which are assessed at Rs. 200,

H. R. SODHI, Presiding Officer[F. No. 3/6/69-LR. III(LR. I]V. K. CHANANA, Dy. Secy.

श्रम महालय

म्रादेग

नर्ड बिल्ली, 27 जून, 197**1**

का॰ ग्रा॰ 1955.—यस इससे उपाबद्ध धनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रीद्योगिक विवाद थीठ टी॰ पालानियाप्पन, पीठासीन श्रधिकारी, श्रीद्योगिक ग्रधिकरण, मद्राग के समक्ष लम्बित है.

भौर यतः न्याग के उद्देश्य भौर पक्षकारां की मुविधाओं के लिए उक्त विवाद भ्रतिरिवन विलम्ब के बिना निपटाया जाना चाहिए;

प्रम प्रम, केन्द्रीय सरकार, श्रौद्योगिक विश्वाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क प्रौर धारा 33ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदन प्रक्तियों का प्रयोग करने हुए, एक श्रौद्योगिक श्रधिकरण गठिन करती है जिसके पीठासीन श्रधिकारी श्री कें पी० एस० प्रारोफ होगे, जिसका मृख्यालय श्रिक्तियों होगा, श्रौर उक्त विवाद में सम्बद्ध कार्यवाहियों का श्री थीक टी० पालानियाप्पन से वापस लेती है तथा उक्त श्रौद्योगिक श्रिक्तरण, श्रीत्लिपी को उक्त कार्यवाहियों के निपटार के लिए इस निर्देश माथ श्रन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यग्राहियों पर उसी प्रक्रम में कार्यवाही करेगा जिस पर यह उसे श्रन्तरित की गई है और विधि के श्रन्तार उसका निपटारा करेगा।

गनुसूची

पक्षकारों का नाम

निर्दिष्ट ग्रधियुवना सं०

कर्मकार बनाम उत्पादन केन्द्र, एहट्मन्र - एल० ४२०१२/१२/७ ४/एस - स्रार - ३ तारीख - ६ फरवरी, 1974

[स० ए**ल०** 42012/12/73/एव श्रार अ]

पी० ग्रार० नय्यर, उप मस्यिय

ORDER

New Delhi, the 27th June, 1974

S.O. 1955.—Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed is pending before Thiru T. Palanippan, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras;

And whereas for the ends of justice and convenience of the parties the said dispute should be disposed of without further delay;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri K.P.M. Sheriff as the Presiding Officer, with headquarters at Alleppey withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Thiru T. Palaniappan and transfer the same to the said Industrial Tribunal, Alleppey for the disposal of the said proceedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Name of Parties

Notification No. by which referred

Workmen Vs. Production
Centre, Ettumanur.

L. 42012/12/73/IR III dated the 6th February, 1974.

[No. L. 42012/12/73/LRIII] P. R. NAYAR, Dy Seev.

म्रावेश

नर्ष दिल्ली, 20 जुलाई, 1974

का० ग्रा० 1956.—यत. पारादीप पत्तन न्यास, डाकधर पारादीप पत्तन जिला कट्टक (उड़ीसा) के प्रबन्धनल से सम्बद्ध नियोजको ग्रौर उनके कर्मकारों के बीज, जिनका प्रतिनिधित्व पारादीप पत्तन श्रमिक सघ, डाकघर पारादीप पत्तन, जिला कट्टक (उड़ीसा) करता है, एक ग्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है,

ष्टीर यन उक्त नियोजको श्रीर उनके कर्मकारों ने श्रीद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 11) की धारा 10क की उपधारा (1) के श्रिधीन एक लिखिन करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देणिन करने का करार कर लिया है श्रीर उक्त श्रिधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के श्रिधीन उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केस्प्रीय सरकार को भेजी है,

भतः, प्रबं, उक्त प्रधिनियमं की धारा 10क की उपधारा (3) के प्रानुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार की, जो उसे 6 जुलाई, 1974 की मिला था, एतबुहारा प्रकाणित करती है।

भौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन करार के बीच

नियोजको का प्रतिनिधित्य करने वाले 🕆

घध्यक्ष,

पारादीप पसन न्यास ।

कर्मकारों प्रतिनिधित्व करने वाले

प्रधात.

पारकीय पत्तन श्रमिक सध ।

पक्षकारों के बीच एतद्बारा करार किया गया है कि निम्नलिखित ग्रीचोगिक विवाद को श्री टी० एस० शंकरन, संपृक्त मिचब, श्रम मंत्रालय, श्रम-णिक्त भवन, रफी मार्ग, नई दिल्लों के माध्यस्थम् के लिए निर्वेणित किया जाए।

- (i) निर्निदिष्ट विवादग्रस्त विषय—-पनन और इक्त कर्मकारों के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट, उस पर लिए गए मरकारी निर्णयों और अस्य संविध्त विषयों, अखिल भारतीय पनन और डाक कर्मकार फेडरेणन द्वारा उठाई गई मांगों और इन पर आगे किए गए विचार-विषयों के संवर्ध में, महापननों के पनन और डांक कर्मकारों से संबंधित निस्निनिखित विवादग्रान निषयों को श्रोबोनिक निवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अभीन साध्यस्थम के लिए, गुण-दोष के आधार पर निर्णयार्थ निर्देशित किए जाने का करार किया गया है:--
 - (1) क्या श्रथमाहास्य प्राप्त श्रौधोगिक श्रावास योजना से प्रश्नेमाहास्य के तस्य ग्रौर श्रस्य सुष्यत कारणों को ध्यान से रखते हुए मानक मकानों के किराय की वसूली की सरकार द्वारा प्रस्तावित वरों को, श्रथान् जहां मूल वेतन 200 क्यों प्रतिमाह से कम है, यहां मूल वेतन का (परन्तु नगर प्रतिकर भने का नहीं) 7 है प्रतिशत श्रौर जहां वह 200 क्यों प्रतिमाह या उससे ग्रधिक है, यहा मूल वेतन (परन्तु नगर प्रतिकर भने का नहीं) का 10 प्रतिगत, घटाया जाना चाहिए श्रौर यित हों, तो किन सीगा तक ?
 - (2) क्या महापनितों के पनित और डांक कर्मकारों के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के घाधार पर सरकार हारा स्वीकृत संशोधित बेतनमानों में वेशन के निर्धारण के विषय में मजदूरी बोर्ड की सिफारिश के प्रतुसार सरकार हारा मंजूर को गई 11 80 ६० प्रतिमाह की ग्रातरिंग सहायता या उनके भाग को ध्यान में रखा जाना चाहिए?
 - (3) क्या मकान किराया भने और नगर-प्रतिकर सत्ते के प्रयोजन के लिए, महगाई भने (अतिरिक्त महंगाई भने और सभय-पनय पर महगाई भत्ते में की गई वृद्धियों सहिन) को प्रशतः या पूर्णतः वेतन के रूप में माना जाना चाहिए?
- (ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें ग्रम्त स्थापनों या उपक्रवों के नाम ग्रीट पते मा समिनित है.
 - (क) पाराज्ञीय पत्तन त्याम (ख) पारादी पत्तन श्रामिक संघ, डाकबर पारादीय पत्तन, डाकघर पारादीय पत्तन, जिला कट्टक, उड़ीसा। जिला कट्टक, उड़ीसा।
- (iii) सच का नाग पारादीप पत्तन श्रमिक सघ।
- (iv) प्रभावित उपकथ में निरोजित कर्मकारों की कृत संख्या लगभग

2,500

(v) विवाद से प्रभावित या सभाव्यत प्रभावित वर्ष्मकारो की प्रनुमानित संख्या लगभग 2000।

मध्यस्य ग्रपना पंचाट तीन मास की कालार्वाध या इतने भीर समय कै भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा ।

उपयुक्त ग्रीकोगिक विवाद को श्री ए० टी० जाम्बे, पीठासीन ग्रधि-कारी, केन्द्रीय सरकार भौद्योगिक श्रधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय सरुया 2, चौथी मंजिल, सिटी प्राईस बिल्डिंग, 298, बाजार गेट, फोर्ट, बम्बई को निर्देशित करने संबंधी पिछला करार, जो हमने 11 जन, 1973 की किया था ग्रीर जिसे भारत सरकार के श्रम ग्रीर पुनर्वास महालय (श्रम ग्रीर रोजगार विभाग) ने धपने प्रादेण सख्या एल-39013/1/73-पी० एण्ड डी॰ (ii), नारीख 9 भुलाई, 1973 के रूप में भारत के राजपन्न, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाणित किया था, एनदक्षारा रह किया जाता है।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ह० प्रेमानन्दा विपाठी 7-6-73 कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : ह० निशामणी खुन्तिया

माक्षी: 1. ह० प्रपाठ्य 7-6-74

2. ह० घपाटय

7-6-74

[मंख्या एल-39013/1/73-पी एण्ड डी ०/एल झार-3]

जी० सी० सक्सेना, प्रवर मचिव

ORDER

New Delhi, the, 20th July, 1974

S.O. 1956.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Paradip Port Trust, P. O. Paradip Port District Cuttack (Orissa) and their workmen as represented by the Paradip Port Workers' Union, P. O. Paradip Port, District Cuttack (Orissa);

And, whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government, under sub-section (3) of section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said Agreement which was received by it on the 6th July,

AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

BFTWEEN

Representing employers-Chairman, Paradip Port Trust. Representing workmen-President, Paradip Port Workers' Union.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri T. S. Sankaran, Joint Seceretary, Ministry of Labour, Shram-Sakthi, Bhavan, Rafi Marg, New Delhi.

(i) Specific matters in dispute.—In the context of report of the Central Wage Board for Port and Dock Workers, the decisions of the Government thereon, and other related matters, the demands raised by the All India Port and Dock Workers' Federation and the further discussions held on these, the following matters in dispute relating to Port and Dock Workers of the Major Ports are agreed to be referred to 51 GI/74—6

- arbitration under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947, for decision on merits:
- (1) Whether, and, if so, to what extent the rates for recovery of rent for standard houses proposed by Government, namely, 7-1/2 per cent of basic pay (and not City Compensatory allowance), where basic pay is less than Rs. 200 per monsom, and at the rate of 10 per cent of basic pay (and not City Compensatory Allowance), if it is Rs. 200 per mensom or more, should be reduced taking per mensom or more, should be reduced taking into account the subsidy element in the Subsidised Industrial Housing Scheme and other relevant fac-
- (2) Whether in the matter of fixation of pay in the revised scales accepted by the Government on the basis of the Central Wage Board Report for Port and Dock Workers at Major Ports, the interin Relief of Rs. 11.80 per mensem or part thereof granted by Government as recommended by Wage Board should be taken into account.
- (3) Whether Dearness Allowance (including additional Dearness Allowance and increases in Deraness Allowance from time to time) in part or full should be treated as pay for the purpose of House Rent Allowance and City Compensatory Allowance.
- (ii) Details of parties to the dispute including the names and addresses of the establishments or undertakings involved:
 - (a) Paradip Port Trust P.O. Paradip Port, District-Cuttack Orissa.
- (b) Paradip Port Workers' Union P.O. Paradip Port District-Cuttack Orlssa.
- (iii) Name of the Unions: Paradip Port Workers' Union.
- (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected: About 2,500.
- (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute: About 2000.

The arbitrator shall make his award within a period three months or within such further time as is extended mutual agreement between us in writing.

The previous agreement entered into by us on the 11th June 1973 and published by the Government of India Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in Part II. Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India vide their Order No. L. 39013/1/73-P&D(ii) dated the 9th July, 1973 to refer the above mentioned industrial dispute to the arbitration of Shri A. T. Zambre, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, 4th Floor, City Ice Building, 298, Bazargate Street, Fort, Bombay is hereby cancelled.

Signature of the Parties

Representing employers:

Premananda Tripathy

7-6-74.

Representing workmen:

Nishamani Khuntia

Witnesses.

1. Illegible 7-6-74.
2. Illegible 7-6-74.

[No. L. 39013/1/73-P&D/LRIII]

S.O. 1957.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the Beas Dam Project, Talwara and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th July, 1974.

BEFORE SHRI H R SODHI, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL I RIBUNAL, CENTRAL, CHANDIGARH

Reference No 8/C of 1973

BETWEEN

the workmen and the management of Beas Dam Project Talwara (Punjab)

APPEARANCES

Shri K K Jaagi, Superintending Engineer along with Salvshii Kuldip Singh and Padamiit Singh for the respondent management

Salvshri Santokh Singh, Harbans Singh Ram Nath, Bachittar Singh Rajpal, P C Shaima, Thaker Dass, Yash Pal, O P Kalia, Daulat Singh Choban and Pritam Singh for the workmen

AWARD

There are two connected References No 8/C of 1973 and 9/C of 1973 raising the same dispute, namely, that the work charged employees of Bens Dam Project, Talwara, who have put in 10 years of continuous service or more should be declared entitled to the regularisation of their services. In Reference No 9/C of 1973, the claim is by a particular category of workmen namely, drivers and conductors, though they are covered by the general Reference as well. The management in both these References is Beas Dam Project, Talwara, which is one of the Units of the Beas Sutley Link Project, with regard to whose work-charged employees. I have given an award on 15-5-1974 in the matter of same dispute in Reference No 2/C of 1971. The present References were made to this Tribunal by the Cential Government in exercise of the powers conferred on it by sub-section (2) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, published in the Government of India Gazette as per Notifications No L 42012/11/73/I RIII, dated 26 5 73 and No L 42012/8/73/LRIII, dated 26 5 73 respectively, and the following matter requires adjudication.

Whether the work charged employees employed at Beas Dam Project Talwara, who have put in ten years or more of continuous service are entitled to the regularisation of their services? If so, from what date?

Claim statements were filed by the workmen to which the management filed its teplies. On the pleadings of the parties following issues were framed —

Preliminary issue

Whether the instant reference is bad in law and without jurisdiction for the reasons given in paras 1 to 3 of the preliminary objections in the written statement, it being pleaded inter alia on behalf of the respondent management that the application for joint reference was not duly signed by the President of the concerned union, nor is the Beas Project Workers United Front a trade union registered under the Trade Unions Act, and also because the Executive Committee of the said Workers United Front did not pass any resolution to raise the demands covered by the reference nor has the demand been espoused by a substantial number of workmen of the Project?

On merits

- 1 Whether the work charged employees employed at Beas Dam Project, Talwara, who have put in 10 years or more of continuous service are entitled to regularisation of their services?
- 2 If issue No 1 is found in favour of the workmen to what relief, if any they are entitled and from what date?

The cases were fixed for evidence of the parties in regard to the preliminary issue but the parties desired an adjournment on 31d June, 1974 to make up mind if they wanted

an agreed award in the same terms as in the case of the other Unit of Beas Sutley I ink Project in Reference No 2/C of 1971 On 14th June, 1974, the management was represented by Shu K k Jaagi, Superintending Engineer along with Sarvshii Kuldip Singh, Peisonnel Officer and Padamitt Singh, Assistant Personnel Officer The several unions were of 1971 represented through their authorised representatives. On be half of the management it was stated that no evidence was to be led whether on preliminary issues of on merits. Same was the stand of the workmen. I quite agree that no amount of evidence could be helpful as it is an admitted fact that of evidence could be neiptul as it is an admitted fact that there are work-charged employees who have put in 10 years continuous service or more or the Project and the sole question to be decided is whether their services should be regularised or not. The statements of authorised representatives of the parties were, accordingly recorded and it was agreed amongst them that award be made. Shri Jaagi, however, while admitting that Punjab Government had regularised services of its work-charged staff submitted that there were no posts in their establishment on which the work-charged employees could be absorbed if their services were regularised After giving my careful thought to the matter I feel that the only correct course is to put the work-charged employees of Beas Dam Project, Talwara at par with those working in the same Project though as a different Unit at Sundernagar and known as Unit I It may be reiterated that the Project started somewhere in the year 1962 and was before re-organisation of the erstwhile State of Punjab under the Punjab Re organisation Act, 1966, managed and controlled by the then State Government of Punjub This is one of the biggest Projects in the Northern India and after the re-organisation it has been taken over by the Central Government for management on behalf of the successor State of the erstwhile State of Punjab and the State of Rajasthan It is not disputed that there are work charged employees who have completed service on the Project for ten years or more and indeed spent best part of their life in a specialised and particular job. I have already observed that the institution of the work-charged employees is indispensable for any construction work but at the same time it is very haish to a worker that he should continue as work-charged employee for a number of years without being entitled to any relief under the Payment of Gratuity Act or other retiral benefits The employees are from different States though the management has constantly by and large, been following the Punjab pattern in the matter of wage structure, revision thereof from time to time and grant of dearness allowance. It was with regard to categories not appearing in the common schedule of rates prepared by the erstwhile State of Punjab that the Bhakra Management Board took Standing Committee Even Himachal Pradesh Government generally followed Punjab pattern The Punjab Government declared sometime past that the services of work charged employees in Building & Roads Branch who had worked for 10 years or more would stand regularised and the same benefit was afterwards extended to the employees of the Irrigation Branch as well I did not as was done by the Punjab Government regularise the services of employees of Unit No 1 and evolved some sort of formula which could give relief to the workmen without imposing unnecessary financial builden on the management It was believed that there would be good will on both sides and I am sure if honestly worked the formula should stand in good stead to both the parties The question referred to me is, of course, about the regularisation of the services of work charged employees and directions which I issued for Beas Sutlei Link Unit No 1 and which I am now repeating cannot be said to be not covered by the reference since it amounts to only granting lesser relief than claimed by the workmen. The management cannot be said to be justified by any standard of moral or social justice if it does not absorb the workcharged employees in the maintenance staff of the completed Project if and when such necessity arises I, therefore, direct that whenever recruitment of maintenance staff on the Project on or near its completion becomes necessary and whether the management at that time is with the Central Government or with any of the State Governments on whose behalf the or with any of the State Governments on whose behalf the Central Government is at present managing, the offer shall first be made to work-charged employees in order of their senionity who have put in continuous service of 10 years or more on the Project in that category of the workers the vacancy occurs but all this will be subject to the medical fitness of the workman. The total length of service at the 1 roject is to be taken in computing the period of 10 years continuous service. It does not, however, follow that if a workman of 10 years continuous service is not available for workman of 10 years continuous service is not available for

any category or trade and those available arc of less than 10 years' service, they are not to be given preference. It is the senior most amongst them who should be taken on the maintenance staff. Scale of wages as applicable to the workmen will not, however, be disturbed to their prejudice nor will their continuity of service be affected. The workmen of Beas-Sutlej Link, Sundernagar expressed an apprehension before me and the same has been repeated by the workmen concerned in the instant references that the management would not be fair to them at the time of completion of the Project and to avoid recruiting the work-charged employees, might change in advance their categories or trades. To protect the workmen against such fears I directed in that case and direct here as well that the category or trade of no workman shall be changed within one year preceding the completion of the Project without his consent in writing and that if any such change without consent is made, it will have no consequence masmuch as such a workman will be entitled to the job of his earlier trade provided the vacancy relates to that trade. The workmen have further urged that there are inter-changeable categories in the sense that workmen of different categories (designations) can be put on the same job, and that the management has been so doing. The submission on their behalf is that in the event of a vacancy to be filled up for a job falling in one of the inter-changeable categories, the senior most from amongst any one of such categories, must be absorbed. I am afraid it will be too much tightening the hands of the administration as it may be that genuinely even in inter-changeable categories there may be one employee who is most suitable for a particular job than others. I, therefore, refrain from issuing any directions in this behalf but do expect that the management will quite honestly choose the best man for the job keeping in view his seniority.

There are bound to be left some of the workmen who cannot be absorbed on the regular maintenance staff and in respect of them I have no reason to doubt that the Central Government and also the State Governments who are beneficiaries under the Project will make every reasonable and genuine effort to get those workmen re-employed whether in any of the concerned States or any other part of the country where there is a need for workmen of those trades. The reference stands answered accordingly.

There is no order as to costs. 27-6-74.

H. R. SODHI, Presiding Officer

S.O. 1958.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the Beas Dam Project, Talwara and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th July, 1974.

[No. L. 42012/8/73/LRIII]

BEFORE SHRI H. R. SODHI, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL), CHANDIGARH

Reference No. 9/C of 1973

BETWEEN

The workmen and the management of Boas Dam Project, Talwara (Punjab).

APPEARANCES:

Shri K. K. Jaagi, Superintending Engineer along with Sarvashri Kuldip Singh and Padamjit Singh for the respondent management.

Sarvashri Santokh Singh, Harbans Singh, Ram Nath, Bachittar Singh, Rajpal, P. C. Sharma, Thaker Dass, Yash Pal, O. P. Kalia, Daulat Singh Chohan and Pritam Singh for the workmen.

AWARD

The Central Government in exercise of the powers conferred on it by Section 10(2) of the Industrial Disputes Act,

1947, referred to this Tribunal, as per notification No. L. 42012/8/73/LRIII, dated 26-5-73, and published in the Gazette of India, the following matter for adjudication:—

Whether the workcharged Drivers and Conductors employed at Beas-Dam Project, Talwara; who have put in ten years or more of continuous service are entitled to the regularisation of their services? If, so, from what date?

Following issues were framed but no evidence was led:— Preliminary issue:

Whether the reference is bad in law and without jurisdiction for the reasons given in paras 1 to 3 of the preliminary objections in the written statement of the management, pleading inter alia that Shrl Pritam Singh, who is stated to have served notice of demand, was not the President of the Punjab P.W.D. Motor Drivers Union, and had not right to serve the notice nor were office-bearers of the union authorised by its Executive Committee through a resolution to raise the present dispute, which was at any rate not supported by a substantial majority of the workmen, and that the application for joint reference was also not signed by the proper persons on behalf of the workmen, nor was the Drivers Union competent to take up the cause of the workers?

On merits:

- (1) Whether the work-charged drivers and conductors employed at Beas Dam Project, who have put in 10 years or more continuous service, are entitled to regularisation of their services?
- (2) If issue No. 1 is decided in favour of the workmen, to what relief are they entitled?

It was agreed between the parties that the award be made in the same terms as was done in the case of Reference No. 2/C of 1971. The instant reference was only in respect of a particular category of employees though their case is covered by another Reference No. 8/C of 1973. The main award has been given in that Reference namely 8/C of 1973 and the same will be operative in the present case as well since both the References stand consolidated.

There is no order as to costs.

H. R. SODHI, Presiding Officer

New Delhi, the 24th July, 1974

S.O. 1959.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Tandur and Navandgi Stone quarries (Private) I imited, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th July, 1974

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

Reference No. CGIT-2 of 1972

PARTIES.

Employers in relations to the managements of M/s Tandur and Navandgi Stone Quarries Pvt. Ltd., Hyderabad,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri B. Ramlal Kishen, LLM, Bar-at-Law, Presiding Officer.

2

APPEARANCES:

For the employers—Shri Manik Arke, Consultant and Shri M. Ramesh, Director.

For the Workmen—Shri M. Ramloo, General Secretary, Tandur Stone quarries Labour and Employees Union, and Shri B. Prakash Rao Advocate

STATE: Andhra Pradesh. INDUSTRY: Stone Quarrying.

Bombay, dated 25th June, 1974

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour and Employment, have by their Order No. L-29011/39/72-LR-IV dated 4th February 1972 in exercise of the powers conferred by clause (d) of subsection (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messis. Tandur and Navandgi Stone Quarries (Private) Ltd., Hyderabad and their workmen in respect of the subject matter specified in the following schedule:

SCHEDULE

"Whether the existing rates of wages and dearness allowance of the different categories of workers employed in the Stone Quarries of M/s. The Tandur and Navandgl Stone Quarries (Pvt.) I.td., Hyderabad on various operations require any revision? If so, what should be such rates of wages and dearness allowance and from what date?"

- 2. The workmen petitioners of the Tandur and Navandgi Stone Quarries (Pvt.) Ltd., represented by the Tandur Stone Quarries Labour and Employees' Union, Tandur, filed a statement of claim stating that the workmen employed by the said management are put to great hardship and they are not given any dearness allowance and their wages were not revised for the last eight years although the cost of living had gone up. Taking into consideration the increased cost of living they demanded increased wages and dearness allowance and the payment of a flat sum of Rs. 30 per month to each worker working in the quarries from the date of demand. It has been stated that the management have been carning good profits and exploiting the workmen and they have the capacity to pay increased wages and dearness allowance.
- 3. In spite of several notices the employers did not file any written statement. Finally on 4-7-1973 the employers and the workmen filed a joint petition before this Tribunal exhibit E-2 stating that the parties had arrived at a settlement with regard to all the issue covered under the above reference and praying that an award be passed in terms of the settlement exhibit F-1. Under the schedule to the settlement exhibit E-3 the following rates were settled for the different categories of work.

Category of Work	Rates Settled.		
1			
1. Earth work (including Porka Tharugu work including tools allowances and lead and lift) 2. Dind Work (including tools allowance and lead and lift)	Rs. 42.00 per 1000 cft Rs. 62.50 per 1000 cft		
 Frashl Work (including tools allowance) Katai Workers Wagon loading Hand polishers 	Rs. 4.80 per 100 sq. ft. Rs. 0.40 per Rft. Rs. 16.00 per wagon. Rs. 00.20 per sq. ft.		

'	-
7. Lorry loading	Rs. 2.00 per lorry o f
	6 tonnes.
	Rs. 3.00 per lorry of
	8 tonnes.
	Rs. 4.00 per lorry of
	10 tonnes
8. Farsh Uthvai	Rs. 1.00 more on
	existing rate.
	_

- 4. Some time after the above settlement was filed, one Shri S. Balappa, describing himself as General Secretary, Tandur Stone Quarries Labour and Employees Union, Malkapur filed an application before this Tribunal for fixing the date of hearing at Hyderabad and requesting for intimation about it at the above address.
- 5. In order to satisfy itself that the settlement reached between the parties was bona fide and entered into voluntarily and in view of the request of Shri Balappa Notices of hearing of the reference at Hyderabad on 18-6-1974 was issued by registered post to all parties. Shri Balappa was not present and the notice issued at the address given has been returned undelivered with the postal endorsement "no such addressee present".
- 6. In order to show that the settlement was bona fide and was entered into without any coercion or intimidation the employers examined Shri Malkur Ramesh the Director of the company. It appears from his evidence that after the reference was made efforts were made to arrive at a settlement and ultimately they succeeded in bringing about a settlement between the parties. He identified his signature on exhibit E-1 the settlement as also the signature of the working President Shri Manjeet Singh of the Tandur Stone Quarries I about and Employees Union and the General Secretary Shri M. Ramulu. He also identified the signatures on the joint application and the signature of the other Director Shri Chandrasckhar. It has also come in evidence that the Regional Labour Commissioner (Central) Hyderabad Shri M. R. Raju and the Assistant Labour Commissioner (Central) Hyderabad Shri D. V. Ramachandran had also signed as attesting witnesses. He has also testified that the rates given in the schedule to the settlement exhibit E-3 are being point to the workers. The lates came into force on 1-4-1973 and the workers were receiving the new rates of wages from that date. When questioned by the Tribunal he deposed that the dispute was raised by Shri G. Venkataswamy and the General Secretary Shri S. Balappa. After Shri Venkataswamy became Deputy Minister of the Government of India Shri T. Anjaiah was elected President and Shri M. Ramulu, General Secretary. It is stated by him that Shri S. Balappa who had signed the application to this Tribunal on 5-3-1974 was not elected General Secretary of the Union and the claim made by him in exhibit W-1 is false.
- 7. The workmen have examined Shri M. Ramulu General Secretary of the Employees Union. According to him he was elected General Secretary of the Union in the election held in April 1973. It has come in evidence that previous to him Shi Balappa was the General Secretary and Shri G. Venkataswamy was the President. After Shri Venkataswamy became Deputy Minister in the Central Cabinet Shri T. Anjaiah was elected as President of the Union. He has stated that the settlement exhibit E-1 was drawn up as a result of negotiations between the parties and it was brought about without any coercion or intimidation. He also speaks about the settlement having been witnessed by the Regional Labour Commissioner (Central) and Assistant Labour Commissioner (Central) and Assistant Labour Commissioner (Central) Hyderabad and the same having been signed by Shri Manicet Singh the working President and the Joint Secretary Organizing Secretary and Executive Members having affixed their thumb impressions. He has also deposed that a resolution was passed at the general body meeting authorizing him and Shri Manjeet Singh, Basappa, Antappa and Narasappa, Sayappa and Devi Ja to enter into the settlement with the employers and exhibit W-2 is the resolution and exhibit W-3 is the authorization. He has sworn on oaft that theirs is a recognized union and is a registered body and that the settlement was signed on 12-6-1973. He asserts that

Shri Balappa does not work in the company have accepted the new rates of wages and now there is no dispute existing between the parties. WW 2 Shri Hanmappa has supported in full the evidence of WW 1 Shri Ramulu He has stated that he had affixed his thumb impression to the settlement ex E 1 and he knows the details therein. He has also identified exhibit E 2 as the application filed before the Tribunal for passing an award in terms of the settlement and exhibit E-3 which is the schedule of rates settled. He has also spoken of the Regional Labour Commissioner (Central) and Assistant I abour Commissioner (Central) and Assistant I abour Commissioner (Central) are stillement. He has asserted that nobody pressurized of threatened them to enter into a settlement It was entered into voluntarily and the wages as per the settlement were being paid to the workers as from 1 4 1973 and no worker has refused to accept the new rates of wages

8 Having cautiously gone through the material on record, I am of the opinion that the settlement entered into between the puttes is fair and reasonable. The rates of wages do not seem to be out of tune with the cost of living. From the evidence it is clear hat the workers have no gitevance on that score and I therefore pass an award in terms of the settlement annexure A which shall form part of this award.

No order as to costs

B RAMLAI KISHEN, Presiding Officer ANNEXURE 'A'

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

Reference No CGIT-No 2 of 1972

BETWICN

Employers in relation to M/s Tandur & Navandgi Stone Quarries Pvt Ltd,

AND

Their workmen represented by the Tandur Stone Quarries I abour and Employees' Union

May it please the Hon'ble Tribunal

Both the parties to the above Reference submit as follows

That the parties have an inved at the settlement with regard to all the issues covered under the above Reference

That the parties hereby file the settlement for record

That the parties pray that an award in terms of the settlement be passed by this Hon'ble Tribunal

FOR WORKMEN

FOR MANAGEMENT

For the Tandur Stone Quaities For the Tandur and Navand-

Labour and Employees Union

- gi Stone Quarties Pvt Ltd
- 1 Sd/- M Chandrasekhar (DIRECTOR)
- 2 Sd/- M Ramesh (DIRECTOR)
- 1 Sd/- Manjeet Singh (Working President)
- 2 Sd/- M Ramulu (General Secretary)
- 3 LTI of China Narsappa Jt Secretary
- 4 LTI of Kotha Sayappa Executive Member
- 5 I T f of Hanma Basappa. Org Secretary
- 6 LTI of Devija, Executive Member
- 7 LTI of Methar Anthappa

Dated 12th June 1973

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER SECTION 18(1) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

NAMES OF THE PARTIES

Representing the Management

Represented by

The Tandur & Navandgi Stone Quarries Pvt Ltd., Bashirabad

Shii M Ramesh, Director

Shri M Chandrasekhar

Director

Representing the workmen

Represented by

The Fandur Stone Quarries
Labour and Employees' Union.
Tandui

Sii Manjeet Singh Working President

Sri M Ramulu, and 5 others, _ General Secretary

- I The workers represented by the Union had raised demands on various occasions for increased wages etc. Various joint discussions and conciliations between the parties had taken place without any results. Ultimately the Central Government has made the reference for adjudication before the Central Government Industrial Tribunal, Bombay which is pending before the Tribunal on CGIT No. 2 of 1972. The workers through their union has already filed the claim statement before the Tribunal.
- 2 Thereafter to avoid litigation the workers of the establishment at a meeting held on 12 6 1973, for the purpose of entering into settlement with the Management for revision of rates of wages, authorised the Union representative to act on behalf of the workers
- 3 With an intention to arrive at an amicable settlement both the Management and the Union representatives had protracted discussions and finally they have arrived at the following settlement

TERMS OF SETTLEMENT

Revision of rates of wages for the workers

1 The following categories of workmen will be given the revised rates of consolidated wages inclusive of dearness allowance, tool allowance etc, effective from 1st April 1973 as per the Schedule attached herewith

CATEGORIES

- 1 Earth workers (Including Poika Thaingu Workers)
- 2 Dind Workers
- 3 Farshi workers
- 4 Kottai workers
- 5 Wagon loaders
- 6 Lorry loaders
- 2 The tools allowance payable to Earth Workers, dind workers, faishi workers is included in the wages to the said categories, as per the previous agreement for the sake of mutual convenience and no separate tools allowance will be payable to these workmen
- 3 The above wages will be in force for a period of three years
- 4 In consideration of the increase in wages granted to the workmen of the establishment, the workmen undertake not to demand any increase of wages or demand any dearness allowance for the said period of the three years and further agree that no demand which will involve additional financial liability to the Company will be made during the period of the operation of the settlement
- 5 The aforesaid undertaking given by the workmen will not deprive the workmen of any of the statutory benefits which may be conferred on them by any new enactment which may be passed subsequent to the date of this settlement

6. The workers agree to withdraw the claim statement filed by them before the Central Government Industrial Tribunal, Bombay and both the parties agree to file this agreement in the settlement of this dispute. The parties further agree to file an application in the Tribunal with a prayer to pass an award in terms of this settlement in CGIT Ref. No. 2 of 1972.

FOR MANAGEMENT:

For the Tandur and Navandgi Stone Quarries Pvt. Ltd. Basirabad.

- 1. Sd/- M. Chandrasckhar, (DIRECTOR).
- 2. Sd/- M. Ramesh, (DIRECTOR).

FOR WORKMEN:

- 1. Sd/- Manjeet Singh (Working President).
- 2. Sd/- M. Ramulu, (General Secretary).
- 3. L.T.I. of China Narsappa, Jt. Secretary.
- 4. L.T.I. of Hanma Basappa, Org. Secretary.
- L.T.J. of Kotha Sayappa, Executive Member.
- 6. L.T.I. of Devi Ja, Executive Member.
- 7. L.T.I. of Methas Anthappa.

SCHEDULE

Category of work	Rates Settled			
Earth Work (Including Porka Tharugu work including tools allowances and lead and lift)	Rs. 42.00 per 1000 cft.			
2. Dind Work (including tools allowance and lead and liit)	Rs. 62.50 per 1000 cft.			
3. Farshi Work (Including tools allowance)	Rs. 4.80 per 100 sp. ft.			
4. Katai workers	Rs. 0.40 per Rft.			
5. Wagon loading	Rs. 16.00 per wagon.			
6. Hand polishers	Rs. 0.20 per sq. ft.			
7. Lorry loading.	Rs. 2.00 per lorry of 6 tonnes. Rs. 3.00 per lorry of 8 tonnes. Rs. 4.00 per lorry of 10 tonnes.			
8. Farshi Uthvai	Re. 1.00 more on existing rate.			
WITNESSES:	FOR EMPLOYERS:			

WITNESSES:

FOR EMPLOYERS

- 1, Sd/- M. R. Raju.
- 2. Sd/- D. V. Ramachandran,
- 1. Sd/- M. Chandrasekhar, (Director).
- 2. Sd/- M. Ramesh, (Director).

FOR WORKMEN:

- 1. Sd/- Manject Singh (Working President).
- 2. Sd/- M. Ramulu, (General Secretary).
- 3. L.T.I. of China Narsappa, Jt. Secretary.
- 4. L.T.I. of Hanma Basappa/ Org. Secretary.
- L.T.I. of Kotha Sayappa, Executive Member.
- L.T.t. of Devi Ja, Executive Member.
- 7. L.T.I. of Methar Anthappa.

[No. L-29011(39)/72-LR.IV]

New Delhi, the 25th July, 1974

S.O. 1960.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Paradeep Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th July, 1974.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

PRESENT:

Shri L. Mallick, B.L., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneswar.

Industrial Dispute case No. 6 of 1973 (Central)

Dated Bhubaneswar, the 27th June, 1974

BETWEEN

The management of Paradeep Post Trust

First Party.

ANT

Their Workmen represented by-

- Paradeep Port Workers Union Congress, Paradeep.
- 2. Paradeep Shramik Second Parties.

APPEAR ANCES:

- Srl T. Misra, Legal Consultant, Paradeep Port Trust For the First Party.
- Sri Nisamani Khuntia, President, Paradeep Port Workers'
 Union. For second party No. 1.
- Sri Sudhakar Muhanty, General Secretary, Paradeep Shramik Congress. For second party No. 2.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred by sections 7A and 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act) have, by their order No. L-38015/1/71-P&D dated 23-11-1973, referred the following schedule of dispute to this Tribunal for adjudication.

"In what manner the directions contained in para 5 concerning Wiremen and Linemen in the Arbitration Award, dated the 9th December, 1968 under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947, given by Shri O. Venkatachalam, ex-Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) under

S.O. 514, dated the 8th February, 1969 should be implemented?"

- 2. The management of Paradeep Port Trust is the first party. Paradeep Port Workers' Union, Paradeep and Paradeep Shramik Congress, Paradeep are second parties Nos. 1 and 2 respectively.
- 3. The case of the management of Paradeep Port Trust (hereinafter referred to as the first party), in short, is as follows:—

That there were three grades of Wiremen and Linemen, viz., Grade 'A' (Rs. 100—155), Grade 'B' (Rs. 80—120) and Junior Grade (Rs. 60—75) under the State Government. After the Central Government took over the management of Paradeep Port from 1-6-1966, the three grades were redesignated as Grade I (Rs. 125—155), Grade I (Rs. 110—131) and Junior Grade (Rs. 80—110) respectively. In doing so, the Port administration did not give Grade I scale (Rs. 155—180) recommended by the Committee for the Classification and Categorisation (hereinafter referred to as the C.C.C.) to any of the existing Wiremen and Linemen on the ground that the existing grade under Central Government were on par with the skilled Grade II (Rs. 125—155) and Grade III (Rs. 110—131) and the semi-skilled Grade I (Rs. 80—110) of the C.C.C. The All India Port & Dock Federation claimed for the introduction of Grade I (Rs. 150—180), Grade II (Rs. 125—155) and Grade III (Rs. 110—131) of the C.C.C. for the existing Wiremen and Linemen. The management did not agree with their proposal for introduction of Grade I scale (Rs. 150—180) their proposal for introduction of Grade I scale (Rs. 150—180) of C.C.C. on the ground that there were no suitable hands amongst the existing Wiremen and Linemen to be fitted into the grade. Thus, a dispute arose between the first party and the second party No. 1 and the matter was referred to Sri O. Venkatachalam, Chief Labour Commissioner (Central) and Arbitrator for decision under Sec. 10-A of the Act. In course of hearing, expert opinion of the then Superintending Engineer (Flectrical & Mechanical Circle) of the Port was sought. He was of the opinion that qualification, duties and responsibilities of the Wiremen and Linemen had not been formulated by the Port authorities. As a result of that some formulated by the Port authorities. As a result of that, some of the existing staff recruited by the Port had not got the requisite qualification as in Vishakhapatnam Port. The Wiremen at Paradeep are not employed in wiring of crafts, polyphase motors etc. and further there were some whose works were not upto the mark. Therefore, the Superintending works were not upto the mark. Therefore, the Superintending Engineer suggested that the trade test and qualification were absolutely necessary before the Wiremen and Linemen could be fixed up in the proper grade. The Arbitrator, while giving the Award, very much appreciated the suggestion given by the Superintending Engineer of the Port and accordingly in his arbitration award dated 9th December 1968, he gave direction to the administration to introduce Grade I (Rs. 150—180) of CCC for Wiremen and Linemen and to place the 180) of C.C.C. for Wiremen and Linemen and to place the existing Wiremen and Lincmen in the appropriate Grade I, II and III of the C.C.C. with effect from 12-7-67 after holding trade test. As per the arbitration award, the C.C.C. scale was given effect to from 12-7-67 after conducting one and the same trade test for all the grades through the Electrical Inspector, Government of Orissa. The first party claims to have fully implemented the award given by the learned Arbi-

4. The case of the second party No. 1, in short, is as follows:--

That the second party No. 1 raised a dispute since the first party did not agree to fit Grade I, Grade II, and Grade III Wiremen and Linemen in the corresponding grades of C.C.C. The dispute under Sec. 10-A of the Act was referred to Arbitrator Sri O. Venkatachalam, Chief Labour Commissioner (Central) on 25-5-1968 by agreement between the parties. The Arbitrator directed the first party to introduce Grade I (Rs. 150—180) of C.C.C. for Wiremen and Linemen and after giving trade test to the existing Wiremen and Linemen, to place them in the appropriate Grade I, II and III of the C.C.C. scale with effect from 12-7-67 i.e. the date of agreement between the first party and second party No. 1.

5. That the first party, instead of holding different trade tests for Grade I, Grade II and Grade III Wiremen and I inemen of the Port for the purpose of fitting them in Grade I and Grade II of the C.C.C. scale, held one test for all grades of Wiremen and Linemen and demoted certain Grade I Wiremen and Linemen to Grade III and gave acce-

lerated lift to some Grade III Wiremen and Linemen to Grade I jumping over the next higher grade and issued appointment orders accordingly. That the second party No. 1 raised a dispute and demanded that the first party should stop action on the basis of the defective and improper trade test.

- 6. That certain employees, who had got accelerated promotion, filed writ petition before the Hon'ble High Court, Orissa, but pending disposal of the writ petition, a settlement was arrived at between the first party and second party No. 2 in which it was agreed to pay higher scale to such of the workmen to whom appointment orders had been issued and who had joined and worked in the higher grade, on their furnishing an undertaking to the management that the increase of emoluments involved will be refunded if the interpretation given by the first party is adjudged to be wrong by the appropriate authorities. The Hon'ble High Court, while disposing of the writ petition, observed that the remedy available under Sec. 36-A of the Act should be allowed to work.
- 7. That before the dispute was referred to the Tribunal under Sec. 36-A of the Act, the Chief Labour Commissioner, who was the Arbitrator, had a joint discussion with the Port authorities and the Paradeep Port Workers Union and recorded the agreed interpretation in his letter dated 24/25th June, 1970 as follows:—
 - "I held discussion with you and your Secretary and with the President, Paradip Port Workers Union on the issues raised by the parties on 11th and 12th June, 1970 at Bhubaneswar. During the discussions, it was admitted by all concerned that the same trade test was given to all the three grades of wiremen/linemen and that no syllabus or content of the test was prescribed in advance for the purpose. It was also common ground that based on the results of the trade test, some workmen were demoted to lower grades while some others were given accelerated promotion jumping over the immediate higher grade. According to the established practice in regard to trade tests, the syllabus and the nature of test for each trade have to be prescribed in advance together with the qualifying service, if any, and different tests should be held for the different grades of workmen in order to consider their suitability for promotion to the next higher grade. Moreover, based on the results of the trade test, no workman should be demoted to a lower grade, but should continue to work in his existing grade. Keeplug in view these considerations, the Port authorities will have to take necessary action accordingly.

The specific points raised by you during the discussion held at Bhubaneswar are also clarified below for the infromation of all concerned:—

- "(i) A workmen 'A' in the existing Grade I (Rs. 125—155) or Grade II (Rs. 110—131) should be trade tested only to decide his suitability for placement in Gr. I (Rs. 150—180) or Grade II (Rs. 125—155) of C.C.C. as the case may be.
- (ii) The question of trade testing the workmen 'A' working in the existing Grade II to decide his suitability for placement in Grade I of C.C.C. ✓ Rs. 150—180) would not_arise
- (iii) If 'A' fails to pass the trade test as in item (i) above, he should continue in the existing Grade I or Grade II (corresponding Grade II or III of C. C. C.)
- (iv) According to the agreement dated 12-7-67, between the Paradip Port administration and the All India Port & Dock Workers Federation, if a Junior Wireman/Lineman possesses a licence, he should be placed in Gr. III of C. C. C. (Rs. 110-131); otherwise he will remain in the existing Grade I (Rs. 80-110) of Junior Wireman/Linemen (Semi-Skilled)."

According to second party No. 1, separate trade test should be held for each category of Wiremen and Linemen to be fitted in the corresponding grade and scale of C. C.

8. The case of Paradeep Shramik Congress (hereinafter referred to as the second party no. 2), in short, is as follows:—

That in accordance with the award given by the Chief Labour Commissioner (Central) and arbitrator which was published in the Gazette of India dated 8-2-1969, Sarbasri R. N. Panda, Lineman Gr. 1, Shri J. Apat, Wireman Gr. 1, B. K. Sahu, Wireman Gr. 1 and Daitari Mahapatra, Lineman Gr. 1 were placed in the appropriate grades of C.C.C. with effect from 12-7-67. After the above order was issued, Paradeep Workers Union, some members of which did not fare well in the trade test conducted by the Electrical Inspector, Orissa took the plea that the trade test was not conducted in the appropriate manner and the order of the first party should not be implemented. The Paradeep Port Shramik Congress, whose members could not get the revised pay, was forced to include the issue in its strike notice served on the first party on 14-9-70. A settlement was arrived at in a conclilation between the first party and second party no. 2 as a result, the concerned workmen got their pay in the revised grade.

- 9. That since the members of Shramik Congress were not given their pay in the revised grade, they had to file a writ in the Hon'ble High Court and the Hon'ble Court observed that the appropriate authority is to dispose of the reference as admissible under sec. 36-A of the Act. That the Chief Labour Commissioner had no scope to give the second interpretation and the second party no. 2 had no knowlege of the circumstances under which such an uncalled for interpretation could be given.
- 10. That there is no ambiguity in the award of the Chief Labour Commissioner for which the interpretation was sought. The first party has rightly held the trade test and placed the Wiremen and Linemen in the grade for which they were found fit.
- 11. Now, the only point that arises for consideration is as to in what manner the directions contained in paragraph 5 concering the Wiremen and Linemen in the arbitration award referred to above should be implemented. The learned Arbitrator, while discussing the facts and rival contentions come to the following conclusion and gave the directions accordingly.
 - "I, therefore, direct the Administration to introduce Grade I (Rs. 150-180) of C. C. C. for Wiremen and Linemen, and after giving trade test to the existing Wiremen and Linemen, to place them in the appropriate Grade I, II or III of C. C. C. w.e.f. 12th July, 1967, the date of their agreement with the Federation."

There is no dispute as to the date from which the arbitration award has to be given effect to. The difference is with regard to grade test. The first paty has implemented the aforesaid direction of Arbitrator by holding one and the same trade test for Gr. I and Gr. II Linemen and Wiremen of the central scale to place them in the appropriate Gr. I, II or III of the C. C. C. The second party no. 1 (Paradeep Port Workers Union) contends that the first party erroneously implemented the award by holding one and the same trade test for the existing Wiremen and Linemen. According to it, the proper and correct implementation should be to hold separate trade tests for each grade by prescribing separate syllabus. In support of its contention, the second party no. 1 urges that one and the same trade test conducted for the existing Wiremen and Linemen has adversely affected the senior Wiremen and Linemen inasmuch as it has resulted in supersession and demotion of senior Linemen and Wiremen. The second party no. 2 (Paradeep Port Shramik Congress) contends that there being no ambiguity in the arbitration award for implementation, there is no scope for any other implementation than the one done by the first party. One and the same trade test has been conducted for all the existing Wiremen and Linemen in the interest efficiency of the Port. On a careful assessment of rival contentions and scrutiny of para 5 of the arbitration award, I feel that the proper and harmoneous implementation of the directions

of the learned Arbitrator in Para 5 of his award should be to hold separate trade tests for each grade of Linemen and Wiremen by prescribing separate syllabus well in advance. This would work harmoneously and injustice would not be caused to the senior Wiremen and Linemen and that is the intention of the learned Arbitrator as is apparent from his direction that trade test of the existing Wiremen and Linemen should be held 'to place them in the appropriate Gr. I, II or III of the C. C. C.'. Had the learned Arbitrator intended otherwise, he must have said that one or the single trade test should be held for the existing Wiremen and Linemen to place them in the higher Grade of C. C. C. para 27 of the C. C. C. report, which has been taken into consideration by the learned Arbitrator, prescribes separate trade tests as per separate syllabus for each grade. Therefore, I hold that separate trade tests should be held for each grade of existing Wiremen and Linemen as per separate syllabus to place them in the appropriate Gr. I, II or III of the C.C.C. I may observe here that any Wiremen or Linemen, who becomes unsuccessful in the examination of his grade, should be allowed to continue in his existing grade and scale of pay until he passes the trade test and he should not be demoted.

12. In the result, the directions contained in para 5 of the arbitration award dated 9th December, 1968 concerning the Wiremen and Linemen be implemented in the manner as indicated above with effect from the date as oven in the arbitration award.

L. MALLICK, Presiding Officer [No. L. 38015/1/71/P&D/LRIII] G. C. SAKSENA, Under Secy.

नई विल्ली, 20 जुलाई, 1974

का० ग्रा० 1961—कर्मचारी पिविष्य निधि ग्रीर कुटुम्ब पेंशन निधि ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) जारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतव्ह्रारा सर्वेश्री शम्भू नाथ मोएला ग्रीर साधन कुमार चक्रवर्ती की पिच्चिमी अंगल के सम्पूर्ण राज्य ग्रीर ग्रंडमान ग्रीर निकाबार द्वीप समृशों के संघ राज्य क्षेत्र के लिए उक्त ग्रिधिनियम ग्रीर तदधीन बनायी स्क्रीम ग्रीर कुटुम्ब पेंगन स्क्रीम के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सरकार के नियत्रणाधीन या उसके स्वामित्व के किसी स्थापन के सबध में या रेलवे कपनी, यह पत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियत्रित उद्योग से सर्वाधिन किसी स्थापन के संबंध में, या एक से ग्रिधिक राज्यों में विभाग ग्रीर णाखाए रखने वाले किसी स्थापन के संबंध में, या एक से ग्रिधक राज्यों में विभाग ग्रीर णाखाए रखने वाले किसी स्थापन के संबंध में, निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं॰ ए-12016(5)/74-पी एफ ग्राई] राम प्रसाद मठला, ग्रवर संचिक

New Delhi, the 20th July, 1974

S.O. 1961.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Sarvashri Sambhu Nath Moitra and Sadhan Kumar Chakravorty to be Inspectors for the whole of the State of West Bengal and Union territory of the Andaman and Nicobar Islands for the purposes of the said Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in clation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having department or branches in more than one State.

[No. A-12016/5/74-PF. I]

R. P. NARULA, Under Secy.

पूर्ति ग्रौर पुनर्वाम मन्नालय (पुनर्वास विभाग)

नर्ष दिल्ली, 12 जुलाई, 1974

का॰ प्रां० 1962. — विरथापित व्यक्ति (दावा) अनुपूरक है प्रिधिनियम, 1954 (1954 वी 12) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रांतिनयों वा प्रयोग करों हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में सहायक बन्दोबस्त प्रधिकारी, श्री डी॰ सी॰ चौधरी को उक्त ग्राधितियम के द्वारा या इसके प्रन्तर्गत बन्दोबस्त ग्राधिकारी को सीपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए बन्दोबस्त ग्राधिकारी के रूप में नियक्त करती है।

[सख्या 15(4)/74-विशव सेल/एस०एस-4]

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 12th July, 1974.

S.O. 1962.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (No. 12 of 1954) the Central Government hereby appoints Shri D. C. Chaudhary, Assistant Settlement Officer in the Department of Rehabilitation as Settlement Officer for the purpose of performing the functions assigned to such officers by or under the said Act.

[No 15/4)/74-Spl. Cell/SS-IV]

नई दिल्ली 16 जुलाई, 1971

का॰ आ॰ 1962.— निष्कान्त सम्पत्ति प्रणासन ग्रिशिनियम, 1950 (1950 की 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त णिवतसी का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में कदोबसा प्रायुक्त, श्री गुलाब एल० ग्रजवानी को उकत श्रीश्चनियम के द्वारा या उसके श्रन्तर्गत उप महा-श्रीभरक्षक को सौपे गए कार्या को निपादित करने के लिए निष्कान्त सम्पत्ति उन महाश्चिभरक्षक के रूप में निषया करती है।

[स० 15/ :/७३-द्रिशेष सेल/एग० एस०-4]

New Delhi, the 16th July, 1974

S.O. 1963.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Gulab L. Ajwani, Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation, as Deputy Custodian General of Evacuee Property for the purpose of performing the functions assigned to such Deputy Custodian General by or under the said Act

[No 15/2/74-Spl. Cell/SS-IV.]

कारुकार 1964 — विस्थापित त्यपित (प्रतिकर एन पुनर्जाय) श्रिश्चित्यप, 1954 (1954 की 11) की धारा 3 की उपप्राप (i) हारा प्रदत्त मित्रियों का प्रयाग नारत हुए धन्याय रारकाः उसके हारा राष्ट्रीयस्य प्राप्तकत, श्री मुलाब एएर अवशामी को इसके हारा उक्त आर्थानयम के हारा या उसके भारतीत ऐसे आपुक्ता को सापे भए कारों यो निष्पादित करने के लिए उप मुख्य बन्दोबस्य पायुक्त के रूप थे क्षिक्त करनी है।

[सक्या 15/3/74-विशेष सेल/एस० एस०- ।]

S.O. 1964,—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation), Act, 1954, (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Gulab L. Ajwani, Settle-

ment Commissioner, as Deputy Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Commissioners by or under the said Act.

[No. 15/3/74-Spl. Cell/SS-IV.]

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1974

का श्या । 1965.— निष्कान्त सम्पत्ति प्रणासन प्रधिनियस, 1950 (1950 की 31) की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पूर्ति और पुनर्वास संवालय (पुनर्वास विभाग) की श्रिधसूचना संख्या 15-2-74-विभोष सेल/एस० एन०-4 (ii) दिनांक 29 मार्च, 1974 का प्रतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में बन्वोबस्त धायुक्त, श्री एस० पी० सूद को इसके द्वारा उक्त श्रिधिनयम के द्वारा या उसके घन्तर्गत निष्कान्त सम्पत्ति प्रभिरक्षक को सौषे गए कार्यों को निष्पादित करते के लिए घाध्र प्रदेश तथा सहाराष्ट्र राज्या के लिए घात्रितन ग्रिभिन्यक, निष्कान सम्पत्ति, व का से निष्का करती है।

[सख्या 15/2/74-विषेष सेल/एप० एग०-1]

New Delhi, the 17th July, 1974.

S.O. 1965.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 6 of the Administration of Evacuec Pronecty Act. 1950 (31 of 1950) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Supply & Rehabilitation. (Department of Rehabilitation) No. 15/2/74-Spl. Cell St. IV (ii) dated the 29th March, 1974, the Central Government hereby appoints Shri S. P. Sud, Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as the Additional Custodian of Evacuec Property for the States of Andhra Pradesh and Maharashtra for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian of Evacuec Property by or under the said Act.

[No. 15/2/74-Spl. Cell/SS-IV.]

का॰ आ॰ 1966.— निष्मान सम्पत्ति प्रशासन अधिनियस, 1950 (1950 की 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदेत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पूर्ति और पुनर्वास मंद्रालय (एउर्वास विभाग) की अधिस्वात सख्या 15/2/74-विभेष सेल/एस० एस०-1 (i) दिनाक 29 सार्च, 1974 का अनिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार पुनर्वार विभाग से बन्धोनस्य अध्यक्षित की एस० पी० सूद को इसके द्वारा उकत अधिनियस के हारा या उसके अन्तर्यत अस्थित को सार्वे पए कार्यों को निष्पादित करने के लिए गुजरात, आन्य प्रदेश, महाराष्ट्र, प्रजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों के अधाया सवणासित केन्न तथा अन्य राज्यों से निष्यात सम्पति के अधिर्थक के सामें निष्यात करती है।

[मस्था 15/2/74-विशेष सेल/एम० एम०4]

दीनानाथ श्रमीजा, ग्रवर समिव

S.O. 1966.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Supply & Rehabilitation (Department of Rehabilitation) No. 15/2/74-Spl. Cell-SSIV (i) dated the 29th March, 1974 the Central Government hereby appoints Shri S. P. Sud, Settlement Commissioner in the Department of Rehabilitation as the Custodian of Evacuee Property for the Union Tertonies and States other than Gujarat, Andbra Pradesh, Maharashtia, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under the said Act.

[No. 15/2/74-Spl. Cell/SS-IV]

D. N. ASIJA, Under Secy.